हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, 04 मार्च, 2020 को माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

04.03.2020/1100/केएस/एएस/1

अध्यक्षः इससे पहले कि मैं प्रश्नकाल शुरू करुं, आज प्रातः नियम 67 के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी द्वारा कोरोना वायरस के ऊपर आवेदन प्राप्त हुआ था परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस, जिसके कारण पूरा विश्व भयभीत है, माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से भी मुझे इस बारे में सूचना मिली कि मैं वस्तुस्थिति से, हिमाचल प्रदेश में इस वायरस की क्या स्थिति है, उससे इस माननीय सदन को और इस माननीय सदन के माध्यम से प्रदेश को अवगत करवाना चाहता हूं तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस पर स्थिति स्पष्ट करें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकता। रूल के मुताबिक हमने 67 दिया है। आप असैम्बली के रूल्ज़ पूरी तरह से ब्रेक करके अपने डिसिज़न दे रहे हैं। हमारी तरफ से आपके ऑफिस को 67 दिया गया, आपने मुख्य मंत्री को इन्फोर्म किया, मुख्य मंत्री महोदय अब उस पर बोलेंगे, ऐसा नहीं होता।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप मेरी बात तो सुन लें। यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। मुख्य मंत्री जी आपको और पूरे प्रदेश को अद्यतन स्थिति से अवगत करवाना चाहते हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर आपने असैम्बली ऐसे ही चलानी है तो हम बाहर चले जाते हैं।

अध्यक्षः आपने बाहर क्यों जाना है, आप क्यों जाएंगे?

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारा 67 का नोटिस आया और आप उस पर मुख्य मंत्री की स्टेटमैंट दिलवा रहे हैं। आप भी इतने साल से मंत्री रहे हैं। मुख्य मंत्री की स्टेटमैंट 12:00 बजे आती है। हमने नोटिस दिया है, पहले आप हमारे नोटिस पर फैसला करें।

अध्यक्षः नोटिस के ऊपर मैंने यही फैसला किया है, क्योंकि कोरोना वायरस पर यहां कोई चर्चा का विषय है ही नहीं।

04.03.2020/1100/केएस/एएस/2

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस पर अन्तर्राष्टीय स्तर पर चर्चा हो रही है।

अध्यक्षः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है इसीलिए उसका हिमाचल प्रदेश में क्या असर है, उसके ऊपर स्टेटमैंट माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे। इसमें स्कोर सैटल करने की तो बात ही नहीं है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह असैम्बली सरकार चलाने के लिए नहीं है और अगर ऐसे चलना है तो फिर हमारा यहां आने का कोई अधिकार ही नहीं है।

अध्यक्षः मुकेश जी, आपका पूरा अधिकार है, आपके नोटिस को हमने स्वीकार किया है परन्तु उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी हिमाचल प्रदेश में अद्यतन स्थिति क्या है, ...(व्यवधान) इस पर मुकेश जी, चर्चा की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसमें स्कोर सैटल करने वाली कोई बात ही नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रदेश में क्या तैयारियां हैं, मुख्य मंत्री जी उससे अवगत करवाने वाले हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आज तक हिमाचल प्रदेश के किसी स्पीकर ने नहीं किया होगा कि 67 पर मुख्य मंत्री को बुलाया जा रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष श्रीमती अ0व0 की बारी में--

04.03.2020/1105/av-as/1

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, हम नियम-67 के अंतर्गत आज अपना विषय रखेंगे। इस विषय पर या तो आप बोलें क्योंकि आप भी प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे हैं या फिर इस संदर्भ में मुख्य मंत्री जी बोलें। कोरोना वायरस से लोग

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित हो रहे हैं। ...(व्यवधान) हिमाचल प्रदेश क्या पूरी दुनिया से अलग है? पिछले कल बिलासपुर से एक मरीज यहां आई0जी0एम0सी0 आया है।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप बैठ जाइए। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि बीच में न बोलें और बैठ जाएं। आप लोग मेरी बात सुनें और इसमें कोई स्कोर सैटल करने वाली बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार इस विषय में संवेदनशील है और इस बारे में सरकार ने उत्तर देना है। इसलिए आपके नोटिस से पहले मुख्य मंत्री कार्यालय से मुझे सूचना मिली कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें वक्तव्य देना चाहते हैं। इसमें राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछले कल बिलासपुर से आई0जी0एम0सी0 में एक मरीज आया था जो कि यहां पर दो घंटे तक तो गाड़ी में बैठा रहा। वहां पर उसको गाड़ी से उतारने के लिए कोई तैयार नहीं था। वहां पर किसी ने कहा कि इसको गाड़ी से नीचे मत उतारो और किसी ने कहा कि इसको पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ भेज दो क्योंकि यहां पर इस वायरस से लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया आप बैठ जाइए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर स्टेटमैंट देना चाहते हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : इस वायरस के कारण अमेरिका में 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और हिन्दुस्तान में इस वायरस से 10 लोग प्रभावित पाए गए हैं। ...(व्यवधान) हमारे यहां पर फार्मास्युटिकल का पूरा कारोबार चीन से रिलेटिड है तथा सारे सॉल्ट चीन से आ रहे हैं। हिन्दुस्तान के बहुत सारे बच्चे चीन में पढ़ रहे हैं। ...(व्यवधान)

04.03.2020/1105/av-as/2

शिक्षा मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, यह हिन्दुस्तान की ही सरकार है जो चीन से अपने सारे बच्चों को वापिस अपने देश लाई है। ...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : आपके पास यहां पर कोई तैयारी नहीं है। आपके पास यहां पर मास्क और दस्तानें उपलब्ध नहीं है। ...(व्यवधान) आपके पास क्या तैयारी है? ...(व्यवधान) ऐसा नहीं होगा, हम अपनी बात रखेंगे। ...(व्यवधान)

(बीच में पक्ष और विपक्ष; दोनों तरफ से माननीय सदस्य नारेबाजी करते रहें।)

अध्यक्ष : मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाएं। ...(व्यवधान) धक्काशाही की तो कोई बात ही नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस मान्य सदन को हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति से अवगत करवाना चाहते हैं तो आप सुन लें। ...(व्यवधान) मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं। यहां पर कुछ माननीय सदस्य जो नारे लगा रहे हैं यह मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। ...(व्यवधान) इस प्रकार के विषय को आप मुद्दा बना रहे हैं, यह ठीक नहीं है। यह विधान सभा की परम्पराएं नहीं हैं इसलिए कृपया करके आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं। ठीक है, आपकी चिंता सही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आप भी किसी-न-किसी विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं आपकी चिंता समझता हूं और इस विषय की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर अपनी स्टेटमैंट देना चाहते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ...(व्यवधान) बिल्कुल हो सकता है। मुझे आपके नियम-67 से पहले मुख्य मंत्री कार्यालय से इस बारे में सूचना प्राप्त हुई है। इसलिए विषय की गंभीरता को देखते हुए मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से स्टेटमैंट देने का आग्रह किया है।

टी सी द्वारा जारी

04.03.2020/1110/TCV/DC-1

अध्यक्ष ....जारी

श्री मुकेश अग्निहोत्री : आप विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। विपक्ष अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ... (व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं और हम प्रश्नकाल को आगे खींच रहे हैं। ... (व्यवधान) दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के प्रश्न लगे हुए हैं। ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, यही व़क्तव्य तो यहां से आएगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप कोरोना वॉयरस के ऊपर व़क्तव्य दें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए।... (व्यवधान)

(बीच में पक्ष और विपक्ष; दोनों तरफ से माननीय सदस्य नारेबाजी करते रहें।)

अध्यक्षः मेरी व्यवस्था सुन लें कि इस चेयर से मैं जिसका नाम बोलने के लिए लूंगा उसी को कार्यवाही में रिकॉर्ड किया जाये। ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बैठें। आप जो बोल रहे हैं, बिना चेयर की अनुमति से बोल रहे हैं। ... (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) मेरा आप से निवेदन है कि आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। आप बैठें तो सही ... (व्यवधान) मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठ जाएं, प्लीज़ बैठ जाइये। ... (व्यवधान)

04.03.2020/1110/TCV/DC-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस बहुत संवेदनशील और गम्भीर विषय पर विपक्ष के माननीय नेता ने नियम-67 के अंतर्गत नोटिस दिया है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी, कृपया बैठिये । इतने महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी स्टेटमैंट देना चाहते हैं और उसको सुनने के लिए हम तैयार नहीं है। ... (व्यवधान) कृपया करके आप बैठ जाइये। मुख्य मंत्री जी आप स्टेटमैंट दीजिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि माननीय विपक्ष के नेता ने नियम-67 के अंतर्गत जो मामला यहां उठाया, वह सचमुच संवेदनशील, गंभीर है और इस सारे विषय को लेकर हमें इस माननीय सदन के माध्यम से सारे प्रदेश की जनता को अवगत करवाना बहुत आवश्यक है। ... (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के सदस्य नारेबाज़ी करते हुए सदन से बर्हिगमन कर गये।)

एन0एस0 द्वारा .... जारी ।

04-03-2020/1115/NS/DC/1

माननीय मुख्य मंत्री .....जारी

अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ अरसे से इस माननीय सदन की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने का काम आज से पहले हमने कभी नहीं देखा है और आज हम इसको देख रहे हैं। यह इतना संवेदनशील और गम्भीर विषय है। मैं इस बात से सहमत हू कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। इस नोटिस के माध्यम से मंशा यही है कि हम उस सारे विषय को ले करके इसकी गम्भीरता को समझें और इसके साथ-साथ में प्रदेश की जनता को भी अवगत करवाएं कि हमें किस प्रकार से आने वाले समय में इस स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। हर बात को ले करके राजनीति करना गलत है और ये लोग कोरोना में भी राजनीति कर रहे हैं। यह सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी बात उठाई और कही, मुझे लगता है कि इतना ही पर्याप्त है। जिस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं कि इतने मरीज़ आ गए और झूठ बोलना इनकी आदत बन गई है। कोरोना वायरस के मरीज़ पर अभी संशय है और अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि वास्तव में यह कोरोना का मरीज़ है भी कि नहीं। श्रीमान जी, निष्कर्ष पर पहुंच गए कि कोरोना वायरस आ गया। आपके पास दस्ताने और दवाई नहीं हैं, आपके पास अस्पताल नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आखिरकार ये

कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे कि यही इलाज़ करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे इन्होंने ही देखा कि इस आदमी को कोरोना वायरस हो गया है। अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत संवेदनशील है और इसमें हमें बहुत गम्भीरता से चलने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण पूरे देश भर में दहशत का माहौल है बल्कि देश नहीं पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। ऐसी परिस्थिति में हमें इसकी गम्भीरता को समझना है, गम्भीरता के साथ-साथ हमें इसकी संवेदनशीलता को भी समझना है। हम ऐसी परिस्थिति अपने आप पैदा नहीं करते हैं। कोरोना वायरस है या नहीं, जब इन्वैस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आएंगी तब स्पष्ट होना है लेकिन श्रीमान जी, कह रहे हैं कि कोरोना वायरस आ गया। इनका वश चले तो ये सैंकड़ों लोगों को मार भी दें। मैं देख रहा था कि पिछले तीन-चार दिनों से जिस तरह ये आंकड़ों की बात कह रहे हैं और ये कहां से आंकड़ें लाते हैं? इस माननीय सदन के अंदर झूठ बोलना, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाना यह मुझे लगता है कि सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हमारी जिम्मेवारी है कि वस्तुस्थिति क्या है? भले ही यह प्रश्नकाल है लेकिन प्रश्नकाल से महत्वपूर्ण यह विषय है कि हम प्रदेश की जनता को इस माननीय सदन के माध्यम से तुरंत जानकारी दें कि वस्तुस्थिति क्या है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस दहशत के माहौल में स्कूल बंद करने की बात कह दें। जब वायरस नहीं है

04-03-2020/1115/NS/DC/2

तो हम स्कूल बंद कर दें। भगवान न करे कि ऐसी परिस्थिति आए। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जहां विपक्ष का हमें ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सहयोग मिलना चाहिए वहां ये लोग उस स्थिति को खराब करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। राजनीतिक मकसद से लोगों में संशय नहीं फैलाना चाहिए। इससे किस राजनीतिक दल का भला होने वाला है? राजनीति में स्तर इस कद्र गिर जाएगा और राजनीति में विपक्ष की स्थिति ऐसी बन जाएगी, मैंने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। अध्यक्ष महोदय, सच में ही मुझे इस बात की बहुत पीढ़ा है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से यह बीमारी चीन में फैलने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। मृत्यु की वज़ह से पूरी दुनिया में ख़बर फैली और एक ऐसा माहौल बन गया जिसके कारण सभी देशों ने एतिहात के तौर पर जो किया जा सकता था करना शुरू कर दिया लेकिन

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

मुख्य मंत्री.... जारी

लेकिन उसके बावजूद भी हम इस तरह से दहशत फलाएंगे, जो बातें सच नहीं है, जो तथ्य नहीं हैं, हकीकत नहीं हैं उन बातों को फैलाने की कोशिश करेंगे तो इसके कारण समाज में बहुत खराब स्थिति पैदा होगी। इसलिए इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसकी वस्तुस्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूंः-

भारत सरकार से ई-मेल अलर्ट प्राप्त होने के तुरंत बाद सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिनांक 23 व 25 जनवरी, 2020 को नोवेल कोरोना वायरस, 2019 के संबंध में निवारक और नियंत्रण उपाय जारी किए गए थे। इस बीमारी को अब Covid-19 के नाम से जाना जाता है। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। जांच के लिए ओरोफ्रेंजियल, जो गले से टैस्ट लिया जाता है, खून के नमूने निम्नलिखित मामलों में ही एकत्रित किए जाते हैंः-

1. किसी ने 15 जनवरी, 2020 के बाद या पिछले 15 दिनों के भीतर चीन के भूआन शहर का दौरा किया है। भूआन शहर वह शहर है जहां सबसे पहले यह बीमारी फैली थी। इस शहर में इस वायरस का बहुत बड़ा प्रभाव है जिसके कारण वहां पर बड़ी तादाद में मौतें भी हुई हैं।

2. जिन 12 देशों में इस बीमारी का जोखिम पाया गया है, उनके नाम चीन, जापान, हाँगकाँग, सिंगापुर, थाइलैंड, साउथ कोरिया, मलेशिया वियतनाम, इंडोनेशिया, इटली, ईरान एवं नेपाल है। इस वायरस का प्रभाव इन देशों में भी देखा गया है, वहां पर पोजिटिव केसिज पाए गए हैं। 10 फरवरी, 2020 के बाद बुखार या खांसी करने में तकलीफ होने के मामलों पर संशय किया जा सकता है।

3. कोरोना वायरस रोग के पुष्ट मामलों के सम्पर्क में आया हो। हिमाचल प्रदेश में Covid-19 के बचाव के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई हैः -

04.03.2020/1120/RKS/HK-2

सभी संबंधित लोगों के लाभ के लिए विभागीय वैबसाइट पर निवारक उपयोगों के बारे में जानकारियां अपलोड की गई हैं जो निम्न बिंदुओं पर केंद्रित हैंः-

1. कम-से-कम 20 सैकिंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोएं।

2. यदि साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें।

3. बिना धुले हाथों से आंखों, नाक, मुंह को छूने से बचे।

4. जो लोग बीमार हैं उनके निकट संपर्क से बचें।

5. खांसी और छीक करते समय शिष्टाचार का पालन करें।

6. बीमारी होने पर घर पर ही रहें।

7. अक्सर उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को साफ और कीटाणु रहित करें।

जेलों और राज्य में स्थिति पर नजर रखने के लिए राज्य और नोडल अधिकारियों की पहचान की गई है। स्टेट सर्विलैंस ऑफिसर (SSO) और डिस्ट्रिक्ट सर्विलैंस ऑफिसर(DSO) के सम्पर्क नम्बर को भारत सरकार के साथ-साथ कॉल सैंटर 1041100 के साथ सांझा किया गया है। यह हैल्प लाइन 24x7 कार्य कर रही है। मुख्य मंत्री सेवा संकल्प-1100 पर जानकारी उपलब्ध है। राज्य और जिला रैपिड प्रतिक्रिया टीमों को फिर से अधिसूचित किया गया है।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

मुख्य मंत्री जारी....

आई.जी.एम.सी. शिमला और डॉ0 आर.पी.जी. मैडिकल कॉलेज टांडा में आईसोलेटिड वार्डों की पहचान की गई है। माईक्रो बायोलॉजी विभागों में नमूना संग्रह सुविधा के साथ दोनों मैडिकल कॉलेजों में चिकित्सा प्रभारी तैनात किए गए हैं। दोनों संस्थानों में वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक संबंधित संस्थानों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। सभी जिला स्तर के अस्पतालों में पृथक वार्डों की पहचान की गई। सभी जिला अस्पतालों और मैडिकल कॉलेजों में व्यक्तिगत संरक्षित उपकरण और एन-95 मास्क उपलब्ध हैं। जिसका जिक्र विपक्ष के माननीय सदस्य कर रहे हैं कि मास्क नहीं हैं। अगर इन्हें मास्क चाहिए तो आज ही उपलब्ध करवा देते हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य

देख-भाल प्रदाताओं को सार्वभौमिक सार्वजनिक यूनिवर्सल प्रीकॉशन और कफ शिष्टाचार के लिए संवेशनशील बनाया गया है। राज्य भर के होटल व्यवसाइयों से डिप्टी कमीशनरों के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि वे पर्यटकों की पहचान कर स्वयं घोषित करें कि उनके किसी मेहमान ने 15 दिन के दौरान 12 जोखिम देशों की यात्रा तो नहीं की है। यानी कि कोई पर्यटक आता है तो उसे बताना पड़ेगा कि उन्होंने कहीं जोखिम देशों का दौरा तो नहीं किया है। जागरूकता पैदा करने और निवारक उपाय के लिए समाचार पत्रों, एफ.एम. रेडियों स्टेशनों, जिंगल्स, समाचार चैनल्स, डी.डी. शिमला के माध्यम से संदेश भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जिला परिषद, ब्लॉक समितियों और ग्राम सभाओं में बचाव के तरीकों का संदेश दे रही हैं। कोविड-19 यानी कोरोना बायरस मामलों की परिवहन की आवश्यकता के मामले में व्यक्ति सुरक्षा उपकरण पी.पी. किट और मास्क के साथ तीन एंबुलैंस शिमला मण्डी और धर्मशाला में तैनात की गई है। सभी जिलों द्वारा नियमित दैनिक रिपोर्टिंग की जा रही है और फिर अंतिम रूप से संकलित राज्य रिर्पोट भारत सरकार और मीडिया के साथ नियमित रूप से दैनिक आधार पर सांझा की जाती है। कुल 30 विदेशी लोग जिनमें से 26 चीनी एवं 4 थाई

थे। सोलन से 7 और शिमला से 10 ने स्वयं घोषणा की है कि उन्होंने बुहान की यात्रा नहीं की थी। ये सभी लोग रोग मुक्त हैं और बुखार खांसी तथा सरवश्न संकट की निगरानी की जा रही है।

04.03.2020/1125/बी.एस./एच.के./-2

भारत सरकार की ओर से हिमाचल से संबंधित 145 निवासियों की सूची 03 फरवरी, 2020 को प्राप्त हुई। जिला स्वस्थ्य अधिकारियों ने इन सभी को निगरानी में रखा है इसके बाद 67 देशी- विदेशी लोगों ने आत्म रिपोर्टिंग की है। इसके अलावा 12 लोग जो बुहान से आए और भारत सरकार द्वारा क्रमशः 18 और 22 फरवरी को सूचित किया गया। इन सभी 214 लोगों को 28 दिनों के लिए गृह निगरानी के तहत रखा गया है जिसमें से 181 ने 28 दिनों की अनिवार्य पृथक अवधि पूरी कर ली है और शेष 15 अभी गृह निगरानी के अधीन हैं और 18 लोग राज्य छोड़ कर अन्य स्थानों पर जा चुके हैं। अभी तक केवल सीमित जानकारी ही उपलब्ध है जो कोविड-19 से जुड़ी बीमारी के लक्षणों को पहचानती है। कोई टीका या विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। लक्षणों से राहत के लिए केवल देखभाल उपलब्ध है। भारत सरकार और जिलों के लगातार व्हाट्स ऐप और ई-मेल के माध्यम से सूचना आदान-प्रदान की जा रही है। अब तक 7 बार 21, 27 जनवरी और 04,07,10 और 24 फरवरी, 2020 भारत सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की गई। मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ने भी 30 जनवरी को भारत सरकार के कैबिनेट, सचिव के साथ वीडियो कॉन्फैंस की थी।

श्री डी.टी.द्वारा जारी...

04/03/2020/1130/डी0टी/वाई0के0-1

मुख्य मन्त्री ..जारी

मैं महत्वपूर्ण जानकारी अभी दे रहा हूं। पिछले कल 3-3-2020 को तीन लोग जिन्होंने पिछले 14 दिनों के अन्तराल में उन देशों की यात्रा की थी जो खांसी सी एवं बुखार होने के

कारण आई0जी0एम0सी0 शिमला एवं डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टाण्डा में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किये गयें हैं ताकि इन लोगों की उचित जांच व उपचार किया जा सके। इन तीनों में से दो कांगड़ा जिले के थे और यह दोनों इटली की यात्रा पर गये थे तथा एक व्यक्ति बिलासपुर ज़िले का रहने वाला है जिसने साउथ कोरिया की यात्रा की थी। इन तीनों की जांच के लिए नमुने ले लिये गये हैं तथा परिक्षण के लिए दिल्ली स्थित लैब में भेजा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी अभी तक की है जो मुझे सांझी करनी थी। मेरा विपक्ष के मित्रों सह यही निवेदन है कि ऐसी सनसनी पैदा न करें जिससे समाज में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो जाये। यह एक बिमारी है और बिमारी गम्भीर है। लिकन यह भी हमको मान कर चलना चाहिए कि इस बिमारी का भी इलाज़ है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो जानकारी हमको मिली है, जिसमें केरल में कोरना वायरस के तीन पॉजिटिव केसिज़ पाए गये थे, उन तीनों का उपचार होने के बाद वह हास्पीटल से डिसचार्ज हो कर अपने घर चले गये है। वह जीवित हैं और स्वस्थ हैं। एतिहात की दृष्टि से जो परहेज करने की आवश्यकता है वह अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी तक की परिस्थिति तो ऐसी है कि हमारे पास तीन ऐसे मामले आये हैं जिनकी अभी जांच होनी है और जांच होने के बाद उनकी रिपोर्ट आयेगी, रिपोर्ट आने के बाद तभी तय हो पायेगा कि यह कोरना वायरस पॉजिटिव है भी की नहीं। लेकिन इस प्रकार से कहना कि कोरना वायरस आ गया, जैसे की यही लोग सुपर-स्पैशलीस्ट बन चुके है और यही तय करेंगे की कोरना वायरस आ गया, यह एक पॉजिटिव केस है। यह लोग ज़िन्दा नहीं रहेंगे, मर जायेंगे और पुरा हिमाचल या पुरी दुनिया ख़त्म हो जायेगी। ऐसा माहौल पैदा करना कतई भी उचित नहीं है। कोरना वायरस के जो सैम्पल जांच के लिए भेजे गये हैं, हम एक्सपेडाइट कर रहें हैं, जल्दी से जल्दी उनकी रिपोर्ट आ जाये और रिपोर्ट आने के बाद जो भी उसमें आवश्यक होगा उसको किया जायेगा। दुसरी बात यह है

कि चाहे यह मरीज आई0जी0एम0सी0 में हो चाहे डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टाण्डा में हों,इन्हें आइसोलेसन वार्ड में रखा गया है। हमारे पास आई0जी0एम0सी0 और डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टाण्डा में पूरी तैयारी है। जहां तक इन्होंने मास्क की बात कि तो मैं कहना चाहूंगा की हमारे पास मास्क उपलब्ध हैं, इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है । इसके लिए समाज के सामने गलत स्थिति रखना बिल्कुल गलत है। आज ही सत्र के मध्य में हम एक बैठक इस सिलसिले में करने वाले हैं। मैंने मुख्य सचिव को भी बोला है, अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य को भी बोला है व स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों को भी बोला है, ताकि इस वायरस के खिलाफ और बेहतर ढंग से तैयारी हमारे पास रहे इसमें चाहे ट्रांसपोटेशन की बात हो चाहे आइसोलेशन वार्ड की बात हो। अगर यह पाया जाता है कि वह कोरना वायरस से संक्रमित हैं उस स्थिति में हम पूरी तरह से तैयार हैं।

ऐसे में हमने यह भी तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में मोटेतौर पर तीन हास्पीटल हम डिसाइड कर रहें हैं, अभी उस पर निर्णय करना है, वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति न आये और मुझे भी पूरा विश्वास है कि ऐसी स्थिति नहीं ओयगी। क्योंकि हम विचार कर रहें है कि हम तीन चिकित्सालयों को खाली कर वहां पर वहां पर आइसोलेशन वार्ड बनायेंगे और वहां पर उनका उपचार किया जायेगा। इसलिए यह करोना वायरस के सिलसिलें में अभी तक किसी भी संस्थान को बन्द करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्कूल या अन्य संस्थान जहां लोगों का आना -जाना होता है उसे बन्द करने की जरूरत इसलिए अनुभव नहीं हो रही क्योंकि अभी तक एक भी पुष्ठि कोरना वायरस के समबन्ध में नहीं हुई है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष से यही कहना चाहता हूं की विपक्ष इसमें सरकार का सहयोग दे और गलत जानकारियों लोगों के बीच में न फैलाऐं । मैं आज देख रहा था कुछ समाचार पत्रों में बहुत बड़ी ख़बर छपि है कि करोना वायरस हमारे हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी प्रवेश कर गया, मेरा मीडिया जगत से भी निवेदन है कि जब तक पुष्ठि नहीं हो जाती ऐसी ख़बर नही आनी चाहिए, हां अगर पुष्ठि होगी तो हम सबसे पहले आपके साथ भी सांझा करेंगे। हम आप सब का भी सहयोग चाहेंगे। इस प्रकार से माहौल खराब न हो क्योंकि आज के अख़बारों में और सोशल मीडिया

एन0जी0द्वारा जारी…….

04-03-2020/1135/वाई.के.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री जारी...

के माध्यम से बहुत लोगों ने हैडलाइन देखी है उसके बाद बहुत जगह से हमें फोन आ रहे हैं और इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। जानकारी देना हमारी जिम्मेवारी है लेकिन दहशत के मारे ऐसी परिस्थिति निर्मित न हो जिसके कारण आदमी परेशान हो जाए और मेरा मीडिया के लोगों से भी और विपक्ष के नेताओं से भी निवेदन है कि ऐसी स्थिति पैदा न हो। यह परिस्थिति किसी एक आदमी द्वारा या सरकार द्वारा निर्मित नहीं है। यह एक ऐसी परिस्थिति बनी है जिसके लिए हम सब को एहतियात बरतने और इसकी गम्भीरता को समझने की आवश्यकता है। इसके लिए जो तैयारी हमें करनी है उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं वह सोचने का विषय है। इस विषय को राजनीतिक दृष्टि से उठाने की आवश्यकता नहीं है।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य माननीय सदन में वापिस आए।)

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का भी बहुत खेद है कि ऐसे संवेदनशील विषय पर सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से सदन से बाहर चले जाना, मुझे लगता है कि उचित बात नहीं है।

04-03-2020/1135/वाई.के.-एन.जी./2

अध्यक्षः प्रश्न काल आरम्भ।

प्रश्न संख्या - 2506

श्रीमती आशा कुमारी (डलहौजी)ः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें बताया गया है कि कुल 15 mining leases में से 14 को EIA clearance मिली है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि ये 15 mining leases कौन सी हैं? यह सूचना चाहे आप मुझे अभी दे दें या बाद में भी उपलब्ध करवा सकते हैं। इन सभी ने कितनी clearance ले रखी हैं? जैसे EIA, Pollution या अन्य कोई भी।...(व्यवधान) अध्यक्ष

महोदय, मेरे आप-पास के माइक चल रहे हैं लेकिन मेरा माइक नहीं चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, कृपया आप अपने सिस्टम को ठीक करवाएं। (श्रीमती आशा कुमारी जी का माइक ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है।)...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्या जी कृपया आप अन्य माइक उपयोग कर लीजिए।

Smt. Asha Kumari : I can't do that. It is against the Rules. ...(Interruption) मैं माइक के बिना ही बोल लेती हूं। माननीय मंत्री जी से मैं जाना चाहूंगी कि उत्तर में जो 14 mining leases हैं जिन्होंने EIA clearance ले रखी है, इसके अलावा भी जो clearances होती हैं क्या वे clearances इन्होंने ले रखी हैं और क्या ये 14 mines लीगली चल रही हैं? वह कौन-सी एक माइनिंग लीज़ है जिसने EIA clearance नहीं ली है और क्या वह functional है या नहीं?

आपने demarcation के बारे में कहा कि जब लीज़ ग्रांट होती है तब demarcation होती है। आज सदन में माननीय श्री राकेश पठानिया जी नहीं है, उन्होंने और मैंने बारमबार रिक्वेस्ट की है कि जो भी mining leases आपने दी हुई हैं चाहे वे private land पर या Government land पर हैं क्या आप उन्हें demarcate करके boundary with flags लगाने का प्रावधान करेंगे?आपने मशीनरी के बारे में कहा है कि any type of excavator, does it include JCBs and Poclain in the hill side or river side?

माननीय उद्योग मंत्री जी श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

04/03/2020/1140/MS/AG/1
प्रश्न संख्याः 2506 क्रमागत---

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है, उसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि 15 खनन पट्टे स्वीकृत हैं जिनमें से 14 खनन पट्टों की जो भी स्वीकृति चाहिए, वह आई है <u>लेकिन आपने कहा है कि डिटेल में मुझे सारी सूचना दे दें तो मैं उसकी डिटेल आपको दे दूंगा।</u> मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जितनी भी माइनिंग लीजिज हैं alongwith name और बाकी सारी चीजें सूचना में हैं और इसमें किस-किस की क्या-क्या क्लेरिटी है, वह भी इसमें है। आपने पूछा है कि वह कौन सी माइनिंग लीज है जिसकी अनुमति

नहीं है। उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि श्री अमर चन्द शर्मा, सपुत्र लक्ष्मीधर शर्मा का एन0एच0पी0सी0 के पास काम था। एन0एच0पी0सी0 के पास तो वह एन0ओ0सी0 थी लेकिन बाद में वन विभाग ने कहा कि पर्टिकुलरली जिसने लीज ली है उसके पास एन0ओ0सी0 होनी चाहिए। इसलिए इसकी रि-डाइवर्शन का केस गया हुआ है बाकी सारा क्लीयर है। उसके बाद जो आपने अगली बात बोली है कि यह जो पिल्लर्स का विषय रहता है, यह बात आपने पिछली बार भी बताई थी और मैंने विभाग को निर्देश भी दिए थे। फिर भी आपको यदि ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा विषय नहीं आया है तो आप पर्टिकुलरली बताएं। हम विभाग के ख़िलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तीसरा प्रश्न आपने जे0सी0बी0 के बारे में किया है। उसमें जो हिल स्कोप्स हैं वहां माइनिंग लीज हो सकती है लेकिन जे0सी0बी0 पंजे वाली नहीं लग सकती है। उसमें जो प्रोविजन किया गया है i.e. tyre mounted front and loaded upto 80 horsepower, उसमें पंजा नहीं होता है दूसरा पोर्शन होता है। लेकिन वह वहीं प्रयोग किया जाता है जहां हिल स्कोप हो। हिल स्कोप पर भी प्रयोग करने के लिए उसको डायरैक्टर इण्डस्ट्रीज से परमिशन लेनी पड़ती है। आपके केसिज के अंदर किसी ने इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली है।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जब किसी ने अनुमति ली ही नहीं है तो जो लोग इस मशीनरी को यूज कर रहे हैं उनके ख़िलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? दूसरा, मैं इनसे यह भी जानना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश के कितने विभाग माइनिंग ऑफिसर और एस0डी0एम0 के अलावा अधिकृत हैं to take action against illegal mining.

04/03/2020/1140/MS/AG/2

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने गलत काम किया है उसमें कुल 417 मामले टोटल हैं और इसमें जे0सी0बी0 वाले मामले भी हैं यानी जिन लोगों ने बिना परमिशन के जे0सी0बी0 लगाई है। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि 202 मामलों में कम्पाउंड करके 11,54,500/-रुपये की वसूली की गई है और 14 मामले न्यायालय में हैं। इनका निपटारा करने के लिए जो राशि उन्होंने बोली है वह 3,14,600/-रुपये है। दूसरा, आपने पूछा है कि कौन-कौन से विभाग अधिकृत हैं तो इसमें जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, पुलिस

विभाग, वन विभाग, आर0टी0ओ0 और राजस्व आदि सभी विभाग कार्रवाई के लिए अधिकृत हैं। हमारा विभाग तो कर ही सकता है।

श्रीमती आशा कुमारीः आपने कहा कि इतने सारे विभाग अधिकृत हैं। माइनिंग ऑफिसर और एस0डी0एम0 के अलावा क्या किसी और विभाग ने कोई कार्रवाई की है? ये जो बाकी आपने अधिकृत किए हैं इनको अधिकृत करने का क्या फायदा है, जब ये कोई ऐक्शन ही नहीं लेते हैं? फिर उसमें चाहे जल शक्ति विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो या वन विभाग हो।

उद्योग मंत्रीः माननीय सदस्या जी, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रही हैं। अगर जल शक्ति विभाग की स्कीम के ऊपर किसी प्रकार की अवैध माइनिंग की गतिविधियां होती हैं तो वे हमारे लोगों को बुलाते हैं और हम उनके साथ जाते हैं तथा ऐक्शन भी होता है। लोक निर्माण विभाग में भी ऐसा ही है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर्टिकुलर स्थान पर वायलेशन हो रही है तो कृपा करके यदि आप बताएंगी तो उसके ऊपर भी ऐक्शन लेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्षः यह चम्बा जिला से स्पेसिफिक प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर दिया है।

04/03/2020/1140/MS/AG/3

प्रश्न संख्याः 2507

श्रीमती रीता देवीः अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि यह शाह नहर परियोजना फतेहपुर तक तो कम्पलीट है लेकिन मेरे इंदौरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 8980 हैक्टेयर भूमि सिंचित होना अनुमानित है जिससे 43 गांव लाभान्वित होंगे परन्तु वर्तमान में 8980 हैक्टेयर भूमि में से 4489 हैक्टेयर भूमि की ही सिंचाई हो पाई है।

जे0के0 द्वारा जारी-----

03.03.2020/1145/JK/AG /1

प्रश्न संख्याः 2507:-------जारी------

श्रीमती रीता देवीः -----जारी-----

अध्यक्ष महोदय, 4,531 हेक्टेयर भूमि यानि 51 प्रतिशत भूमि की सिंचाई नहीं हो पाई है। सिंचाई में वंचित क्षेत्र के लिए विभाग द्वारा सी.ए.डी.ए. शाह नहर से प्रधान मंत्री सिंचाई योजना से हर खेत को इस योजना के अन्तर्गत 95 करोड़ रुपये की मंजूरी केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। इसी मद में 1.67 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त विभाग को मिल गई है परन्तु दूसरी किश्त से सम्बन्धित मामला वर्ष 2016 से लम्बित है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

जल शक्ति मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परियोजना काफी बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 15,287 हेक्टेयर जमीन सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई है। यह परियोजना वर्ष 1997 से शुरू हुई थी। वर्ष 1997 में इसकी AA&ES 143.90 करोड़ रुपये की हुई थी। फिर दोबारा इसकी रिवाइज्ड AA&ES 26.04.2008 में 310.79 करोड़ रुपये की दी गई। उसके बाद इसकी दोबारा से रिवाइज्ड AA&ES 31.03.2012 को 387.17 करोड़ रुपये की दी गई। यह एक बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना को भारत सरकार की तरफ से या आई.बी.पी. के माध्यम से 90:10 के अनुपात में राशि दी गई है। अब जितनी ये राशि दी गई है, उसके अन्तर्गत इसमें काफी ज्यादा काम हुआ है लेकिन अभी भी जैसे कि माननीय सदस्या जी चाह रही हैं कि शाह नहर की डवैल्पमैंट के साथ अभी काफी काम बाकी है। इस नहर के राइट बैंक की लम्बाई 47.305 किलोमीटर है, लैफ्ट बैंक की लम्बाई 26.009 किलोमीटर है। अब 90:10 के अनुपात में जितनी राशि थी वह सारी खर्च हो चुकी है। योजना सितम्बर, 2013 में पूरी हो चुकी है। इन्होंने भी ठीक कहा कि अभी तक शाह नहर डवलपमैंट का प्रोजैक्ट भारत

03.03.2020/1145/JK/AG /2

सरकार के पास लम्बित है, जो कि 79.98 करोड़ रुपये का है। उस पैंसे में से 12.08.2016 को 1.17 करोड़ रुपया दिया है। सी.ए.डी.ए. में यह काफी पहले यानि 2016 का प्रोजैक्ट है

और अब तो इसकी भी लागत बढ़ी है। विभाग कोशिश कर रहा है कि इस योजना के लिए और राशि दी जाए। जैसे कि माननीय सदस्या कह रही हैं कि इनके विधान सभा क्षेत्र का काफी बड़ा एरिया, 4-5 हजार हेक्टेयर का एरिया है जो कि मेरे ध्यान में नहीं है। **मैं आपसे चाहूंगा कि आप निश्चित तौर पर मुझे बताएं कि ऐसा कौन-कौन सा एरिया है, कौन-कौन से गांव हैं जिनको इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है। निश्चित तौर पर हम उनको भी शामिल करेंगे और उसके उपरान्त फिर दोबारा से हमें यह रिवाइज्ड डी.पी.आर. बना कर भारत सरकार को भेजनी पड़ेगी।**

प्रश्न समाप्त।

श्री एस.एस. द्वारा जारी

04.03.2020/1150/SS-AS/1

प्रश्न संख्या : 2508

श्री विशाल नैहरिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपने दिशा निर्देश तो जारी कर दिये हैं परन्तु अभी भी कई कार्य ऐसे हैं जो नगर निगम धर्मशाला में लम्बित पड़े हुए हैं। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि आप इन खाली पदों को भरने के लिए कितना समय लेंगी? यह आप हमें बता दीजिए।

शहरी विकास मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मैंने कहा कि 23 पद रिक्त हैं, अगर हम देखें तो उसमें श्रेणी-III के 14 पद रिक्त हैं और चतुर्थ श्रेणी के 4 पद रिक्त हैं। इस प्रकार श्रेणी-III और IV के कुल 18 पद रिक्त हैं। उसका एम0सी0 की फंक्शनल कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमने उसको किसी-न-किसी तरीके से रिऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे हैल्थ ऑफिसर का बहुत पुराना ब्रिटिश समय का पद चला हुआ है। इसी तरह के और भी कई पद हैं। आजकल जैसे टांडा और धर्मशाला में अन्य बड़े हॉस्पिटल्ज़ हैं इसलिए उनके साथ लगती एम0सी0 में हैल्थ ऑफिसर जैसे पदों की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से जैसे हमारे पास एस0डी0ओज़0 हैं उनके पास एम0सी0 के एक्सियन का चार्ज दे रखा है। टी0सी0पी0 में जो टाउन प्लानर है उसको एम0सी0 का काम भी दे रखा है। क्योंकि टी0सी0पी0 का

काम थोड़ा है इसलिए वे एम0सी0 का भी काम देख रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति काफी सही है। **एम0सी0 धर्मशाला में काफी पद भरे हुए हैं और जो पद खाली हैं उनको हम रिऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जहां पर थोड़ी बहुत कमी-पेशी होगी, उसको भी हम पूरा करेंगे।**

04.03.2020/1150/SS-AS/2

प्रश्न संख्या : 2509

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, यह जो नमगया गांव है यह हिन्दुस्तान का आखिरी गांव है। तिब्बत के साथ लगता गांव है। वहां पर बहुत बागवानी होती है। लेकिन वहां पानी की बड़ी किल्लत है। यह मैं दूसरी बार प्रश्न कर रहा हूं। हमने इसको एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में रखा हुआ है। परन्तु विभाग इसमें लापरवाही बरत रहा है। अब ये कहते हैं कि सतलुज में सिल्ट है। मैंने यह पूछा था कि जो आपने डी0पी0आर0 तैयार की, कब आपने टैस्ट किया कि सतलुज में कितनी सिल्ट है? इससे नीचे के इलाके में कोई 3 हजार मैगावाट से ज्यादा पन-बिजली योजनाएं बन रही हैं। उसमें भी क्या सिल्ट का असर नहीं हो रहा? इसी के नीचे हमारी पूह गांव की पंचायत ने केवल मात्र 30 लाख रुपये में सतलुज के पानी को दो किलोमीटर ऊपर निकाल दिया। उसमें भी 14-15 लाख रुपया बिजली विभाग को दिया है। इसका मतलब है कि 15 लाख रुपये में 2 किलोमीटर तक पानी हम नीचे से ऊपर पहुंचा पा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आई0पी0एच0 का जो एक्सियन बैठा है उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल क्यों नहीं करते? मुझे यह बताया जाए कि पानी का टैस्ट कब हुआ? बिना टैस्ट के आप कह देते हैं कि सतलुज में गाद है। इसका मतलब है कि आप स्कीम बनाना नहीं चाहते हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मुझे टैस्टों की रिपोर्ट दी जाए कि कब टैस्ट किया? कौन अधिकारी मौके पर गया, कितना पानी लिया गया और कितनी गाद किस महीने में थी? क्या आज की डेट में वहां पर बोरवैल नहीं खोला जा सकता? क्या आज की डेट में वहां पर सैडिमेंटेशन टैंक नहीं बनाया जा सकता? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

जल शक्ति मन्त्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, वैसे वाकई चिन्ता का विषय है। मैं माननीय सदस्य की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सतलुज नदी से अनेकों ऐसी सिंचाई की परियोजनाएं हैं जिनमें डाउन स्ट्रीम में पानी उठाया गया है।

जारी श्रीमती के0एस0

04.03.2020/1155/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्या 2509जारी--

जल शक्ति मंत्री जारी---

मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी एक स्कीम को मैंने एक बार बजट में डाला, विभाग ने उसको इनफिज़िबल कह कर नकार दिया। फिर हमने दूसरी बार डाला, फिर उन्होंने दूसरी बार उसको इनफिज़िबल कर दिया। जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना, मैंने तीसरी बार डाला तो वह फिज़िबल हो गई। मैंने उनको पूछा कि दो बार इनफिज़िबल हो गई तो तीसरी बार फिज़िबल कैसे हो गई? सोर्स ऑफ वाटर तो वही है, वही नदी है, वही पानी है, तो ऐसा होता रहता है। मैंने विभाग को आदेश दिए है कि इसको दोबारा से री-एग्ज़ामिन करें। 72 साल देश की आजादी के उपरांत भी अगर हमारी टैक्नोलॉजी यह कहे कि नॉट फिज़िबल है तो ऐसा नहीं है। मैं दोबारा से उसको री-एग्ज़ामिन करवाऊंगा और इसकी डी.पी.आर. बनवाकर इस कार्य को करने की कोशिश करेंगे।

04.03.2020/1155/केएस/एएस/2

प्रश्न संख्या 2510

श्री होशयार सिंह (देहरा): अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है, इसमें बताया गया है कि 74 companies fall under CSR. मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कानून के मुताबिक इन्होंने 2 परसेंट CSR पूरा इस्तेमाल किया है या नहीं?

दूसरे, क्या सरकार यह प्रयास करेगी to get the maximum CSR fund for the development of the State and distribute that fund equally in all the districts of the State. क्योंकि इस पूरी लिस्ट में जिला कांगड़ा के 15 चुनाव क्षेत्रों में कहीं भी पैसा नहीं लगा है, सिर्फ दो जगह लगा है that too a mere amount of 15.00 lakh बाकी न चम्बा में, न जिला कांगड़ा में और न मेरे चुनाव क्षेत्र में कहीं भी यह पैसा नहीं लगा है। तो यह CSR का पैसा आया, यह सिर्फ दो ही जगह जा रहा है बाकी हमें इसका कोई लाभ नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक और जानकारी लेना चाहूंगा, जानकारी नहीं यह प्रश्न है कि सिर्फ 5 कम्पनियां जिनमें एस.जे.वी.एन.एल. का वर्ष 2018 का नैट प्रोफिट 1,224 करोड़ रुपये, एन.एच.पी.सी. का वर्ष 2018 का प्रोफिट 2,758 करोड़ रुपये, ए.सी.सी. का है 1,510 करोड़ रुपये, अम्बुजा का 1,487 करोड़ और कॉलगेट पॉमोलिव का प्रोफिट 673 करोड़ रुपये है। ये सिर्फ पांच कम्पनियां हैं जिनका कुल मिलाकर हिमाचल में 7,652 करोड़ रुपये का प्रोफिट है। यदि आप इसका 2 परसेंट कैल्कुलेट करते हैं तो ये 160 करोड़ रुपये होता है। 160 करोड़ में अगर हिमाचल को ही सिर्फ 50 परसेंट भी ये कम्पनियां देती हैं तो 75 करोड़ होता है। परन्तु 75 करोड़ तो छोड़ो यह 5 करोड़ भी नहीं है। तो यह पैसा कहां जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस CSR को कौन कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है और इसकी डिस्ट्रिब्यूशन कौन करता है?

04.03.2020/1155/केएस/एएस/2

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, कम्पनी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार CSR हेतु स्कीमों का चयन कम्पनी की CSR कमेटी तथा बोर्ड के डायरैक्टर्ज़ पर निर्भर करता है। राज्य सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता। दूसरे, कम्पनीज़ एक्ट के अनुसार कम्पनी को CSR राशि व्यय करते समय स्थानीय स्कीमों को प्राथमिकता देनी चाहिए परन्तु इसकी कोई बाध्यता नहीं है। कम्पनी को अपनी CSR राशि व्यय करते समय जहां-जहां उसका कार्यक्षेत्र है, वहां-वहां बांटना पड़ता है अतः CSR की सम्पूर्ण राशि एक राज्य अथवा स्थान पर व्यय

करना शायद सम्भव नहीं है। अध्यक्ष जी, एक तो मैंने बताया कि इसके कायदे-कानून, इसकी जो भी प्रक्रिया है, इसका सारा सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्ज़ से चलता है, भारत सरकार से चलता है। इसका हमारे पास कोई हिसाब-किताब नहीं है और न ही हमारा इसके ऊपर कोई चैक है लेकिन यह व्यवस्था पक्की है कि जो उनका प्रोफिट होता है, कम्पनी का जो 5 करोड़ रुपये से ज्यादा प्रोफिट है, उनको 2 परसेंट खर्च करना पड़ता है, वह उसने कहां खर्च किया, इसकी जानकारी लेने का हमें हक है। एक आपने कुछ कम्पनियों के नाम लिए कि उनको बहुत ज्यादा लाभ हुआ है, उसका कुछ परसेंटेज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर लगे तो उसका फायदा हो सकता है और आपने कुछ जिलों का नाम भी मैंशन किया,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

04.03.2020/1200/av-dc/1

प्रश्न संख्या : 2510 क्रमागत--------

उद्योग मंत्री ---- जारी

मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यवस्था या प्रावधान है वह मैंने आपको बता दी है। लेकिन फिर भी वे हमारे इन क्षेत्रों के अंदर लगे हैं और हम इसके बारे में रिप्रेजैंट करते हैं, गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को लिखते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था भी की जाए ताकि हमारे ऐसे क्षेत्रों को भी लाभ मिले जहां इनका लाभ नहीं मिला है।

04.03.2020/1200/av-dc/2

प्रश्न संख्या : 2511

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो आपने प्रश्न के 'क' भाग के उत्तर के अंतर्गत प्रोजैक्ट दर्शाए हैं क्या इनकी ए0ए0 एण्ड ई0एस0 हो चुकी है और इनके टैंडर कब तक लगेंगे? दूसरा, प्रश्न के 'ख' भाग में जो आपने लिखा है कि 4 योजनाओं की डी0पी0आर0 बनाई जा चुकी हैं तो क्या ये

डी0पी0आर0 प्लानिंग डिपार्टमैंट को भेजी जा चुकी हैं ताकि उनको आगे नाबार्ड को भेजा जा सकें तथा जो नहीं बनाई है वह कब तक बना दी जायेगी?

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इनकी जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक योजना 24,83,89,000/- रुपये की है तथा उसकी टैक्निकल बिड खुल चुकी है। आपकी दूसरी योजना 12,73,12,000/- रुपये की है और यह भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत है तथा इसकी भी टैक्निकल बिड खुल चुकी है। आपकी तीसरी योजना विभिन्न बस्तियां, ग्राम पंचायत लाना चेता की 157.45 लाख रुपये की है। इसके लिए टैंडर किए थे मगर सिंगल बिड आने की वजह से इसको रीकॉल किया गया है। चौथी योजना आपकी ग्राम पंचायत चाड़ना, तहसील संगड़ाह की 2,50,36,000/- रुपये की है और इसकी भी टैक्निकल बिड खुल चुकी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि टैंडर की एक प्रक्रिया होती है। उसमें सबसे पहले टैक्निकल बिड खुलती है और उसमें कितने ठेकेदार या फर्म्ज क्वालीफाई करती है फिर उन्हीं की फाइनेंशियल बिड खोली जाती है। टैक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड में ज्यादा दिनों का गैप नहीं होता। हम कोशिश में हैं कि इसकी फाइनेंशियल बिड जल्दी-से-जल्दी खोली जाए। फाइनेंशियल बिड खोलने के बाद इसकी जस्टिफिकेशन बनती है और फिर नेगोसिएशन होती है तथा उसके उपरान्त वर्क अवार्ड होता है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां माननीय जय राम जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके रेणुका विधान सभा क्षेत्र के लिए बोरियों में धन भर-भर कर दे रही है। लेकिन आप फिर भी नहीं मानतें, आप माना भी करो और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद भी किया करो। प्रश्न के 'ख' भाग में जो नाबार्ड या दूसरी परियोजनाएं हैं उनकी प्रक्रिया भी प्रोसैस में चली हुई है।

प्रश्न काल समाप्त

04.03.2020/1200/av-dc/3

सदन की समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2019-20), समिति का 20वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि समिति के 36वें मूल

प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2019-20) का 20वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि समिति के 36वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित है,की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

04.03.2020/1200/av-dc/4

विधान सभा कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब कर्नल इन्द्र सिंह, सदस्य, कार्य सलाहकार समिति का दशम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित करेंगे तथा प्रस्ताव भी करेंगे कि उसे अंगीकार किया जाए।

कर्नल इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति का दशम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित करता हूं तथा यह प्रस्ताव भी करता हूं कि इसे अंगीकार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने दशम् प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने दशम् प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है?

प्रस्ताव स्वीकार

मंत्री द्वारा वक्तव्य टी सी द्वारा जारी

04.03.2020/1205/TCV/DC-1

मंत्री द्वारा व़क्तव्य

अध्यक्षः अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री व़क्तव्य देंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी ने 02 साल पहले ट्राउट मछली के 5,00,000 अण्डे जो जम्मू-कश्मीर से लाये गये थे, उसमें वायरस होने की बात कही थी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी हमने डी0सी0एफ0आर0 , भीमताल, उत्तराखण्ड से जांच करवाई थी तो उसमें ऐसा कोई भी वायरस नहीं पाया गया था।

दूसरा, जो इन्होंने कहा कि ट्राउट पालक के फॉर्म इस बीज़ के कारण खाली पड़े हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2018-19 में भारी बारिश हुई और पतली-कूहल का जो फॉर्म था, वह नष्ट हो गया। इसके बावजूद भी हमने 5,00,000 मछली के अण्डे जम्मू-कश्मीर से मंगवाये लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे, फिर भी हमने ये अधिकांश किसानों को दिए। इस वर्ष हम 10,00,000 ट्राउट आई.डी. ओबा, डैनमार्क से मंगवा रहे हैं और इनको सभी किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। हम इसमें कमी नहीं आने देंगे। मैं यह स्पष्टीकरण देना चाहता था।

04.03.2020/1205/TCV/DC-2

मुख्य मंत्री द्वारा व़क्तव्य

अध्यक्षः धन्यवाद मंत्री जी, अब माननीय मुख्य मंत्री, बद्दी में बिना लाइसैंस नकली दवाइयां बनाने वाली कम्पनी बारे माननीय सदन को जानकारी देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक व़क्तव्य इस माननीय सदन में रख रहा हूं। छत्तीसगढ़ दवा प्रशासन से सूचना प्राप्त हुई कि छत्तीसगढ़ में कुछ दवाइयां कोरियर कम्पनी द्वारा प्राप्त हुई है और भेजने वाले का नाम आदर्श फॉयल्ज़, बद्दी है। इन दवाइयों के नकली होने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत संवेदनशील विषय है क्योंकि दवाइयां सीधा मानव के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए ही हमने यह कार्रवाई की है, जिसकी मैं जानकारी दे रहा हूं। इस सूचना के प्राप्त होते ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया और जांच प्रारम्भ कर दी गई। इस कड़ी में सूचना जुटा कर पहले दिनांक 02.03.2020 को आदर्श फॉयल्ज़ का निरीक्षण किया गया और आदर्श फॉयल्ज़ के मालिक से सूचना जुटाई गई व रिकॉर्ड खंगाला गया जिससे यह पता चला कि मै0 ग्लैमर्ज़ हैल्थ केयर प्राइवेट लि0, साईं रोड, बद्दी इस प्रकार की नकली दवाइयां बनाने में शामिल है। दिनांक 03 मार्च, 2020 को सहायक औषधि नियंत्रक व ड्रग इंस्पैक्टर ने पुलिस की मदद से मै0 ग्लैमर्ज़ हैल्थ केयर प्राइवेट लि0, साईं रोड, बद्दी के परिसर का निरीक्षण किया। श्री अनुराग शुक्ला व श्री अरविंद शुक्ला मौके पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि वे इस फर्म़ का काम देखते हैं। तलाशी के दौरान यह पाया गया कि इस फ़र्म के पास वर्ष 2016 से फूड प्रोडक्शन का लाइसैंस था। इस फ़र्म में टैब्लेट्स, कैप्सूल और ओरल लिक्विड बनाने की मशीनें पाई गईं। तलाशी के दौरान इलैग्जरा फॉर्मा, उत्तराखंड व ऐसीबोलिक एस0पी0 टैब्लेट, निरमया फॉर्मा, बद्दी के नाम पर बनी हुई दवाइयां, दूसरी कम्पनी की प्रिंटिड रोल्ज़ फॉयल्ज़, डिब्बे व रबड़ की मोहरें इत्यादि पाई गई।

एन0एस0 द्वारा .... जारी ।

04-03-2020/1210/NS/HK/1

माननीय मुख्य मंत्री .....जारी

जिन्हें फॉर्म-16 पर जब्त कर लिया गया है। कोर्ट से कस्टडी ऑर्डज़ आज दिए जाएंगे। कब्जे में ली गई दवाइयों के सैंपल्ज़ भी ले लिए गए हैं जो बिना लाइसैंस के नकली दवाइयां बनाने का स्पष्ट मामला है। दिनांक 03 मार्च, 2020 को Drugs & Cosmetics Act की धारा 27 (C) के तहत श्री अरविन्द शुक्ला और अनुराग शुक्ला पर सैक्शन 18 (A) (1) सैक्शन 17 (B) की अवहेलना के लिए पुलिस थाना, बद्दी में एफ0आई0आर0 दर्ज़ कर दी गई है। इसमें सात साल से ले करके उम्र कैद तक का प्रावधान है। इस एफ0आई0आर0 में पुलिस विभाग से अनुरोध किया गया है कि इनके बाकी साथियों को भी पकड़ा जाए। इन्होंने रॉ मैटीरियल, फोयल्ज़ व डिब्बे कहां से लिए तथा नकली दवाइयां कहां बेचते थे? इसका पता लगाया जाए। एस्सिटैंट कमीश्नर, फूड सेफ्टी (सोलन) व फूड सेफ्टी ऑफिसर (सोलन) ने दिनांक 03-03-2020 को सैंपल लिए तथा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 के अंतर्गत इसमें विस्तृत जांच की जा रही है। मैं0 ग्लैमर्ज़ हैल्थकेयर, साईं रोड, बद्दी को सील करके पुलिस कार्रवाई बैठा दी गई है। अरविन्द शुक्ला और अनुराग शुक्ला को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मैंने इस माननीय सदन में इसलिए दी क्योंकि मुझे लगा कि जब भी कोई ऐसा विषय सरकार के ध्यान में आता है तो सरकार तुरंत कार्रवाई करती है ताकि मानवीय जीवन के साथ कोई इस प्रकार का हादसा या घटना न घटित हो और इस प्रकार की नकली दवाइयां न बनाई जाएं।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह लाइसैंस वर्ष 2016 से लिया था और यह लाइसैंस फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए लिया था लेकिन वहां पर ये इस प्रकार का काम कर रहे थे जो नियमों के खिलाफ़ है। इनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई जिस रूप में भी की जा सकती है उस कार्रवाई को हम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर एक स्टेटमैंट और देना चाहता हूं। हमारा एक आई0डी0पी0 का प्रोजैक्ट है। इसके बारे में अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली इंटेग्रेटिड डवलपमैंट प्रोजैक्ट (आई0डी0पी0) के लिए विश्व बैंक के Board of Executive Director ने दिनांक 18 फरवरी, 2020 को हुई बैठक में 80

मिलियन यू.एस. डॉलर यानी 560 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति प्रदान की है। माननीय मुकेश जी, आप सुन लीजिए। इन्होंने कहा है कि स्वीकृति नहीं हुई और कोई धनराशि नहीं आई है। यह अंतिम बैठक जो स्वीकृति के लिए होती है वह हुई है। मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं। इसके लिए शीघ्र ही समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इसके बाद एम0ओ0यू साइन करने की औपचारिकता रहती है। इस परियोजना हेतु विश्व बैंक के साथ लोन नेगोशिएशन दिनांक 03 जनवरी, 2020 को हुआ था जो राशि भारत सरकार से प्रदेश को 90 प्रतिशत अनुदान यानी 504 करोड़ रुपये और 10 प्रतिशत प्रदेश सरकार का शेयर यानी 56 करोड़ रुपये की राशि होगी तथा ऋण के रूप में प्राप्त होगी। यह महत्वकांक्षी परियोजना लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत की हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में अगले 7 वर्षों में वन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। जिससे पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

04.03.2020/1215/RKS/HK-1

मुख्य मंत्री... जारी

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त स्टेट रोड ट्रांसफोर्मेशन परियोजना के प्रथम चरण के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, विश्व बैंक तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच 21 फरवरी, 2020 को शिवरात्रि के शुभ दिन पर समझौता वार्ता सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई है। अप्रैल, 2020 को इस परियोजना से संबंधित ऋण अनुबंध (loan agreement) हस्ताक्षरित हो जाएगा। कुल 1540 करोड़ रुपये की लागत की यह परियोजना दो चरणों में लागू की जाएगी। योजना के प्रथम चरण में कार्यान्वयन हेतु लगभग 575 करोड़ रुपये (82 मिलियन डॉलर) की धनराशि 90:10 में प्रदेश सरकार को प्राप्त होगी। परियोजना के 6 वर्ष के कार्यकाल के प्रथम चरण में लगभग 90 किलोमीटर लम्बाई की चार सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्तरोन्नत कर विश्व स्तरीय आधारभूत सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा

जिससे प्रदेश की आर्थिकी तथा जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा।

इसके अतिरिक्त परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित विभागों की रूप रेखा तथा कार्य-पद्धति में मूलभूत सुधार, सड़क दुर्घटना की दृष्टि से अति संवेदनशील सड़कों पर सी.सी.टी.वी. कैमराज लगाना व दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जन-सहभागिता को बढ़ावा देने जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां भी इस परियोजना में शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय, शिमला शहर में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एस.जे.पी.एन.एल. द्वारा कार्यान्वित की जा रही शिमला, वाटर सप्लाई और सीवरेज प्रोजैक्ट की शत-प्रतिशत लागत को वर्ल्ड बैंक द्वारा वहन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत डी.पी.एल-I में 280 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है। भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2019 को आयोजित त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक में डी.पी.एल.-1 के कार्यान्वयन पर संतुष्टि जताते हुए भारत सरकार व वर्ल्ड बैंक द्वारा इस परियोजना के दूसरे चरण डी.पी.एल.-II को अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। 12 से 23

04.03.2020/1215/RKS/HK-2

नवम्बर, 2019 को प्रदेश में आये वर्ल्ड बैंक मिशन ने इस परियोजना को पूरे प्रदेश में लागू करने हेतु दूसरे चरण डी.पी.एल.-II में प्रदेश की 13 यू.एल.वीज. के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपये यानी दो सौ मिलियन डॉलर की शत- प्रतिशत सहायता के लिए सहमति प्रदान की है। अब आप पूछेंगे कि पैसा कहां से आएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैसा आ जाएगा। हम उसके बहुत करीब पहुंचे हैं और हर चीज के लिए वक्त लगता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन में यह जानकारी देना चाहता था।

अध्यक्षः माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली): माननीय अध्यक्ष जी, 'ब्रिक्स' में कोई पैसा नहीं आया है। वैसे भी 'ब्रिक्स' में 190 करोड़ रुपये श्री महेन्द्र सिंह जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को आये हैं। मुख्य मंत्री जी को तो बहुत थोड़ा पैसा मिला है और इनके वहां पर 160 करोड़ रुपये मिला है। जो आपने 'ब्रिक्स' का जवाब दिया, है वह पैसा नहीं आया है। वह तो आपके निर्वाचन क्षेत्र का पैसा फंस गया है। हमने 1892 करोड़ रुपये के टूरिज्म प्रोजैक्ट की बात की। मुझे लगता है कि जब आप जवाब देंगे, तो इसकी स्थिति स्पष्ट करेंगे।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

04.03.2020/1220/बी.एस./वाई.के./-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी....

हमने रेलवे के प्रोजैक्ट्स की बात की है, मुझे लगता है कि आप जरूर बताएंगे कि रेजवे के प्रोजैक्ट्स की क्या स्थिति है? हमने हवाई प्रोजैक्ट्स की बात की है। आपने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि फोरन फडिंग से 11 हजार करोड़ रुपया आ रहा है। उसमें से 5 प्रोजैक्ट्स आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी के विभाग के हैं। कोई इसमें रिमोल्डिंग का है कोई चैनेलाइजैशन का है। वह जो हमने प्रोजैक्ट्स का जिक्र किया है उस बारे में हमें बताएं। जिस दिन यह सारी बात मैंने यहां पर रखी थी, उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं थे। गिरी से आप शिमला के लिए पानी उठाना चाहते थे, 15 करोड़ रुपया आपने जारी किया था। 15 करोड़ रुपए की सीधे बर्बादी हो गई है। आपने यह स्क्रैप्ट कर दिया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जब चर्चा में हिस्सा लिया था, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं थे परंतु जब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे तो ये सभी बातें उसमें आ जाएंगी।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, कृपया आप भी थोड़ा सयंम रखिए। हम अध्यक्ष की कुर्सी का बड़ा सम्मान करते हैं और आपका भी सम्मान करते हैं लेकिन ऐसा इम्प्रैशन न जाए कि आप सरकार के लिए हैं।

अध्यक्ष : इस तरह का कोई इम्प्रैशन नहीं जाएगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : सुबह जो हुआ है वह बहुत गलत हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुख्य मंत्री महोदय ने तीन स्टेटमैंट्स अब दी हैं। अभी मंत्री जी ने स्टेटमैंट्स दी है। लेकिन ठीक है आप कुर्सी पर नए-नए विराजमान हुए हैं आपने एक एक्सैप्शन आज तक की हिस्ट्री में कर दी है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने जो 7-8 प्रोजैक्ट्स की बात की है उन पर स्पैसिफिक जवाब आ जाए इतना मैं चाहता हूं।

04.03.2020/1220/बी.एस./वाई.के./-2

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ है और कुर्सी के मान-सम्मान की बात आपने कही है। इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह सही है कि चर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष के तालमेल से होती है परंतु निर्णय इस चेयर का होता है कि चर्चा किस नियम के अन्तर्गत कब होनी है। यह बात में आपके ध्यानार्थ लाना चाहता हूं। दूसरा अगर सरकार में मंत्री और मुख्य मंत्री किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपनी स्टेटमैंट देना चाहते हैं तो उनको अधिकार है और यह नियमों के अनुरूप है। आपने कहा कि नियमों की धज्जियां उड़ा दी। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि आपकी संसदीय पद्धति के अनुसार ही कार्यवाही चलती है। आपको बोलने का पूरा अधिकार है ।

मुख्य मंत्री : जो विपक्ष के नेता ने मामला उठाया उसका हमने उत्तर दिया है। आप बात नहीं करते आप शोर डालने का काम करते हैं।

अध्यक्ष : मैं स्वयं जानता हूं कि मुझे कौन सी जिम्मेवारी कैसे निभानी है। आप नेता प्रतिपक्ष है। अगर विपक्ष ने ही सब कुछ निर्णय लेना है तो इस कुर्सी का क्या औचित्य है? अब माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे।

जल शक्ति मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रतिपक्ष के नेता से विनम्र आग्रह रहेगा कि बार-बार आप माननीय अध्यक्ष की कुर्सी को इस तरह अपमानित न करें। आपको भी एक लम्बा समय इस माननीय सदन में हुआ है और हमें भी यहां बैठते हुए लम्बा समय हुआ है।

यदि हम हर बार, हर बात पर ही माननीय अध्यक्ष जी के ऊपर प्रश्न उठाएंगे, अगुंली उठाएंगे उससे इस माननीय सदन की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। दूसरा प्रतिपक्ष के नेता से मेरा आग्रह रहेगा कि आपने एन.डी.पी. प्रोजैक्ट की बात कही है।

श्री डी.टी.द्वारा जारी...

04.03.2020/1225/DT/YK-1

जल शक्ति मन्त्रीः जारी

यह प्रोजैक्ट वर्ष 2016 में डी.ए. से हुआ था। वर्ष 2016-17 में आपकी सरकार थी। वर्ष 2018 में फिर हम आये। आपको वर्ष 2016-17 में जो काम करने चाहिए थे, उस पर आपने कुछ नहीं किया। हम इस पर आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ने पर यह जो बैंक है यह संघाई में है, चाईना में है। इसमें माननीय अध्यक्ष जी, हमे एक टैक्निकल दिक्कत आ रही है। उस टैक्निकल दिक्कत को बैंक के अधिकारियों ने हमारे साथ, हमारे भारत सरकार के आधिकारियों के साथ शेयर नहीं किया। अभी दो तीन महीने पहले भारत सरकार के अडिशन सैक्रेटरी आये थे। जब में उनसे मिला, मैंने उनसे कहा की यह क्या बात है? उन्होंन एक टैक्निकल प्रोब्लम बताई। ...(व्यवधान)माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चहाता हूं कि बहुत बातें ऐसी है हमें इस हऊस के बीच में नहीं बोलनी चाहिए। जो टैक्निकल दिक्कत उन्होंने बताई हमने कहा कि हम उस दिक्कत का समाधान कर देते हैं। हमने उस दिक्कत का समाधान कर दिया। उसके बाद हमने उन सारी प्रपोजल को बदला। बदलने के उपरांत जब बी.ओ.डी. की बैठक होनी थी, तो जिस कारोना को लेकर आज पूरा देश, पूरा विश्व भयभीत है, उस कारण वह बी.ओ.डी की बैठक नहीं हुई। जब की वह बैठक एक महीना पहले होने वाली थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं की यह सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में किसी भी बात को नहीं छुपाएगी। दुसरा, आपने उस दिन कहा था की ए.डी.बी. का जो प्रोजैक्ट है जो रेनोवेशन ऑफ ऑल्ड वॉटर सप्लाई स्कीम है, उसमें हम लास्ट स्टेज पर पहुंचे हैं। मैने उस दिन भी कहा था और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज भी कह रहा हूं, यह जो फोरन फंडिग प्रोजैक्ट है, अगर हम ऐसा बोले की हम भारत सरकार के पास गये, हम डी.ए. के पास गये, किसी बैंक को उन्होंने अधिकृत किया और

वह बैंक हमें सीधा पैसा दे दें तो उसके लिए एक प्रोसैस है। जब तक उस पूरे प्रोसैस से वह गुजरेंगे नहीं तब तक वह नही करते हैं। मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर उनको लगता है की यह प्रोजैक्ट वायबल है तो फिर वह अपना कंसलटेंट लगाते हैं और जब उनका कनसलटैंट सब कुछ देखता है उसको देखने के उपरांत फिर जब वे सैटीसफाई हो जाते हैं फिर वह कहते हैं कि अब आप अपना कनसलटैंट लागाइए। जब दोनों कनसलटैंट डी.पी.आरज. बनाकर फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं तो फिर मेजर मिशन आता है। अब मेजर मिशन की तरफ एशियन डवलपमैंट बैंक जो रेनोवेशन ऑफ

04.03.2020/1225/DT/YK-2

ऑल्ड वाटर सप्लाई सकीम जिसमें 798 करोड़ रूपये आने वाले समय में हमारे को विभिन्न पेय जल परियोजनाओं के लिए है वह अप्रैल, मई तक आने वाला है। इसके इलावा शिवा प्रोजैक्ट है शिवा प्रोजैक्ट है। यह प्रोजैक्ट उस स्टेज पर पहुंच चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो ए.डी.बी. मिशन आया उसकी बैठक विधान सभा के अंदर ही हुई। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रिम प्रोजैक्ट है जिसमें किसान की आमदनी को वर्ष 2022 तक दोगुना करना है, उस प्रोजैक्ट को हमने जल शिक्त विभाग के माध्यम से डी.ए. को भेजा। डी.ए. ने उसको स्वीकार किया। दुसरा प्रोजैक्ट जो बागवानी के लिए था, ऐसा क्षेत्र जो बागवानी से वंचित था जो सब ट्रोपिकल एरिया था, उसके लिए हमने 1680 करोड़ रुपये को प्रोजैक्ट भेजा और डी.ए. ने उसको भी स्वीकार किया। डी.ए. ने दोनो प्रोजैक्टों को एशियन डवलपमैंट बैंक को दे दिया। उनकी टैक्निकल टीम ने ऐसा महसूस किया कि ये दोनों प्रोजैक्ट आपसे में मिलते-जुलते हैं। सिंचाई किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए है और बागवानी का प्रोजैक्ट भी किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इस बात पर सहमती हुई की इन दोनों प्रोजैक्टों को इक्ट्ठा करके इसका नाम शिवा प्रोजैक्ट रखा जाए। 17 क्लस्टर पाइलेट प्रोजैक्ट के रूप में हिमाचल प्रदेश के बीच में प्लांटेशन हुई है। ...(व्यवधान) माननीय सुखविन्द्र जी आप पुराने सदस्य है।

श्री एन.जी. द्वारा... जारी

04-03-2020/1230/ए.जी.-एन.जी./1

जल शक्ति मंत्री जारी...

और मैं आपको एक राय देता हूं कि बैठे-बैठे हर बात पर बोलना और बीच-बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है।...(व्यवधान)

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मेरी बात का रिप्लाई बाद में भी दे सकते हैं।...(व्यवधान)

जल शक्ति मंत्रीः जब मैं बोल कर बैठ जाऊंगा तब आपको बोलने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, हम कहां मना कर रहे हैं कि यह कोई स्पष्टीकरण नहीं ले सकते। आप स्पष्टीकरण लें सकते हैं लेकिन जब आप बीच में बात करते हैं तो यह नियमों के विरूद्ध है।...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आगे अभी और भी चर्चा होनी है इसलिए आप बैठ जाएं।...(व्यवधान) आगे आपको ही बोलना है कृपया बैठ जाएं।...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आपको चर्चा में भाग लेना है आप उस समय अपनी बात रख सकते हैं। कृपया बैठ जाएं और माननीय सदन के समय को बचाएं।

जल शक्ति मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश हित की कोई बात हो तो विपक्ष के लोग उसे सुनना नहीं चाहते। माननीय सुखविन्द्र जी, जो भी प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं उन सभी में प्रदेश हित है। हमें कोई ऐसा प्वाइंट आउट कर दे कि किसी प्रोजैक्ट के अंदर हमने किसी भी विधान सभा क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि कोई भी योजना आए उसमें हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधान सभा क्षेत्रों का बराबर अधिकार है। मैं शिवा योजना में कहना चाहूंगा कि उसका मेजर मिशन अप्रैल-मई माह में आने वाला है। आप 5 साल सत्ता में रहे और यदि आपने उन 5 सालों में इस के लिए कोशिश की होती तो आज हमें इतना समय न लगता लोकिन आपकी तरफ से कोशिश नहीं हुई। आपके समय में कोई कोशिश न होने के कारण आज हमें ही इसके लिए सारी कोशिश करनी पड़ी। माननीय नेता प्रतिपक्ष

से मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आप हर बात में टांग अड़ाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप हिमाचल प्रदेश की प्रगति को रोकने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।...(व्यवधान)

04-03-2020/1230/ए.जी.-एन.जी./2

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है लेकिन आपने बजट में पेश कर दिया था और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से हटा दिया।

जल शक्ति मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि हम सभी को यह विचार करना होगा कि हिमाचल प्रदेश की योजनाओं को लाने में हमारा व्यक्तिगत रूप से क्या योगदान हो सकता है, हम इन्हें धरातल पर कैसे ला सकते हैं और जब हम इस मानसिकता के साथ चलेंगे तब निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा। हम सब चाहे विपक्ष में या सत्तापक्ष में बैठे हों, हम सभी अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों के प्रति जवाबदेह हैं और जो बड़े नेता हैं वे हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हम इस बात को न भूलें कि यदि आज हम सत्तापक्ष को रोकेंगे तो हमारा भला होगा और जो सत्तापक्ष की ओर बैठे हैं वे सोचेंगे कि हम विपक्ष के क्षेत्रों में कुछ नहीं करेंगे तो हमारा भला होगा। हम सत्तापक्ष वालों को सभी 68 विधान सभा क्षेत्रों में काम करना है और विपक्ष का काम है कि जो विकास की योजनाएं हैं उनके लिए सत्तापक्ष को सहयोग करना आवश्यक है। आपके और हम सब के सहयोग के बगैर कोई भी योजना सम्पूर्ण नहीं हो सकती है। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम अहंकार न करें और सभी को मिलजुल कर चलना चाहिए। मैं जो हाउस के बीच में देख रहा हूं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष की कुर्सी बहुत गौरवमयी होती है और इसकी तरफ कृपया उंगली न उठाएं।

अध्यक्षः माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी।

श्री मुकेश अग्निहोत्री जी श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

04/03/2020/1235/MS/As/1

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी अपने स्टैंड पर कायम हूं। 11000 करोड़ रुपये की फॉरैन फण्डिंग के प्रोजैक्ट्स में पैसा नहीं आया है; किसी भी प्रोजैक्ट में पैसा नहीं

आया है। मंत्री जी कह रहे हैं कि मिशन आ रहा है, पैसा आ जाएगा। यह प्रदेश के विकास की बात है। मंत्री जी, प्रदेश के विकास में हम भी उतने ही शामिल हैं जितने आप हैं। पिछले बजट में आपने 11000 करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट लिखे थे लेकिन एक साल के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उनकी चर्चा नहीं आई। हमने तो आपसे उनका सिर्फ़ स्टेट्स मांगा है। दूसरा, मंत्री जी महान हैं। हम इनसे ब्रिक्स की बात कर रहे हैं लेकिन इन्होंने ब्रिक्स में सबकुछ लपेट लिया। हमने तो यह कहा कि ब्रिक्स में आपने कहा कि 269.74 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 बन रही है। ठीक है, आपने अपने चुनाव क्षेत्र का भी विकास करना है क्योंकि आप वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं लेकिन धर्मपुर के लिए 78.86 करोड़ रुपये की एक डी0पी0आर0 और 62.26 करोड़ रुपये की दूसरी डी0पी0आर0 है। इसमें से आपने थोड़ा सा हिस्सा मुख्य मंत्री जी को 28 करोड़ रुपये और राकेश जम्वाल जी को 20 करोड़ रुपये दे दिया। इस तरह से 190 करोड़ रुपया निकल गया तो बाकी क्षेत्रों के लिए क्या बचा, यह सब आपके सामने है? फिर आप कह रहे हैं कि मैं संतुलित विकास कर रहा हूं। यह संतुलित विकास का एक ट्रेलर है कि आपने किस ढंग से 79 करोड़ रुपये और 62 करोड़ रुपये के दोनों प्रोजैक्ट्स अपने क्षेत्र के लिए रखे। इस तरह से 269 करोड़ रुपये के ब्रिक्स में बाकी क्षेत्रों के लिए तो कुछ है ही नहीं।

जल शक्ति मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि धर्मपुर विधान सभा चुनाव क्षेत्र का कोई भी प्रोजैक्ट उस वक्त शुरुआत में था लेकिन अब धर्मपुर का कोई भी प्रोजैक्ट ब्रिक्स में नहीं है। ...(व्यवधान) मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप इस तरफ हुआ करते थे बल्कि आपका आज भी विषय लगा है जिसमें आपने नियम-61 के अंतर्गत चर्चा मांगी है। उसके लिए मैंने हां की है कि चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, जब ये इस तरफ थे तो नाबार्ड का पैसा आया। क्या हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड का पैसा कुछेक क्षेत्रों के लिए है? नहीं, यह पैसा हिमाचल प्रदेश के 68 विधान सभा क्षेत्रों के लिए है। अध्यक्ष जी, पिछली बार जब हम उस तरफ थे तो मेरी एक भी स्कीम नाबार्ड में नहीं थी। लगभग 50 करोड़ रुपये की स्कीमें इनके चुनाव क्षेत्र में चली गईं। क्या अब मैं ऐसा कहूं कि सारी स्कीमें इनके क्षेत्र में क्यों चली गईं?

04/03/2020/1235/MS/As/2

जब आप इस तरफ होते हैं और उस समय आप अपने क्षेत्र का काम नहीं कर सके तो फिर कब करेंगे? लेकिन वर्तमान सरकार ने "जल जीवन मिशन" के अंतर्गत पूरे हिमाचल प्रदेश के किसी भी चुनाव क्षेत्र का; यहां पर विनय जी बैठे हैं, मैंने इनके प्रश्न का उत्तर दिया है कि जितने भी अपोजिशन के साथी बैठे हैं कोई भी साथी ऐसा कह दें कि उनके विधान सभा क्षेत्र में हमने "जल जीवन मिशन" में उनको इग्नोर किया है, कोई एक कह दे? हमने अपने तौर पर चारों जोन्ज की मॉनिटरिंग की है और चारों जोन्ज की मॉनिटरिंग करने के साथ-साथ 68 विधान सभा क्षेत्रों में देखा है; शहरी क्षेत्रों को छोड़कर की कोई क्षेत्र ऐसा तो नहीं रह गया, जहां पर अभी तक "जल जीवन मिशन" की कोई योजना न हो। मैं कुछ दिन पहले रात को सुन्नी में रूका था। मैंने वहां सुबह एक्सियन को पूछा कि यहां "जल जीवन मिशन" में कितनी योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अभी टैण्डर नहीं हुए हैं। आप मेरे अधिकारियों से पता करें। मैंने दूसरे ही दिन एस0ई0 शिमला को बुलाया और साथ में एक्सियन और एस0डी0ओ0 को भी बुलाया। मैंने उनको पूछा कि आप लोगों ने शिमला ग्रामीण क्षेत्र के "जल जीवन मिशन" के अंतर्गत टैण्डर क्यों नहीं किए। आप लोग पता कर सकते हैं। मेरे साथी यहां सामने बैठे हैं। मेरी बहन आशा जी सामने बैठी हैं, आप बोलिए? क्या हमने आपके क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है या किसी भी सदस्य के क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव किया है? मुकेश अग्निहोत्री जी, यह सरकार भेदभाव वाली सरकार नहीं है। भेदभाव कब होता था उसकी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप उस सत्तापक्ष वाली कुर्सी पर बैठते थे और हम आपको विपक्ष से बार-बार कहते थे कि हम भी लोकतंत्र की प्रक्रिया के अंतर्गत इस सदन में चुनकर आए हैं। हम पहली बार सदन में नहीं आए हैं। मैं सातवीं बार सदन में लगातार चुनकर आया हूं। आज माननीय जगत सिंह नेगी जी का प्रश्न लगा हुआ था। विभाग ने कहा कि योजना फिजिबल नहीं है। मैंने आज प्रश्न का यहां सदन में उत्तर दिया है। मैंने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि क्यों फिजिबल नहीं है। क्या सतलुज नदी का पानी सूख गया है? क्या हमारी तकनीक इतनी ख़राब हो गई है कि आजादी के 72 साल के उपरान्त भी हम पानी को न उठा सकें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह जो भेदभाव की आप बात करते हैं, यह भेदभाव वाली भावना वर्तमान सरकार में नहीं है।

जारी जे0के0 द्वारा-----

03.03.2020/1240/JK/AS /1

जल शक्ति मंत्री :-----जारी-----

जो भेदभाव की आप बात कर रहे हैं, यह भेदभाव वर्तमान सरकार में नहीं है। आपको पुरानी यादें याद आती हैं। हमें पता है कि कितने ज़ख्म हमें लगे हैं। किस प्रकार के ज़ख्म हमने सहन किए हैं। यह हमें पता है, वह आपको पता नहीं है। इस करके माननीय अध्यक्ष जी, मैं इन मित्रों को विशेषकर मुकेश अग्निहोत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं ...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब हम कन्क्लूड कर रहे हैं। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज मंत्री जी को बोलने दें ताकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आगे चर्चा हो सके। ...(व्यवधान)

जल शक्ति मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को सलाह देना चाहता हूं कि इस कुर्सी पर बहुत अच्छे-अच्छे लोग बैठे हैं और इस कुर्सी को सुशोभित किया है। लेकिन इस कुर्सी में ऐसी द्रयोगल नहीं लगी है, जो हर समय आपका उठना-बैठना लगा रहता है। आप इस कुर्सी को अपमानित कर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस कुर्सी की गरिमा बनाए रखें। इस कुर्सी की गरिमा के साथ-साथ माननीय अध्यक्ष महोदय की कुर्सी की भी गरिमा बनाए रखें।

03.03.2020/1240/JK/AS /2

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण् पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठिए। अब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आगे चर्चा होगी। आज ही चर्चा का समापन माननीय मुख्य मंत्री महोदय के भाषण से होगा इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे आबंटित समय का अवश्य ध्यान रखें। अब इस चर्चा में श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी हिस्सा लेंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पर पढ़ा, मैं उस पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 में जब श्री जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री बनें, उन्होंने यहां पर कुछ शब्द कहे थे। उन शब्दों को मैं याद करवाना चाहूंगा।

मुझे ऊंचाइयों पर देख कर हैरान हैं कुछ लोग,

पर उन्होंने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे।

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा था। जब ये मुख्य मंत्री बनें तो हिमाचल की जनता भी हैरान थी, विधायक दल भाजपा भी हैरान था। श्री जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री बनें। मैं जब अभिभाषण को देख रहा था तो अभिभाषण में ऐसा लगा कि यह सोई हुई सरकार का लिखा हुआ अभिभाषण है, इसलिए मुख्य मंत्री जी अब जागो। अब आप लोगों को भी जागने का समय आ गया है। 24 महीने से आप कुम्भकर्ण की नींद सोये हुए हैं। अभिभाषण पर चर्चा हुई तो ऐसा लगा कि संसद में बोल रहे हैं। मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, अच्छी बात है। मोदी जी देश के प्रधान मंत्री हैं। आप कांग्रेस से सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? 50 साल तक आपने राज किया और क्या किया? कांग्रेस ने 70 साल में इस देश को सबसे बड़ी ताकत दी है। इस लोकतंत्र की बुलंदियों को मज़बूत रखा है। यह इस लोकतंत्र की ताकत है। आम आदमी की आवाज़ को बुलन्द रखा है, यह इस लोकतंत्र की ताकत है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

04.03.2020/1245/SS-AS/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु क्रमागत :

आज इस लोकतंत्र की वजह से एक आम परिवार का व्यक्ति इस देश का प्रधान मंत्री बनता है। एक आम परिवार का सदस्य जो विधायक बनता है, वह प्रदेश का मुख्य मंत्री बनता है। इस सभागार में बैठे जितने लोग हैं वे विधायक बनते हैं और विधायक बनने के बाद अपने चुनाव क्षेत्र की आवाज़ को बुलन्द करते हैं। यह कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी देन

इस देश के लिए है। हमारे साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ लेकिन वहां भी लोकतंत्र कभी इतना मजबूत नहीं हुआ जो इन 72 सालों में यहां लोकतंत्र मजबूत हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यहां की लोकतंत्र की परम्परा मजबूत रहे। हमारे प्रतिपक्ष के नेता, माननीय मुकेश अग्निहोत्री ने एक बात उठाई। कोरोना एक महामारी है क्या उसमें विपक्ष चिन्तित नहीं होगा? माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी स्टेटमैंट देना चाहते हैं उनका स्वागत है। लेकिन अगर विपक्ष के नेता को भी अपनी बात रखने का अधिकार आप देते तो लोकतंत्र और मजबूत हुआ होता। क्योंकि यह महामारी कोई सत्तापक्ष से संबंधित नहीं है आम व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। लेकिन देश में तो आज कोई लोकतंत्र की बात उठाता है तो उसको देशद्रोही का दर्जा दे दिया जाता है। अगर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसे देशद्रोही का दर्जा दे दिया जाता है। अगर महंगाई की बात उठाता है तो उसे देशद्रोही का दर्जा दे दिया जाता है। अगर बेरोज़गारी की बात उठाता है तो उसे देशद्रोही का दर्जा दिया जाता है। यह लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश जो भारत सरकार कर रही है, कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में 6 वर्षों के दौरान जो हुआ है उसको कभी नहीं होने देगी। 'भारत माता की जय', यह सब लोग बोलते हैं। इस देश में 130 करोड़ नागरिक रहते हैं। 130 करोड़ नागरिक इस भारत माता की जय कहते हैं। भारत माता की जय पर केवल आपका अधिकार नहीं है। आप अपना अधिकार मानकर बैठे हैं। भारत माता की जय पर उन सपूतों का अधिकार है, उन स्वतंत्रता सेनानियों का अधिकार है जिसने इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, खून की नदियां बहाई और ये लोग आज भारत माता को अपना प्रतीक चिन्ह मानकर बैठे हैं। भारत माता हमारी भी है। हम सब लोग भारत माता का सम्मान करते हैं क्योंकि इस भारत माता की जो लोग पूजा करते हैं वे कांग्रेस के लोग और भारतवासी हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं वे भारत माता के सपूत नहीं हो सकते। आज

04.03.2020/1245/SS-AS/2

यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सदस्यों ने उठाई है। आप इसी देश के प्रधान मंत्री को याद कीजिए। आप ही की पार्टी के पूर्व प्रधान मंत्री, जिसे सत्तापक्ष और विपक्ष भी बड़े आदर व सम्मान से उनका नाम अटल जी पुकारते थे। उन्होंने गुजरात में प्रेस कॉंफ्रेंस

की। उनके साथ में मोदी जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री को अपना राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए क्योंकि गुजरात के दंगों में मुख्य मंत्री जी ने अपना राष्ट्र धर्म नहीं निभाया था। यह मैंने नहीं कहा। यह प्रधान मंत्री, वाजपेयी जी ने कहा था जिसको हम सब सम्मानपूर्वक याद करते हैं। आज देखिये देशभक्ति की परिभाषा भूल गए। आज हमसे देश भक्ति के बारे में सवाल करते हैं। देशभक्ति हमारे खून में है। देश भक्ति और इस देश की एकता व अखण्डता के लिए हमने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बता दीजिए जिसने इस देश की एकता और अखण्डता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया हो।

जारी श्रीमती के0एस0

04.03.2020/1250/केएस/डीसी/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जारी---

जिस तरह आप समाज को बांट रहे हैं, बलिदान हम करते हैं, देश को हम बनाते हैं और आप हमसे सवाल करते हैं कि आपने 70 साल में क्या किया? ...(व्यवधान) 70 साल में इस देश की आजादी के बाद जिस देश में सूई तक नहीं बनती थी, सूई से ले कर जिस मंगल ग्रह की यात्रा की माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने, अमेरीका में भाषण में कहा था, सूई से ले कर मंगलयान की यात्रा का सफ़र कांग्रेस पार्टी की नीतियों द्वारा, कार्यक्रमों द्वारा तय किया गया। ...(व्यवधान) यह सच्चाई है और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है।

अध्यक्ष महोदय, आज 6 साल से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी इस देश में राज कर रहे हैं। हमने संस्थाएं मज़बूत की। उन संस्थाओं में जहां आम नागरिक के अधिकार सुरक्षित हो, आपके अधिकार सुरक्षित हो। हमने आर.बी.आई. को मज़बूत किया, इलैक्शन कमीशन को मज़बूत किया, ज्यूडिशरी को मज़बूत किया, आम आदमी के अधिकार को मज़बूत किया लेकिन 6 साल में आजादी के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चार जज निकलते हैं और कहते हैं कि हमारी कार्य-प्रणाली में हस्तक्षेप किया जा रहा है। यह पहली बार हुआ। हमारी सरकार के 70 सालों के समय में किसी ने भी अंगुली उठाकर नहीं कहा कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसी तरह से जो प्रैस आम आदमी की आवाज, आम आदमी की पीड़ा और दर्द की आवाज उठाता है, उसको कुचलने की कोशिश पिछले 6

साल में हुई है। आर.बी.आई. के गवर्नर, एक लगा, दो लगा, तीन लगा, तीनों इस्तीफा दे कर चले गए। इलैक्शन कमिशन वाले दुखी हो गए और एक ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये सब चीज़ें जो पिछले 6 सालों में घटित हुई, 70 साल में नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप 6 मार्च, 2020 को बजट देने जा रहे हैं। राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, ठीक है यह आपने सो-सो कर लिख दिया ---(***)--- रूटीन में इस भाषण में अपनी बात लिखते हैं। ...(व्यवधान) अब मैं डिपार्टमैंट वाइज़ मंत्रियों की बात बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले बेरोज़गारी की बात करना चाहूंगा। ...(व्यवधान

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

04.03.2020/1250/केएस/डीसी/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बैठें। माननीय कृषि मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं।

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा ---(***)---इसके लिए या तो ये क्षमा मांगे या अपने शब्द वापिस लें। इन्होंने बहुत गलत शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब क्या है कि मस्त होते हैं? यह इन्होंने बहुत गलत शब्द कहा है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, क्या आप अपने शब्द वापिस लेते हैं?

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मुझे इसका गलत मतलब समझा दें कि क्या मतलब है ---(***)---? ...(व्यवधान) गलत बात बता दें। बताएं कि इसका गलत मतलब क्या है? पांच बजे के बाद छुट्टी हो जाती है। ...(व्यवधान) मैं इलेबरेट कर दूं, सही मतलब कर दूं?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप चर्चा में हिस्सा लें परन्तु माननीय कृषि मंत्री जी और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी कह रहे हैं, क्या इन शब्दों को आप वापिस लेते हैं?

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, मैंने अच्छे शब्द बोलें हैं, मैं क्यों वापिस लूंगा?

अध्यक्षः नहीं, आप बेवजह इसका इशू न बनाएं।

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी...

04.03.2020/1255/av-dc/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको इसका मतलब समझा देता हूं और अगर इनको कहीं गलत लगेगा तो फिर आपने बोलना।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो अभी कहा है यह निंदनीय है तथा इनको अपने ये शब्द वापिस लेने चाहिए। ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि इनको अपने कार्यकाल की याद आ रही है और ये अपने कार्यकाल की बात दोहरा रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो '---(***)---' शब्द का इस्तेमाल किया है इसके कई अर्थ निकलते हैं। ...(व्यवधान) नहीं, मैं आपके अधिकारों का संरक्षण करूंगा परंतु आप अपने शब्दों को वापिस ले लीजिए। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, क्या आप अपने शब्दों को वापिस लेते हैं? ...(व्यवधान) आपको अपनी बात रखने के लिए समय दिया गया है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इस अभिभाषण में अगर किसी को ---(***)---शब्द से पीड़ा हो रही है तो मैं आपको उसका मतलब समझा देता हूं।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस शब्द से सत्ता पक्ष में बैठे सभी माननीय सदस्यों को आपत्ति है। ---(***)---' आपको इसका संदर्भ समझाने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इन शब्दों को या तो वापिस लिया जाए या कार्यवाही से एक्सपंज किया जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपने ये शब्द वापिस लेते हैं?

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर यह कह देता हूं कि ---(***)--- अब क्या ये शब्द भी वापिस ले लूं?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह पूछ रहा हूं कि आप अपने शब्द वापिस लेते हैं या नहीं?

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

04.03.2020/1255/av-dc/2

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने ये शब्द वापिस लेता हूं।

अध्यक्ष : आप आगे बोलिए और समय का ध्यान रखें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह कहता हूं कि सूर्यास्त और मंत्री त्रस्त; यह तो ठीक है न? (सत्ता पक्ष की और इशारा करते हुए कहा।) ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रकार के शब्द असंसदीय हैं और इन शब्दों को एक्सपंज किया जाए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, मेरा मकसद किसी पर गलत टिप्पणी करना नहीं है इसलिए मैं इसको इलेबोरेट करना चाह रहा था परंतु आपने मौका नहीं दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी, हिमाचल प्रदेश में रोज़गार एक बड़ा साधन है और सरकारी रोज़गार एक उससे भी बड़ा साधन है। हिमाचल प्रदेश की इम्प्लॉयमैंट एक्सचेंजिज में अभी लगभग 9.11 लाख बेरोज़गार युवक नौकरी की कतार में खड़े हैं। उनमें से 75000 पोस्ट ग्रेजुएट, 135000 ग्रेजुएट, 6.15 लाख दसवीं पास, 40000 अंडर मैट्रिक तथा 500 अशिक्षित हैं। वर्ष 2012-13 में जब हमारी सरकार आई थी तो बेरोज़गारों की संख्या 9 लाख के करीब थी और हमने अपने कार्यकाल में बेरोज़गारी को दूर किया। बेरोज़गारी को दूर किया और उसकी संख्या घटकर 7.11 लाख रह गई। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलते रहिए क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के दो वर्षों के कार्यकाल में अगर आंकड़े 5-10 हजार ऊपर-नीचे हो जाए तो अलग बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने अभी अपना भाषण देना है तो वर्ष 2018-19 में यह आंकड़ा बढ़कर 8.66 लाख हो गया।

टी सी द्वारा जारी

04.03.2020/1300/TCV/HK-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु.. ....जारी

अब 60,000 के करीब और बेरोज़गार युवक नौकरी की लाइन में लग गये। आपने पहले घोषणा-पत्र में कहा कि 02 करोड़ लोगों को भारत सरकार में रोज़गार मिलेगा। (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, अभी 10 मिनट हुए है। आपने उनको 40 मिनट दिये हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, हमने सभी को बराबर का समय दिया है और भोजनावकाश का समय भी हो रहा है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : आप समय एक्सटैंड कर लें, आपसे बात हुई है। 20 मिनट बोलने का तो हमारा भी अधिकार है, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात रखें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : आपका जो दृष्टि पत्र था, आपने उसमें कहा था कि आप 02 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे लेकिन पिछले 05 साल में रोज़गार देने के बज़ाय 3.67 करोड़ लोगों के रोज़गार विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा छीन लिए गये। वर्ष 2015-16 के बाद सरकार ने रोज़गार के 3 सालों के आंकड़े ही नहीं दिए हैं। यह सरकार रोज़गार

नहीं दे पा रही है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी जो बजट आने वाला है, उसमें रोज़गार के अवसर पैदा कीजिए। आपकी सरकार में जो अवसर मिल रहे हैं, उनमें पिछले 2 सालों से घोटाले ही हो रहे हैं। 'अमर उजाला' में पटवारी की भर्ती से संबंधित ख़बर छपी कि लगभग 3 लाख अभ्यर्थी पटवारी की परीक्षा में बैठे और मंत्रियों में होड़ लग गई कि मेरे इतने पटवारी लगने चाहिए। गलत काम करवाया गया और आज सी0बी0आई की इंक्वायरी हो रही है और उच्च न्यायालय के माध्यम से हो रही है। 3 लाख लोग पटवारी की भर्ती में बैठे थे। इन 2 सालों में फ़र्जी डिग्री स्कैम हुआ, क्या आपकी सरकार सोई हुई है। स्कॉलरशिप स्कैम हो रहा है और यह सरकार सोई हुई है। मुख्य मंत्री जी, जाग जाओ।

04.03.2020/1300/TCV/HK-2

...(व्यवधान) किस वर्ग को आपने राहत दी है। सरकारी कर्मचारी जो प्रदेश की रीड की हड्डी होते हैं। आज प्रदेश आर्थिक रूप से मज़बूत हुआ है तो उसमें सरकार कर्मचारी व अधिकारियों को बहुत बड़ा भाग है क्योंकि वे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं और जब वह पढ़-लिखकर अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं तो उनको रोज़गार नहीं मिलता है। उसको निजी क्षेत्र में भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। सरकारी कर्मचारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर हिमाचल प्रदेश पूरे देश में पहले नम्बर पर आया है तो उसमें सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका बहुत अधिक रही है। उन्होंने छोटे-से गांव में जाकर लोगों को प्रेरित किया कि आप पढ़ो, आपको रोज़गार मिलेगा लेकिन रोज़गार के अवसर देने में हिमाचल प्रदेश की सरकार नाकाम रही है। हर बार आप सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को डी0ए0 के रूप में छोटा-सा टुकड़ा दे देते हैं। क्यों नहीं छट्ठा वेतन आयोग इस प्रदेश में लागू किया गया, कितने सालों से सरकारी कर्मचारी व अधिकारी इसका इंतजार कर रहे हैं। ...(व्यवधान) हम स्वीकार करते हैं, हमने गलती की और हम विपक्ष में आ गये। ...(व्यवधान) यही नहीं, हमें एक बार मौका मिलना चाहिए, इनको ओल्ड पेंशन भी हम लागू करेंगे, यह हमारे राष्ट्रीय नेता राजीव गांधी ने कहा है। हमारे प्रैस वाले बंन्धु है, इनके बारे में सोचिए ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वाइंड अप करे। आप चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं इसलिए चेयर को अड्रैस करे।...(व्यवधान) माननीय सदस्य, वाइंड अप करे।

श्री सुक्खु जी एन0एस0 द्वारा .... जारी ।

04-03-2020/1305/NS/HK/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण सोई हुई सरकार ने लिखा है। तभी मैं इस पर बोल रहा हूं कि कर्मचारियों, प्रैस वालों के लिए कुछ नहीं किया गया है। यही नहीं, शिमला शहर के लिए हमारी सरकार ने सितम्बर, 2016 में रिटैंशन पॉलिसी लाई। कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। अब मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार दो साल से सोई हुई नहीं है? माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी आप जागिए। आपकी भारत सरकार ने दिल्ली में हरदीप पुरी जी मंत्री हैं और उन्होंने अवैध कॉलोनियां और अवैध कब्जों को भी नियमित कर दिया है। आप उस नियम को पढ़िए। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम कानून बनाते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी एक उम्मीद रखता है कि उसका शिमला में घर हो। उसने कोई अवैध कार्य नहीं किया है। उसने अपने मकान की एक मंजिल और बढ़ा ली यह सोच कर कि मुझे चार पैसे किराये के रूप में मिलेंगे और उन चार पैसों से मैं अपने बच्चों का गुज़ारा करूंगा जिसको रोज़गार नहीं मिला है और वह बेरोज़गार है। रिटैंशन पॉलिसी लागू कर दी। क्या हम दोबारा यह कानून नहीं बना सकते? इस कानून की धारा के तहत आर्टिकल 14 का हवाला देकर सैक्शन 30 का हवाला दिया गया है। यह तो रिटैंशन है और यह अपनी जगह है। किसी ने अपना मकान बनाया हुआ है और अगर एक मंजिल ज्यादा बना दी तो कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में दोबारा से कानून लाया जाए और कई गरीब लोगों, कर्मचारी वर्ग के लोगों ने तीन मंजिल से एक मंजिल अधिक बनाई है और अगर सरकार इस माननीय सदन में उसका नियमितीकरण करने के लिए कोई कानून लाती है तो हम आपका इस संदर्भ में पूरा समर्थन करेंगे। क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक और बात आम जनता से संबंधित है जो इस अभिभाषण में नहीं है और वह एन0जी0टी0 के बारे में है। सरकार प्रूडैंटली अगर इसके बारे में विचार करे तो एन0जी0टी0 की कार्यप्रणाली सिर्फ पानी और पर्यावरण से संबंधित है और यही इसके क्षेत्राधिकार में हैं। इसमें लिखा गया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय महेन्द्र सिंह ठाकुर जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि अब अढ़ाई मंजिल ही बनेगी। वे कौन-से स्ट्रक्चर डिजाईनिंग करते हैं, वे कौन-सी लोड बीयरिंग कैपेस्टिी देखते हैं? पूछना यह चाहिए कि यहां पर पानी और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और उस पर स्टे होना चाहिए। इस मामले में एन0जी0टी0 ने कह दिया कि अढ़ाई मंजिल से ऊपर नहीं बनेगी। आप इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखिए, लोड बीयरिंग कैपेस्टिी देखिए।

04-03-2020/1305/NS/HK/2

हिमाचल प्रदेश सचिवालय, एडवांस स्टडी और रेलवे बोर्ड बिल्डिंग आठ मंजिलों के बने हुए हैं। ऐसा क्यों है? अध्यक्ष महोदय, ये भवन आज़ादी के पहले के बने हुए हैं। मैं यह बात आपके ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय की बिल्डिंग 13 मंजिल की बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश की लोड बीयरिंग कैपेस्टिी अन्य राज्यों से बहुत है। हमारी लोड बीयरिंग कैपेस्टिी दिल्ली से भी ज्यादा है। आप क्यों नहीं दस मंजिलें खड़ी करने की परमिशन देते हैं? होरिजंटल शोधी से ले करके मशोबरा तक दो व तीन मंजिलों के घर बना दिए गए हैं। जब टैक्नोलॉज़ी नहीं थी तब हमारी आठ मंजिला धज्जी दीवार पर सचिवालय की बिल्डिंग बनी हुई है।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

04.03.2020/1310/RKS/YK-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु... जारी

आने वाले समय में एन.जी. टी. के ऑर्डरों को दरकिनार करके यहां कानून लाया जाए ताकि इससे लाखों लोगों को राहत मिले और प्रदेश की ग्रीनरी भी बचे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपका विषय आ गया है, कृपया वाइंड-अप करें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : माननीय अध्यक्ष जी, ---(***)--- मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आजकल पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू हो रहे हैं। मुझे कल कुछ बच्चे मिले उन्होंने कहा कि अब हिंदी में इंटरव्यू नहीं होंगे। अब हमें इंग्लिश में इंटरव्यू देना होगा। इसका क्या मकसद है? हमारी राष्ट्र भाषा हिंदी है। मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, हिंदी सब जगह लागू की जा रही है और आप कह रहे हैं कि इंग्लिश में इंटरव्यू होंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी आपको इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने कल Motor Vehicle Act के संबंध में एक प्रश्न किया था। आपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमने इस एक्ट को लागू कर दिया है। यानी जो एक्ट के तहत पैनल्टी की धाराएं हैं, वे भी ऑटोमैटिकली लागू होंगी। मैं यह बता रहा हूं कि पार्शल एक्ट कभी लागू नहीं होता है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड-अप करें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष जी, जो नया Motor Vehicle Act बना है, वह इस प्रदेश में लागू हो गया है। प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि हम इसकी धारा-280 की अनुपालना पर विचार कर रहे हैं। जो आपने पैनल्टी कम की है उसके बारे में सदन को अवगत करवाया जाए अन्यथा इस पर हाई कोर्ट में रिट होगी। माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली जाते हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मिलते रहते हैं जो कि अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके ध्यान में कुछ चीजें लाना चाहता हूं। नदौन में Spices Board के लिए 17 करोड़ रुपये Spices Board of India ने स्वीकृत किये हैं और जिसका उदघाटन भी हो चुका है।

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

04.03.2020/1310/RKS/YK-2

यह बोर्ड Ministry of Commerce and Industry, Government of India के अधीन आता है। आप इस पर थोड़ा गौर कीजिए। IIFT(Indian Institute of Foreign Trade) में एम.बी.ए. के बाद फोरन की एम.बी.ए. होती है। हमने उसकी एक ब्रांच यहां खुलवाई थी। लेकिन भारत सरकार इसे अबंडन करने की कोशिश कर रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी

IIFT(Indian Institute of Foreign Trade) में विदेशी विद्यार्थियों और हमारे छात्रों को एक्सपोजर का मौका मिलेगा। इसमें गारंटिड रोजगार है और कैम्पस इंटरव्यू से ही छात्रों का चयन कर लिया जाता है।

जल शक्ति मंत्रालय पैसे लाने का कार्य जरूर कर रहा है। वैसे तो जल शक्ति मंत्रालय ने माननीय मुकेश जी की सभी बातों का जवाब दे दिया लेकिन किस निर्वाचन क्षेत्र में कितना पैसा दिया जाएगा वह हम आने वाले समय में बताएंगे। अगर आप पैसा देंगे तो हम कहेंगे कि आपने पैसा दिया और नहीं देंगे तो हम कहेंगे कि आपने पैसा नहीं दिया।

आप बजट में विधायकों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों, प्रैस, और समस्त जनता का ध्यान रखिए। कल माननीय डॉ. राजीव बिन्दल जी बड़े आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे। वे कह रहे थे कि स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट्स में 90:10 का शेयर है।...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य मुझे बार-बार कहना ठीक नहीं लग रहा है, कृपया आप वाइंड-अप करें।

04.03.2020/1310/RKS/YK-3

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय मुख्य मंत्री जी, स्मार्ट सिटी में 90:10 का शेयर नहीं है। इसमें प्रदेश सरकार को 50 प्रतिशत शेयर देना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सोल्यूशन्ज होने चाहिए लेकिन म्यूनिसिपल कोर्पोरेशन, शिमला में अभी तक ऑनलाइन नक्शे सब्मिट होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। आपके दो साल पहले के रोपवेज प्रोजैक्ट्स पैंडिंग पड़े हुए हैं। जो एम.ओ.यू. साइन हुए हैं उनमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। एम.ओ.यू. साइन होना अच्छी बात है। इसमें कुछ पैसा आएगा और हम आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन क्या यह कोई धोखा तो नहीं है?

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

04.03.2020/1315/बी.एस./वाई.के./-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जारी...

यहां जो अधिकारी बैठे हैं, कहीं ये हवा में सपनें तो नहीं बेच रहे हैं और आने वाले चार साल बाद हम आपके बजट की कापी लेकर आएं और कहें कि एम.ओ.यू. के माध्यम से कुछ नहीं हुआ। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप जवाबदेही तय करिए तभी इस प्रदेश का भला हो सकता है। सत्ता भले ही बदले परंतु हमें इस प्रदेश के भले की सोचनी चाहिए। बेरोजगारी बाहें फैलाए सड़कों पर खड़ी है। तीन-तीन लाख युवा इन्टरव्यू के लिए एक साथ आ रहे हैं। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम आपसे आशा करते हैं कि छह तारीख को जब आप बजट पेश करेंगे उस बजट में सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, महिलाएं, युवावर्ग और सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए लोगों की आशाओं के अनुरूप खरे उतरेंगे। आपने यहां कहा था कि हमारा ईमानदार प्रयास रहेगा उस ईमानदार प्रयास की आशा आपके छह तारीख के बजट से होगी, धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जब चर्चा में भाग ले रहे थे तो आपने मंत्रियों के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं, वे टिप्पणियां असंसदीय थीं।...(व्यवधान) कृपया चेयर की भी सुन लिया करो। आपने कहा कि "अच्छी बातें सुनने में कोई ---(***)--- नहीं होना चाहिए" इस ---(***)--- का क्या अभिप्राय है? आप इस माननीय सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। अतः इन शब्दों को मैं कार्यवाही से एक्सपंज करता हूं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : माननीय अध्यक्ष महोदय, ---(***)--- शब्द को तकलीफ में बदलने की कृपा करें। मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं।

"कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा,

तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा"

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोवकाश हेतु 02.15 बजे अपराह्न तक स्थगिम की जाती है

--(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया

श्री डी.टी.द्वारा जारी...

04.03.2020.1420.डी.टी/ए.जी/-1

माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 14.20 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री सुख राम जी चर्चा में हिस्सा लेंगे।

श्री सुख राम (पांवटा साहिब) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो 25 फरवरी, 2020 को माननीय सदन में अभिभाषण दिया, मैं उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हिमाचल प्रदेश में लगभग पिछले सवा दो वर्ष से आदरणीय जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यरत है। इन दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो जनहित के काम किए हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। "हिमाचल गृहणी सुविधा योजना" में 1,74,514 महिलाओं को गैस उपलब्ध करवाई गई है और इसके अतिरिक्त महत्वकांक्षी योजना जनमंच है। अब तक 179 जनमंच हुए जिसमें 45,708 समस्याएं आईं और 41,658 का समाधान उन जनमंचों में किया गया। हिमाचल प्रदेश में जो बुजुर्ग हैं उनकी पैशन की आयु 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की गई। लाखों लोगों को इसका लाभ हुआ है। इसकी राशि बढ़ा करके 1500 रुपये कर दी गई है। "मुख्य मंत्री रोशनी योजना" के तहत जिन गरीब परिवारों को आज भी बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, आई.आर.डी.पी. परिवार जिनकी आय 35 हजार से कम हैं उनको बिजली का कनैक्शन दिया गया। इस दौरान मजदूरों की मजदूरी है को 210 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए की गई। पूर्व की सराकर की यदि बात करुं तो उन्होंने 5 वर्ष में 175 रुपये से बढ़ाकर 210 रुपए की थी। 35 रुपए पांच वर्ष में बढ़ाई थी। "आयुष्मान भारत योजना" केन्द्र की योजना थी। हिमाचल प्रदेश की जनता को इससे 49 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। "हिमकेयर योजना"से हिमाचल प्रदेश के लोगों को 98 करोड़ रुपए का लाभ मिला। "प्रधानमंत्री किसान निधि योजना" 597 करोड़ रुपए की है और इससे हिमाचल प्रदेश के किसानों को भी लाभ मिलेगा। बिजली, सिंचाई, ट्यूबवैलों में पूर्व की सरकार ने 50 पैसे से एक रुपये की वृद्धि की थी। आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने पुनः किसानों को राहत देने का काम किया और उसे फिर से 50 पैसे कर दिया है। उसका परिणाम यह हुआ कि जब लोक सभा का चुनाव हुआ जनता ने हमारी सरकार पर विश्वास

प्रकट किया और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। 68 में से 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली। इसके बाद दो उप चुनाव हुए दोनों में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई। यहां तक कि धर्मशाला में कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत ही जब्त हुई। ये किसी सरकार की लोकप्रियता का मापदंड है कि जो वर्तमान में

04.03.2020.1420.डी.टी/ए.जी/-2

सरकार है उसकी लोकप्रियता कितनी है। "जल-जीवन मिशन" अभी शुरू हुआ है और इसमें 2,896 स्कीमें स्वीकृत हुई हैं। प्रदेश की सरकार ने हर परिवार की रसोई में नल लगाकर देना है। केन्द्र सरकार की यह स्कीम है। "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के बारे में मैं कहना चाहता हूं। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह योजना चलाई थी। अगर हिमाचल प्रदेश में यह योजना नहीं होती तो हिमाचल प्रदेश की सड़कें जिस रफतार से बन रही हैं तो शायद 70 वर्ष और सड़कें बनाने के लिए लग जाते।

श्री एन.जी द्वारा जारी

04-03-2020/1425/ए.जी.-एन.जी./1

श्री सुख राम जारी...

मैं जिला सिरमौर की बात करना चाहता हूं। पिछले 2 वर्षों में जिला सिरमौर के शिलाई में जल शक्ति विभाग का डिवीज़न खुला, सराहां में सब-डिवीज़न खुला, लोक निर्माण विभाग का उप-मण्डल नौहराधार-बोगधार में खुला, जल शक्ति विभाग का सब-डिवीज़न ददाहू में व पांवटा साहिब में खुला, इलैक्ट्रीकल का सब-डिवीज़न पांवटा साहिब में खुला और पांवटा साहिब के अस्पताल को 100 से 150 बिस्तरों का दर्जा दिया गया, शिलाई के अस्पताल को 50 से 100, राजगढ़ के अस्पताल को 50 से 100, सराहां के अस्पताल को 50 बिस्तरों का दर्जा दिया गया। जिला सिरमौर में 4 आई.टी.आई. और 10 पी.एच.सी. नई खोली गई। किसी सरकार की लोकप्रियता का मापदण्ड होता है कि चुनाव या उप-चुनाव में वह जीत हासिल करे और दोनों चुनावों में हमारी सरकार खरी उतरी है। हमारे विपक्ष के मित्र भ्रष्टाचार की बहुत बातें करते हैं और जब ये सत्ता में होते हैं तब ये इतना भ्रष्टाचार

करते हैं कि उसकी सीमाएं लांघ जाते हैं। भ्रष्टाचार करने में इनकी कोई सीमा नहीं होती जिसे मैं 2 उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। दिनांक 17-12-2014 को श्री रेणुकाजी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नैहरवार स्कूल में एक language teacher (L.T.) का इन्टरव्यू हुआ। उसमें कुमारी सन्तोष पुत्री श्री सदानंद को 10 में से 0.83 नम्बर दिए गए और दूसरे कैंडिडेट पारूल पुण्डीर को 10 में से 9.33 नम्बर दिए गए। यानि के उसे एक नम्बर भी नहीं दिया गया और उसकी सलैक्शन कर दी गई। फिर वे कोर्ट में गए और वहां पर उन्हें राहत मिली। इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 27-04-2017 को एक ड्राइवर का इन्टरव्यू हुआ था उसमें एक कैंडिडेट को 10 में से 1.5 नम्बर दिए और दूसरे कैंडिडेट को 10 में से 9.85 नम्बर दिए गए। एक कैंडिडेट के कुल नम्बर 74.7 बने और जिसकी सलैक्शन हुई उसके कुल नम्बर 74.8 बने। यानि के सारी सीमाओं को लांघ कर ये अपने लोगों को बैनेफिट देते थे। जब ये लोग विपक्ष में जा कर बैठ जाते हैं तो इन्हें बड़ा-बड़ा भ्रष्टाचार याद आता है और उसकी दुहाइयां देते हैं।

04-03-2020/1425/ए.जी.-एन.जी./2

पिछले कल इन्होंने खनन पर बहुत कुछ बोला कि हिमाचल प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार है और यहां अवैध खनन हो रहा है। मैं इनकी सरकार के समय की बात बताना चाहता हूं कि जिस भी स्टोन क्रशर की लीज़ का टाइम खत्तम हो जाता था तो उद्योग मंत्री जी उन्हें फिश पौंड बनाने की अनुमती देते थे और वे फिश पौंड जे.सी.बी. से बनाए जाते थे फिर उनका मैटीरियल स्टोन क्रशर में उपयोग किया जाता था। हमारे उद्योग मंत्री जी भी यहां है और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि फिश पौंड बनाने की अनुमती देनी ...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः वह पोलिसी आपके समय में लाई गई थी।

श्री सुख रामः मैं पोलिसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो आपके समय की बात बताना चाहता हूं कि आपने अपने समय में क्या किया। यदि उस पोलिसी को हम लाए थे तो जब हम विपक्ष में बैठ गए थे और आप सत्ता में आ गए थे तब आपने उस पोलिसी में परिवर्तन

क्यों नहीं किए? आपने हिमाचल प्रदेश में सैंकड़ो लोगों को अनुमती दी, आपने नदियों को जे.सी.बी. से खोदने की अनुमती दी।...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः बिलकुल नहीं दी।

श्री सुख रामः मैं कह रहा हूं कि आपने अनुमती दी और यदि नहीं दी तो बताइए कि फिश पौंड किस चीज़ से बनता है, बेलचों से बनता है क्या? मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कहां-कहां फिश पौंड बने? उसमें मछली पालन का कितना उद्योग हुआ और कितनी मछलियां बाहर सप्लाई की गई या नम्बर 2 का धंधा आपनाने का प्रयास किया गया।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

04/03/2020/1430/MS/As/1

श्री सुख राम जारी---

मैं मुख्य मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि पिछले 7 साल में कहां-कहां कितने-कितने फिश पौंड बने और उनसे कितना बिजनैस या राजस्व हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिला, उसके ज़रा आंकड़े तो यहां पर रखो क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि कितने फिश पौंड बने। गर्मियों और सर्दियों में फिश पौंड के माध्यम से अंधाधुन्ध माइनिंग होती रही। बरसात में वे सारे फिश पौंड भर जाते थे और उसके बाद फिर परमिशन मिल जाती थी। यह धन्धा एक साल नहीं चला बल्कि लगातार पांच साल तक चलता रहा। जब ये विपक्ष में बैठ गए तो आजकल इनको हिमाचल प्रदेश की बड़ी चिन्ता है कि यहां पोस्टें खाली पड़ी हैं और शिक्षा विभाग में भर्तियां नहीं हो रही हैं। क्योंकि आपकी सरकार चार साल तक तो सोई रहती है और जब चुनाव का पांचवा साल शुरू होता है फिर आप मुख्य मंत्री जी को लेकर फील्ड में जाते हैं। वहां लोग प्राइमरी स्कूल की मांग करते हैं और आप मिडल स्कूल देते हो। अगर मिडल स्कूल की बात करते हैं तो आप जमा-दो का स्कूल देते हो। जहां जमा-दो की मांग होती है वहां कॉलेज दे देते हो। जहां पटवार सर्कल की बात होती है वहां सब-तहसील दे देते हो और जहां सब-तहसील की बात होती है वहां तहसील दे देते हो। ...(व्यवधान) बन्द करने की बात नहीं है लेकिन बिना बजट दे देते थे। वर्ष 2017

के अंत में चुनाव आ जाता है और अक्तूबर में कॉलेज खोल देते हो और कॉलेज भी दुकानों और गौशालाओं में खोलते हो। जमा-दो का स्कूल दो-दो कमरों में खोल देते हो और इसी तरह से कॉलेज भी खोल देते हो। यानी जितना काम आप चार साल में नहीं करते, उससे दस गुणा काम चुनाव के अंतिम समय में आपको करने की याद आती है।

जो शिक्षा का बेड़ा गर्क किया है वह आप लोगों ने किया है क्योंकि आप लोगों को समय पर याद नहीं आती। आप लोग यह नहीं देखते कि इसका बजट में प्रावधान है या नहीं या उसके लिए बजट में कितना प्रावधान रखा है। आप डैपुटेशन में स्टाफ भेज देते हैं जिससे न एक स्कूल चलता है न दूसरा चलता है। न एक कॉलेज चलता है न दूसरा कॉलेज चलता है। वहां पर न बिल्डिंग होती है और न ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। अगर हिमाचल प्रदेश में अच्छी शिक्षा का स्तर गिरा है तो उसके लिए 90 प्रतिशत आप लोग दोषी हैं क्योंकि आप लोगों का कोई सिस्टम नहीं है। मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में यहां तक देखा कि मुख्य मंत्री जी भाषण देकर बैठ गए लेकिन इनकी चार

04/03/2020/1430/MS/As/2

मांगे रह गई तो फिर मुख्य मंत्री को खड़ा कर लेना और कान में बोलना कि सर ये दो काम तो अधूरे रह गए थे, इनकी भी घोषणा कर दो और मुख्य मंत्री ने भी प्राइमरी स्कूल की जगह हाई स्कूल दे देना। इसलिए जब प्रदेश में सिस्टम से काम नहीं होता है तो इस तरह के हालात प्रदेश में होते हैं।

यहां माननीय सदस्य हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि स्कूल खाली पड़े हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि स्कूल खाली हैं लेकिन वे स्कूल क्यों खाली हैं? ...(व्यवधान) मैं नहीं छेड़ रहा हूं। मैं आपकी बात कह रहा हूं। मैं सिरमौर के बारे में आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान) मैं समर्थन कर रहा हूं कि स्कूल खाली हैं। ...(व्यवधान) आप लोगों ने क्या किया कि एस0एम0सी0 में भर्ती की, जिसका मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया है। एक को 8.83 नम्बर दिए और एक को 9.83 दिए। फिर प्वाइंट वन प्रतिशत से उसकी सलैक्शन करनी। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बैकडोर से भर्ती करने का धन्धा जिला सिरमौर में चला रखा था। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आपने शिक्षा का भट्ठा बिठा दिया। उन पदों को भरने का क्राइटेरिया क्या रखा गया? यहां तक हुआ, मैं छछेती स्कूल का उदाहरण आपको देना चाहता हूं जो कि विनय कुमार जी का चुनाव क्षेत्र है। एक लड़का ड्राइंग मास्टर की ट्रेनिंग कर रहा था इसलिए दो साल तक वहां पोस्ट नहीं भरी। वह इसलिए नहीं भरी कि

जब हमारा बच्चा ट्रेनिंग करके आएगा तब उसको स्कूल में लगाएंगे। वह पद दो वर्ष तक खाली रखा। बाद में एस0एम0सी0 के माध्यम से उस स्कूल में पद भरा गया। पैरा टीचर और पी0टी0ए0 से सारे पद चाहे जमा-दो स्कूल हो या हाई स्कूल हो, सभी जगह भरे गए और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होती है कि जब वे एस0एम0सी0 से पद भरे जाते हैं और पी0टी0ए0 पर भरे जाते हैं तो उनकी अपने घर में सर्विस करने की तबीयत नहीं करती। उनको पावंटा या नाहन चाहिए। अधिकतर टीचर पी0टी0ए0 की पॉलिसी के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर पावंटा में सर्विस करेंगे, अपने घर में सर्विस नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने पावंटा में अपने बच्चे पढ़ाने हैं। उनको अपने बच्चे पढ़ाने की चिन्ता हो जाती है। पावंटा के लोग जाकर शिलाई, रेणुका और पच्छाद में बच्चों को पढ़ाएंगे और पच्छाद वाले शिलाई, पावंटा और नाहन में राजनीतिक प्रभाव के कारण सर्विस कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी में उनको छूट देनी और अच्छे स्कूल देने और जब हमने पता करना कि क्यों भर रहे

04/03/2020/1430/MS/As/3

हैं तो कहा जाता है कि वहां अच्छे स्कूल नहीं हैं इसलिए इनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में एजुकेशन देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सारी बैकडोर एंट्रीज हैं। पॉलिसी में होना चाहिए था कि जिस स्कूल में आप भर्ती हुए हैं उसी स्कूल में आप 15 वर्ष तक सर्विस करेंगे। आप चार साल के बाद उनको नीचे के क्षेत्र में लगा देते हो। आपने तो यहां तक रिकॉर्ड बनाया, मैं आपको बता देता हूं। आपने यहां छः बार के जीते हुए मंत्री जो कि विधान सभा के स्पीकर भी रहे, उन्होंने पिछली से पिछली बार जब आपकी सरकार थी, यह रिकॉर्ड में है कि प्रवक्ता की दो पोस्टें खाली करवाईं। उसी दिन यहां से ऑर्डर हुए। उसी दिन उन दोनों को रिलीव किया गया।

जारी जे0के0 द्वारा-----

03.03.2020/1435/JK/AS /1

श्री सुख राम जारी---

उसी दिन इन्टरव्यू रखे गए। उन दोनों बच्चों ने दोनों स्कूलों में इन्टरव्यू दिए और उसी दिन आप लोगों ने एस.एम.सी. पर भर्ती कर दी। उनकी भर्ती आपने इसलिए की, उनकी ट्रांसफर इसलिए की और आपने इंतजार भी नहीं किया। उसी दिन ट्रांसफर, उसी दिन

रिलीविंग, उसी दिन इन्टरव्यू और उसी दिन उन दोनों की भर्ती। यानि कि आप इतनी अच्छी योजना से काम करते हैं। मैं इस माननीय सदन में उसका कागज ले कर सकता हूं। ऐसा है, यदि चुटकी से काम करना है तो तभी शिक्षा विभाग का बेड़ागर्क होता है और आपका ही यह सारा कुछ धन्धा है। आप इतनी राजनीतिक द्वेश की भावना से हिमाचल के जिला सिरमौर में काम करते थे। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नम्बर दो का व्यक्ति समझते थे। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति की पोस्टिंग न हो जाए, पहले डायरैक्टर को बोल के रखो, बी.डी.ओ को बोल के रखो, कितने दिन में पोस्ट निकलनी है, मैंने आपको उदाहरण दिया । आपने एक को .83 नम्बर दिए और दूसरे को 9.83 नम्बर दिए, यह रिकॉर्ड में अंकित है। इस तरीके से जिला सिरमौर में आपने भर्ती की है। मैरिट कहां है, मैरिट तो आपने दर-किनार कर दी। आपने तो क्राइटेरिया भी दर-किनार कर दिया। आपने कोई नियम-कानून रखा ही नहीं। आज हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन का जो स्तर गिर रहा है, वह इसी कारण गिर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, फिश पौंड की बात मैंने पहले ही आपसे कर दी । मुकेश अग्निहोत्री जी को खनन की बड़ी चिन्ता हो गई है। मैं यहां पर एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन नदियां हैं। उसमें 69 छोटे-छोटे नदी-नाले हैं। यहां पर विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं और मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें 95 परसेंट लोगों की जमीन है। बरसात में जंगल से पानी आता है। माइनिंग में आपने बिल्कुल बैन लगा दिया। जब बरसात ज्यादा होती है तो लोगों

03.03.2020/1435/JK/AS /2

के घरों में भी पानी भर जाता है और 5-10 बीघा जमीन लोगों की नदी-नालों से बह जाती है। अगर वह किसान अपनी जमीन से मिट्टी उठा कर प्लेन करना चाहता है तो माइनिंग वाले खड़े हो जाते हैं। अपनी जमीन से मिट्टी उठा करके भी प्लेन नहीं कर सकते। उनको कहा जाता है कि इसमें तो माइनिंग एक्ट लग गया है और आपकी तो गाड़ी भी अन्दर हो जाएगी। अब तो आपने एक्ट भी बहुत ज्यादा सख्त बना दिया है। या तो आप नदियों की

चैनेलाइजेशन कर दो या लोगों को मिट्टी उठाने की परमिशन दो क्योंकि उनकी वे नदियां हैं। अपने घर के लिए वह मेटीरियल नहीं ला सकते हैं। ट्रैक्टर नदी के पास गया नहीं और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। रास्ते में फोरैस्ट गार्ड मिल जाएगा या माइनिंग वाला कहीं रास्ते में मिल जाएगा। आम व्यक्ति आज इस चीज से परेशान है। इसके लिए कोई पॉलिसी बनाओ हिमाचल प्रदेश के लोग कहां जाएंगे क्या उत्तराखंड से मेटीरियल लाएंगे? हरियाणा से क्या मेटीरियल लाएंगे? आपने इतनी सख्त पॉलिसी बना दी। पुलिस वालों को कोई दूसरा काम नहीं है। उनको काम है जहां सड़क में ट्रैक्टर मिले वहां एक से पैसे लिए और तीन से पैसे जमा करवा दिए। यह धंधा बन गया है। हमारे वहां आम आदमी इस पॉलिसी के कारण परेशान है। आप वहां के लिए ओवर लोडिंग खत्म करिए। हमें उसमें कोई ऑब्जैक्शन नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोग ट्रैक्टर से मेटीरियल लाएंगे। आप चार टन की बात करेंगे, पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज़ होगी । इस पॉलिसी में बदलाव करिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों का हिमाचल है। यह अधिकारियों का हिमाचल नहीं है। हमारा भी हिमाचल है, यह आम लोगों का हिमाचल है। कितने लोगों के चालान हो रहे हैं। आदमी कच्ची सड़क से पक्की सड़क में आया नहीं तब उसका चालान हो जाएगा। आपका किसी सड़क के ऊपर मेटीरियल गिरना है, सड़क अपग्रेड करनी है फिर कहां से मेटीरियल लाएंगे। नदी में कहीं आपने ट्रैक्टर ले गए तब चालान होना है। इसलिए यह जो पॉलिसी आपने सख्त बना दी इसमें छूट दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है। यहां घर बैठे-बैठे पॉलिसियां मत बनाओ। आम आदमी को परेशान करने वाली पॉलिसी मत बनाएं। हिमाचल प्रदेश के लोगों का उसके ऊपर हक है। अपनी जमीन से भी क्या हम मेटीरियल नहीं उठा सकते हैं? अपनी जमीन को प्लेन करने के लिए क्या हम मिट्टी नहीं उठा सकते हैं?

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

04.03.2020/1440/SS-DC/1

श्री सुख राम क्रमागत :

क्या उसके लिए भी हमें एप्लाई करना पड़ेगा और किसी अधिकारी से बात करनी पड़ेगी? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पॉलिसी में तबदीली करिये। आप चार टन की बात कर रहे हैं। क्या भरते वक्त वहां उसने कोई कांटा लगा रखा है कि इसमें चार टन भरना है और

पांच टन भरा गया? अगर आप अधिकारियों को इतनी शक्तियां देंगे तो उनका दुरूपयोग होगा। आम व्यक्ति उससे परेशान होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें आप थोड़ी-सी तबदीली लाईये।

चौहान साहब बोल रहे थे कि 500 करोड़ रुपये में से 250-300 करोड़ रुपये का घपला हो गया। देखिये, वैसे इतने के तो काम ही नहीं हुए। मु0 194 करोड़ रुपये के काम हुए हैं। उसमें से भी मु0 40 करोड़ रुपया बैलेंस पड़ा है। ...(व्यवधान) हम भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। परन्तु अगर ऐसी बात कहेंगे कि सिरमौर में 500 में से 250-300 करोड़ रुपये का घोटाला हो गया तो पूरे हिमाचल के लोग सोचेंगे कि सिरमौर में तो बड़े भारी घपले होते हैं। ...(व्यवधान) चौहान साहब, शिलाई भी जिला सिरमौर में ही आता है। चलो, इंक्वायरी हो। मैं नहीं कहता कि इसकी इंक्वायरी न हो। इसकी आप पूरी इंक्वायरी करो। यह मैंने भ्रष्टाचार पर बात की है।

जे0जे0एम0 की जो स्कीमें चली हैं उसमें हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए केवल नलके लगाने की स्कीम नहीं है। जहां पीने के पानी का स्त्रोत है उसको टैप करने की भी स्कीम है। वह उससे स्कीम बनेगी। उससे भी लोगों को लाभ मिलेगा। यहां पर माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया, इसमें हमारी सरकार के दो सालों के कामों का वर्णन है। दो साल के दौरान प्रदेश की सरकार ने जो काम किये, उसका लोक सभा के उप-चुनाव में भी नतीजा देखने को मिला। कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि दिल्ली में 70 में से 67 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोटें मिलीं। यानी कि नोटा को ज्यादा वोटें मिलीं और कांग्रेस को कम वोटें मिली हैं। कांग्रेस की दिल्ली में यह हालत हुई है। ...(व्यवधान) पैसा नहीं होता है। आप उसकी फिगर्ज़ देखना। ऐसा है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होना चाहिए। दूसरे की शादी में नाचना नहीं चाहिए। अपने घर की तरफ भी देख लो कि आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है। प्रदेश में आदरणीय जय

04.03.2020/1440/SS-DC/2

राम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बेहतरीन काम कर रही है। लोगों के हित में काम कर रही है। अभी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो बजट पेश किये हैं और परसों तीसरा बजट पेश होना है। पूरे पांच बजट पेश होंगे तो हिमाचल प्रदेश का जन-जन

आदरणीय जय राम ठाकुर जी के पीछे चलेगा। आगामी समय में हमारी सरकार बनेगी और आप फिर विपक्ष में बैठेंगे।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। मैं राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण का भरपूर समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत, जय हिमाचल।

04.03.2020/1440/SS-DC/3

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी हिस्सा लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

इस अभिभाषण में इन्होंने हमें बड़ी चालाकी और चतुराई से धारा-370 और सी0ए0ए0 में उलझाने की कोशिश की है, जिस तरह से देश में भी यही चला हुआ है। आपने देश के लोगों का ध्यान ज्वलंत समस्याओं से हटाने के लिए धारा-370 और सी0ए0ए0 लगा रखा है। हिमाचल में भी आपने यही किया है। अभिभाषण के पैरा नम्बर-2 में ही आपने शुरू कर दिया। आपको अपने हिमाचल की बात करनी चाहिए थी। लेकिन आप दिल्ली की बात करने बैठ गए। चलो, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं पहले आपकी जो हिमाचल में कारगुजारी है उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं। शब्दों का चयन करने में बी0जे0पी0 का कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि 70 साल तक आपका एक ही काम रहा। आप उस फैक्टरी के अंदर रहे जहां आपको इस किस्म के शब्दों का चयन करना, भाषण देना, लोगों को गुमराह करना सिखाया जाता है। वे तौर-तरीके आप सीखते रहे। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा-6 में बड़े अच्छे शब्द लिये हैं और माननीय राज्यपाल जी को आपने दो घंटे खड़े रखकर तकलीफ दी है। अगर आप अपने पैरा-6 में जो ये कहते हैं कि 'दो साल विश्वास के, प्रगति और विकास के', इतना ही बता देते और वे बैठ जाते तो सब कुछ आ जाता। फिर क्या ज़रूरत थी कि दो घंटे आपको बताना पड़ा कि क्या विश्वास आपने किया?

जारी श्रीमती के0एस0

04.03.2020/1445/केएस/डीसी/1

श्री जगत सिंह नेगी जारी---

तो अब मैं शुरू करता हूं कि ये जो दो साल विश्वास के आपके हैं, कौन सा विश्वास आपने हमें दिया? आपने तो इन दो सालों में पूरा का पूरा विश्वास ही खो दिया। आपने एक स्वर्णिम दृष्टि पत्र, मैं तभी तो कह रहा हूं कि शब्दों का चयन आप बड़ा अच्छा करते हैं, स्वर्णिम दृष्टि पत्र, वह पत्र आपका अदृष्ट हो गया और स्वर्णिम स्वाह हो गया। वह विश्वास ही आपने तोड़ दिया। हमने सोचा कि स्वर्णिम दृष्टि पत्र के माध्यम से आप हिमाचल को पता नहीं कौन सी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे परन्तु आपने तो हमारा विश्वास ही खो दिया। आपने हमें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, आपने उधर भी हमारा विश्वास खो दिया। आपने युवाओं का विश्वास भी खो दिया। आपने युवाओं से वायदा किया था कि आपकी सरकार बनेगी तो रूसा को सबसे पहले खत्म करेंगे लेकिन आज वे रूसा के बच्चे आपको रुला रहे हैं। आज आपके ए.बी.वी.पी. वाले सारे के सारे युनिवर्सिटी में, कॉलेजों में ताले लगा रहे हैं यहां तक कि आपको तो उन्होंने भैंस बना दिया। भैंस ला कर यूनिवर्सिटी के आगे रख दी और बीन बजाने बैठ गए। उनसे पूछा कि यह भैंस कौन है तो कहने लगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आप तो अब भैंसा बन गए। बीन भी आपको सुनाई नहीं दे रही है। फिर दोहरे नियम अपना रहे हैं। ए.बी.वी.पी. वाले अगर ताले लगा दें तो कोई केस नहीं बनता, अगर हम कुछ करें तो हमारे ऊपर देशद्रोह का केस बन जाता है। यूनिवर्सिटी बंद कर दो, ताले लगा दो, किसी भी दफ्तर में जा कर नारे लगा दो, वह देशद्रोह नहीं है क्योंकि वे ए.बी.वी.पी. वाले हैं। आप उनसे डरते हैं।

आपने जहां युवाओं का विश्वास खोया, वहीं मज़दूरों का विश्वास भी खो दिया। आपने बड़ी-बड़ी बातें की थीं कि आप मज़दूरों की हर तरह से रक्षा करेंगे लेकिन आज आपने उनका भी विश्वास खो दिया। इसी तरह से किसानों का विश्वास कहां रह गया? किसानों को कहा गया कि आपकी आय डबल कर देंगे। अरे, कैसे

डबल कर देंगे? गाय के मूत्र से, गोबर से अनाज को डबल कर दोगे? क्या सभी को भूखे मार दोगे? अगर आप दो साल में ये काम कराओगे तो दूध कम हो जाएगा। वाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं और गाय आप एक किलो दूध देने वाली ला रहे हैं। गौशालाएं बना रहे हैं। स्कूलशालाएं बंद और गौशालाएं बना रहे हैं लेकिन आपकी वह भी नहीं बनी। अच्छा हुआ कि आपने अभी शराब का रेट दोबारा बढ़ा दिया। मैं तो खुश था, ट्राईबल हूं, मैंने सोचा सस्ता शराब पी लूंगा पर उससे भी आपने वंचित कर दिया। पिछले दिन आपने हमें बढ़िया सपना दिखाया और अगले दिन हमारा सपना ही तोड़ दिया।

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के विश्वास की बात की जाती है। महिलाएं क्या विश्वास करेंगी जिस प्रदेश में एक साल में 1600 से ज्यादा महिलाओं के रेप, मर्डर या उत्पीड़न के केस रजिस्टर हो जाएं तो महिलाओं का भी आपने विश्वास खो दिया। ये दो साल विश्वास के नहीं हैं। अविश्वास के हैं, धोखे के हैं और तिरस्कार के हैं।

अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों से बड़े-बड़े वायदे किए गए थे। कर्मचारी भी आज अविश्वास की अवस्था में हैं। समाज का कोई भी वर्ग आज खुश नहीं है। ये दो साल विश्वास के नहीं, अविश्वास के हैं। इसी के साथ आगे आप कहते हैं प्रगति और विकास लेकिन बताएं कि आपने प्रगति क्या की? अगर हर रोज दिल्ली जाना प्रगति है तो हम समझ सकते हैं। अगर खिचड़ी बनाना प्रगति है, पता नहीं कितने क्विंटल खिचड़ी बनाई गई, एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो क्या खिचड़ी बनाना प्रगति है? मुख्य मंत्री जी, उसके बाद जो कचरा वहां छोड़ कर गए, उस एरिया में जो प्रदूषण हुआ, वह भी आपको देखना चाहिए था। आप तो खिचड़ी खा कर चले गए। आप रिकॉर्ड बना रहे हैं। मुख्य मंत्री जी, आज आपने तीन-चार स्टेटमैंट्स दीं। वाकई चिंता का विषय है। हम प्रगति कर रहे हैं फ़र्जी दवाइयां बनाकर। हिमाचल का नाम बदनाम करने में हम प्रगति कर रहे हैं। आज जम्मू-कश्मीर में 9 बच्चे मारे गए क्योंकि हमने नकली दवाइयां बनाई। आज झारखंड में भीबच्चे मरने वाले हैं क्योंकि हमने नकली दवाइयां बनाई। आपने क्या किया, क्या

एफ.आई.आर. दर्ज की? आपने अभी तक किसी को अरैस्ट नहीं किया। क्यों अरैस्ट नहीं किया ताकि वे वहां पर एविडैंस को खत्म कर दें?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

04.03.2020/1450/av-hk/1

श्री जगत सिंह नेगी--------जारी

बाद में जब आप उनको अरैस्ट करने लगेंगे तब वहां पर न तो फैक्ट्री मिलेगी और न ही दवाई पर जो दूसरी कम्पनियों के रैपर लगाये थे; वे मिलेंगे। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि उनको उसी समय अरैस्ट क्यों नहीं किया गया? यहां पर अगर कन्हैया कुमार नारा लगाता है तो उस पर देशद्रोह का केस बनता है और जिन्होंने दवाइयां बनाकर लोगों को मौत का सामान बेचा उनको आप अरैस्ट नहीं करते, यह आपका दोहरा चरित्र दर्शाता है। आप प्रगति करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्या 16 करोड़ रुपये का टैंट बनाना प्रगति है? अगर 16 करोड़ रुपये का टैंट लगाकर दूसरे दिन उसको हटाना है तो क्या आप उसको प्रगति कहते हैं? माननीय मुख्य मंत्री जी, क्या हैल्पलाइन बनाना प्रगति है? आपकी सरकार ने इतनी सारी हैल्पलाइन्स बना दी हैं। यहां पर माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी ठीक कह रही थी कि ये हैल्पलाइन्स नहीं बल्कि हैल्पलैस लाइन्स हैं। आपकी सरकार ने इतनी सारी हैल्पलाइन्स बना दीं कि याद भी नहीं रहती और इसके लिए एक डायरैक्टरी साथ रखनी पड़ेगी। आपको हैल्पलाइन्स के लिए एक अलग से डायरैक्टरी बनानी पड़ेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन हैल्पलाइन्स की लाइन्स भी टूटी हुई हैं। पता नहीं आप इनको कहां जोड़ना चाहते हैं। यहां पर हमारे एक मंत्री जी बड़े उत्तेजित होकर कह रहे थे कि हमने बहुत बढ़िया हैल्पलाइन्स बनाई हुई हैं। आपके एरिया से हेलीकॉप्टर के लिए हजारों फोन आते हैं मगर आप वहां पर हेलीकॉप्टर नहीं भेज पाते। आप हेलीकॉप्टर के लिए भरमौर वालों के साथ लड़ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर भरमौर चला गया। आप तो आपस में ही लड़ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर को कहां भेजे। आपका 2 वर्ष का प्रगति का कार्यकाल इस तरह से आगे बढ़ रहा है।

फर्ज़ी डिग्रियों की बात आई कि आपने लाखों फर्ज़ी डिग्रियां देने का रिकॉर्ड बना दिया। क्या यह आपकी प्रगति है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र की बात करे तो

04.03.2020/1450/av-hk/2

आप 2 साल से लैपटॉप नहीं दे पाये। आपने केवल 8000 लैपटॉप देने थे मगर 2 साल आपको उसके टैंडर करने में लग गये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसकी फैक्ट्री कहीं चांद पर तो नहीं लगी है? आपने स्कूल के बच्चों को 2 साल की वर्दी नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, हम यह पूछना चाहते हैं कि इनके लिए प्रगति के मायने क्या है? बाद में जो वर्दी दी गई वह भी घटिया दी गई। ...(व्यवधान) बाद में वह वर्दी धोते समय ही फट गई। आप लोग यहां पर कहते हैं कि बहुत ज्यादा विकास किया गया है। आदमी के बच्चे को पैदा होने में 7 से 9 महीने का समय लगता है और हाथी, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर है, उसके बच्चे को डेढ़ साल का समय लगता है। आप ब्ल्यू रैवोल्यूशन के अंतर्गत मछली पैदा करने की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ब्ल्यू व्हेल 100 फीट लम्बी होती है और उसका भार लगभग 1300 क्विंटल से ज्यादा होता है। उसके बच्चे को भी पैदा होने में डेढ़ साल का समय लगता है। लेकिन आपका विकास कैसा है जो 2 साल से पैदा ही नहीं हो रहा? आप इस विकास को कब पैदा करेंगे? मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपका विकास इस 5 साल के कार्यकाल में पैदा होगा भी या नहीं? आप बार-बार विकास को लेकर के जो उड़नखटोला में उड़ रहे हैं और उड़ते समय जो झटके लग रहे हैं उससे कहीं विकास का गर्भपात तो नहीं हो गया? यह विकास कब पैदा होने वाला है? अगर राज्यपाल महोदय इतना ही बता देते कि यह विकास फलां-फलां तारीख को पैदा होने वाला है तो हम लोग भी केक लेकर आते और मामा बनकर आपकी खुशी में शामिल हो जाते। लेकिन आपका विकास पैदा होने वाला नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि समय भाग रहा है और जैसे-जैसे समय खत्म होता है तो उत्पादन करने या पैदा करने की शक्ति भी खत्म हो जाती है तथा अंतिम वर्ष में तो चुनाव आयोग भी आपको पैदा नहीं करने देगा। इसलिए आपका यह विकास पता नहीं कहां और किस हालत में है। अगर अंतिम वर्ष में पैदा करेंगे तो वह कमज़ोर होगा और वह लंगड़ा-लूला भी हो सकता है। ऐसी स्थिति देखकर मुझे नहीं लगता कि आपका विकास पैदा होने वाला है। आपने पूरे देश में अनुच्छेद 370 को लेकर ऐसा शोशा पैदा किया। आपने इस अनुच्छेद 370 के नारे को वर्ष 1950 से शुरू किया।

आपके महान् नेताओं ने चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे या अन्य नेता थे; उन्होंने केवल 370 का एक ही मुद्दा पकड़ा। अब ज्यादातर लोगों को यही पता नहीं है कि अनुच्छेद 370 है क्या।

टी सी द्वारा जारी

04.03.2020/1455/TCV/HK-1

श्री जगत सिंह नेगी ... जारी

आप और हम कश्मीर तो चाहते हैं लेकिन कश्मीर के लोगों को नहीं चाहते। ऐसे कैसे कश्मीर चलेगा? आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1947 में कश्मीर का राजा कौन था? वह हिन्दू राजा था, जब देश आजाद हुआ तो वह एक कोने में बैठ गया। उनकी चाहत थी कि हिन्दुस्तान में रहेंगे तो राजपाठ चला जाएगा। वे आख़िर दिन तक इंतजार करते रहे कि पाकिस्तान किसी किस्म की कोई ऑफर दे तो वे पाकिस्तान जाने की तैयारी में थे परंतु पाकिस्तान वाले भी तेज़ थे। जब पाकिस्तान ने वहां से कश्मीर को हड़पने के लिए पठानों को भेजा तब राजा हरि सिंह तड़फ़े और नेहरू जी को फोन किया कि मुझे बचाओ, मैं हिन्दुस्तान में आना चाहता हूं। अगर पहला परमवीर चक्र मिला है तो वह कश्मीर की लड़ाई में मिला है। यह भी उस समय हिन्दुस्तान की सोच थी। ... (व्यवधान) बिल्कुल बोलूंगा, आप सच्चाई से डरते क्यों हो? ... (व्यवधान) उसके बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, सरदार पटेल ने फ़ैसला किया, ठीक है हम कश्मीर को बचाएंगे लेकिन उन्होंने हरि सिंह के साथ शर्त रखी कि आपको हिन्दुस्तान के साथ मिलना पड़ेगा। हरि सिंह ने भी शर्त रखी कि ... (व्यवधान) मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के संघ में आऊंगा लेकिन इन-इन शर्तों पर आऊंगा। उसमें एक शर्त थी ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। ... (व्यवधान) आपको मिर्ची क्यों लगी? ... (व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए। संसदीय कार्य मंत्री आप बोलिए।

04.03.2020/1455/TCV/HK-2

शिक्षा मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग है। वहां पर धारा-370 अस्थायी सोल्यूशन था, वह समाप्त हो गया है। अब ये

चाहते हैं कि कश्मीर हमारा नहीं था। हरि सिंह तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। ये हिन्दुस्तान के साथ है या पाकिस्तान के साथ है। ये इमरान ख़ान की भाषा बोल रहे हैं या हिन्दुस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आज हिन्दुस्तान धारा-370 ख़त्म होने के बाद एक निशान कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं। ये बताएं कि क्या ये कश्मीर में 2 झण्डे और 2 विधान चाहते हैं क्योंकि ये किन्नौर में ठाकुर सेन नेगी, जिन्होंने किन्नौर को बनाया, उनका भी विरोध करते थे इसलिए ये हिन्दुस्तान में कश्मीर का भी विरोध कर रहे हैं।

Sh. Jagat Singh Negi (Kinnaur): Hon'ble Speaker, Sir, with your permission, whatever the Hon'ble Minister has said here, I have all the documentary evidence. Sir, I may be allowed to lay these documents on the Table of the House i.e. the agreement which was made between the then Maharaja of Kashmir and Government of India.

एन0एस0 द्वारा ....जारी

04-03-2020/1500/NS/YK/1

श्री जगत सिंह नेगी ..... जारी

उसमें असली बात आ जाएगी। मैं सभा पटल पर रख दूंगा। यह तो जुबानी बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) This is not the way. I am not yielding. यह कोई तरीका है। आप बैठिए। ...(व्यवधान) सर, यह नहीं बैठेंगे I will come in the Well of the House. ...(Interrruption)

(माननीय सदस्य जगत सिंह नेगी जी वेल में आ करके बयानबाज़ी करने लगे।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठे। आपको बोलने का पूरा समय दिया जा रहा है। माननीय सदस्य आप अपने स्थान पर बैठे। ...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह नेगी : ...(व्यवधान) हम भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं। हम लोग आपसे ज्यादा विद्धान है। आपने क्या किया? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलें आपको समय दिया गया है। ...(व्यवधान) मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठे-बैठे न बोलें। माननीय जगत सिंह नेगी जी, आप अपने स्थान पर जाएं। ...(व्यवधान) नहीं-नहीं। आप बैठे। ...(व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय विधायक व माननीय राकेश सिंघा जी वेल में आ करके नारेबाज़ी करने लगे।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाएं और वहां से अपनी बात रख सकते हैं। मैं आपको अलौ करूंगा। ...(व्यवधान) सभी माननीय सदस्य सुनें। माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी इस अभिभाषण पर बोल रहे हैं। माननीय सदस्य आप अपने स्थान पर जाएं और अपनी बात कहें। आईए। माननीय नेगी जी आपका विषय पूरा नहीं हुआ है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य आईए। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया बैठे। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठें। ...(व्यवधान) --------

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

04.03.2020/1505/RKS/YK-1

(कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य और CPI(M) के विधायक, श्री राकेश सिंघा जी वेल में आकर नारेबाजी करते रहे।)

अध्यक्षः ...(व्यवधान) कृपया बैठ जाइए।...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय पर अपनी स्टेटमैंट जारी करेंगे, कृपया सभी सदस्य अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य और CPI(M) के विधायक, श्री राकेश सिंघा जी अपनी-अपनी सीट पर बैठ गए।)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इस विषय को यहां तक लाने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही हो और हम विषय से बाहर निकल जाएं तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है। यदि कोई रैफरैंस किसी से तालमेल खाता हो तो ऐसा रैफरैंस देने में कोई आपत्ति नहीं है। हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लिखित सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों पर चर्चा करने

के लिए यहां पर मौजूद हैं। विपक्ष इस पर अपनी टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र है। आपको जहां कमी लग रही है आप उस बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम आपकी बातों को सुन रहे हैं। हम इन चीजों में सुधार लाने की गुंजाइश निकाल रहे हैं। लेकिन इस विषय को जम्मू-कश्मीर तक पहुंचा देना ठीक नहीं है। माननीय जगत सिंह नेगी जी जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं। आप हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन हमें इन चीजों के ऊपर इतना जोश व रोष व्यक्त नहीं करना चाहिए। दोनों माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है। जब बात वहां से हुई तो यहां से भी कुछ कहा गया। आप दोनों वरिष्ठ सदस्य हैं परंतु जब देश बात की आती है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कुछ बातें आवेश में होने लगती है। मेरा निवेदन है कि हमें इन बातों को समाप्त करना चाहिए और इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो विषय हैं, हमें उन विषयों पर बात करनी चाहिए और इस चर्चा को समापन की ओर आगे बढ़ाना चाहिए।

04.03.2020/1505/RKS/YK-2

अध्यक्षः माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, हम सब चुने हुए सदस्य हैं। हम सब भारतीय हैं और किसी को यह शक नहीं होना चाहिए कि मैं ज्यादा भारतवासी हूं और ये लोग कम भारतीय हैं या वे लोग बड़े देशभक्त हैं और हम लोग कम हैं। माननीय नेगी जी जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं और इस विधान सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय नेगी जी इस विधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। जब इतने वरिष्ठ सदस्य को माननीय मंत्री की चेयर में बैठा व्यक्ति देशद्रोही होने से जोड़ दें तो यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपना वक्त्व्य दिया है मैं उससे सहमत हूं लेकिन इस बात की व्यवस्था दी जाए कि 'देशद्रोही' शब्द को आप इस कार्यवाही से निकाल रहे हैं। माननीय

अध्यक्ष जी, जो बात कही गई है उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी माफी मांगे या इस संबंध में आप अपनी व्यवस्था दें।

अध्यक्षः माननीय शिक्षा मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

04.03.2020/1510/बी.एस./ए.जी./-1

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा अगर कार्यवाही में देशद्रोही या गद्दार शब्द कहा गया है उसे एक्सपंच करने की कृपा करें। जो इन्होंने भाषा बोली मैंने सिर्फ उसमें बात कही है कि आप जो एक्सैशन की बात यहां पर कर रहे हैं, महाराजा हरिशचन्द्र पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे या कोई दूसरा राजा उस वक्त हिन्दुस्तान में मिलना ही नहीं चाहता था। आज ये धारा 370 क्या है? इस तरह की भाषा जो बोली गई है यह हिन्दुस्तान की भाषा नहीं है। आप हिन्दुस्तान के साथ है या नहीं? आप इसे क्लैरिफाई करें। ...(व्यवधान) मैंने कहीं नहीं कहा कि ये देशद्रोही हैं। अगर कहीं देशद्रोही या गद्दार शब्द की बात कही होगी कृपया उसे एक्सपंच कर दें। मैंने नीचे एस.डी.एम. के ऑफिस से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस की है। इन्होंने भी किन्नौर में प्रैक्टिस की है। इसलिए बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस में आती हैं। यहां पर भी आई होगी। इस तरह का कोई शब्द कहा गया है उसे एक्सपंच कर दें।

अध्यक्ष : इस तरह का कोई शब्द कार्यवाही में आया होगा तो उसे एक्सपंज किया जाता है। माननीय सदस्य जगत सिंह जी समय की तरफ भी ध्यान रखें और कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्र का मंदिर है। इस मंदिर में हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है आप आर्टिकल 108 भारतीय संविधान के अनुसार मेरी अभिव्यक्ति और मेरी स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते। आप इस बात को बड़े हल्के में ले रहे हैं। यहां पर एक मंत्री वह भी इस हाउस के सीनियर सदस्य हमें देशद्रोही

कहते हैं। आप मुझे देशद्राही बनाना चाहते हैं? मैं मंत्री से बात कर रहा हूं। किसी को देशद्रोही बोल दिया जाए या गाली दे दी जाए, इसे कौन सहन करेगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब यह विषय समाप्त हो चुका है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, इन्होंने स्वयं कहा कि यदि इस तरह के शब्द कार्यवाही में होंगे तो वे माफी मांगते हैं। कृपया आप विषय पर बोलें।

04.03.2020/1510/बी.एस./ए.जी./-2

श्री जगत सिंह नेगी : मुझे इनके कहने से कुछ नहीं लेना-देना देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है इसे वक्त बताएगा। इतिहास को मैंने नहीं बनाया। मैंने आपसे अनुमति ली है और मैं यहां पर सन 1947 के शुरू से सभी दस्तावेज ले करके आया हूं। किस तरह से कश्मीर हिन्दुस्तान में आया, 370 कैसे बना और कित तरह से 2019 में 370 को कम किया गया। वह सब में अपने साथ ले करके आया हूं। मैं यहां सब दस्तावेजों को रख दूंगा कृपया ये इन्हें पढ़ लें। जहां तक धारा 370 की बात है इसका हौआ इतना निकाल दिया कि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, कोई बड़ा तीर चला दिया है। आज आपने कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया है। आपने उनके साथ एक वायदा किया था उसे आपने पूरा न करके उनके साथ वायदाखिलाफी की है। आज 7 महीने हो गए कश्मीर के लोग जेल की तरह अंदर हैं। धारा 144 वहां पर लगी हुई हैं। इन्टरनैट वहां पर नहीं है, बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं। 70 लाख कश्मीरी जो हिन्दुस्तान के साथ हैं आपने उनको बंदी बनकर रखा हुआ है, यह मेरा आरोप है। इसका जवाब आप दे दीजिए। ये याद दिलाने वाले कोई नहीं है मुझे पता है। इतिहास को किसी के कहने से नहीं बदला जा सकता। हिटलर ने भी इतिहास को बदलने की कोशिश की थी माउंटवैटन ने भी इतिहास को बदलने की कोशिश की परंतु उन्होंने जिस सच्चाई को दबाया था वह आज ओपन हो रही है। यही हाल कश्मीर का भी होगा। हम कश्मीर को चाहते हैं। कश्मीर के पंडितों को 1990 में विस्थापित होना पड़ा उस समय दिल्ली के अंदर कौन थे? उस वक्त दिल्ली में आदरणीय वी.पी. सिंह जी की सरकार थी और उसमें आपकी पार्टी भी भागीदार थी। आपने उस वक्त पंडितों को वहां पर

क्यों नहीं रोका? क्या आप 7 महीने में उन्हे वापित ले गए? नहीं ले जा पाए। मेरा कहना है कि धारा 370 के बाद धारा 371 भी है। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। धारा 371 में नागालैंड को अलग से अधिकार दिया हुआ है, महाराष्ट्र को अलग से दिया हुआ है, आन्ध्र प्रदेश को अलग से दिया हुआ है, जिस किस्म की रियायतें हमने कश्मीर को दी है आज मेघालय, सिक्किम को और मणिपुर को भी दी हुई है। 14 अगस्त को नागालैंड में झण्डा लहराते हैं। ...(व्यवधान) सर, हमें आपका संरक्षण चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है।

04.03.2020/1510/बी.एस./ए.जी./-3

अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी, कृपया बैठ जाईए, सबको बोलने का मौका दिया जाएगा।
श्री डी.टी.द्वारा जारी...

04.03.2020/1515/DT/AG-1

अध्यक्षः माननीय सदस्य नेगी जी, कृपया आप बैठ जाइए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ बोलना चाहते है कृपया आप इनकी बात सुन लें। आपको बोलने का पूरा समय दिया जाएगा।

श्री जगत सिंह नेगीः इस हाउस से संबंधित नियमों की किताब मेरे पास उपलब्ध है, मैं इस किताब का क्या करूं?

अध्यक्षः माननीय संसदीय कार्य मंत्री कृपया आप अपनी बात रखें।

संसदीय कार्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि यह सिर्फ गवर्नर अड्रेस के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव है लेकिन ये इस पर नहीं बोल रहे हैं। हिन्दुस्तान में जम्मू-कश्मीर में धारा 371 चल रही है उसका कोई रैलिवैंस यहां पर नहीं है। इसका कोई रैफरैंस नहीं है। यह धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर बोलें। उसमें सिर्फ उस बात का धन्यवाद किया गया है कि धारा 370 समाप्त हुई है। लेकिन ये धारा 370 को ठीक बताने की कोशिश

कर रहे हैं और 371 पर चर्चा कर रहे हैं। आप नार्थ ईस्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हिमाचल के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो चीजें आउट ऑफ कंटैस्ट बोली जा रही हैं वे गवर्नर अड्रेस के धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं आ सकती हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया बैठिए। आप व्यवस्था सुन लीजिए। ...(व्यवधान) वैसे तो जो अभिभाषण है उस पर चर्चा अंतिम चरण पर हैं। चार दिन से यह बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से चर्चा चली हुई है। इसलिए इस चर्चा को आप कृपया वाइंड अप कर दें।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल का अभिभाषण है वह सरकार का दस्तावेज है। इसमें पैरा नं. 3 में ही धारा-370 का उल्लेख कर दिया है। अभी तो मैंने सी.ए.ए. का जिक्र किया ही नहीं। उसके बाद एन.आर.पी. और एन.आर.सी. है, फिर आप क्या करेंगे।...(व्यवधान) आज अफसोस की बात है कि हमें बोलने नहीं दिय जा रहा है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपको बोलने के लिए काफी समय दिया गया है।

04.03.2020/1515/DT/AG-2

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए और निमयों के तहत मुझे बोलने दीजिए अन्यथा इन नियमों का कोई मायना नहीं है। जब मैं बोलता हूं तो ये एक मिनट में खड़े हो जाते हैं। इनको आप कौन सी मिर्ची खिलाकर लाए हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपने काफी बोल दिया है, कृपया वाइंड अप कीजिए।

श्री जगत सिंह नेगीः काफी सदस्यों ने धारा-370 का गुण गाया है। मैं भी इसमें थोड़ी अपनी बात रख रहा हूं। धारा- 371 के बारे में भी मैं बता रहा हूं। नागालैंड में आज भी नागा लोग 14 अगस्त को अपनी आजादी बनाते हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप हिमाचल की बात करें, आप किन्नौर की बात करें। आप नागालैंड को छोड़िए।

श्री जगत सिंह नेगीः नागालैंड में आपको आज भी इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। अगर आपको मणिपुर में जाना है वहां भी आपको अलग से परमिट लेना पड़ता है नागालैंड में भी आप जमीन नहीं खरीद सकते। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के तहत जमीन खरीद सकते। कश्मीर सुन्दर है वहां के लोग सुन्दर हैं यदि आप वहां से शादी करना चाहते हैं तो शादी जबदस्ती नहीं होती वहां लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं।

अध्यक्ष : आदरणीय नेगी जी, बाकी बाते काफी हो गई कृपया आप किनौर की बात करें। आप समाप्त करें।

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सिटीजन अमैंडमैंट एक्ट का जिक्र आया है । इस एक्ट को लाने की क्या आवश्यकता है। हिन्दुस्तान में पहले ही यह एक्ट बना है। जो हिन्दुस्तान में पैदा हुआ वर्ष 1950 से वर्ष 1987 के बीच में वह अपने आप ही हिन्दुस्तानी है। वर्ष 1987 से वर्ष 2003 में जो पैदा हुआ यदि उसके माता- पिता जी भारतीय हैं वह भी भारतीय है। हां वर्ष 2020 के बाद कोई भारत में पैदा होता है उसका माता या पिता में से एक हिन्दुस्तानी और एक इलिगल इमिग्रैंट न हो तो भी सिटीजन बन सकता है। ये सभी पहले से हमारे पास प्रावधान है तो क्या आवश्यकता पड़ी कि आप विदेशियों को भारत में बुलाना चाहते हैं। आज भारतवासियों के पास रहने के लिए छत नहीं है, खाना नहीं है, रोजगार नहीं हैं क्यों आप बाहर के लोगों को यहा बुला रहे हैं। श्री एन.जी. द्वारा... जारी

04-03-2020/1520/ए.एस.-एन.जी./1

श्री जगत सिंह नेगी जारी.....

यदि आप हिन्दुओं के ज्यादा खैर-ख्वार हैं तो श्रीलंका व बर्मा में जो हिन्दू हैं उन्हें भी इस कानून में शामिल कीजिए। (घण्टी) केवल 3 स्थानों के हिन्दुओं को लाकर आप वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और आप हर प्रकार से सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं। आप कहते हैं कि देश को सोने की चीड़िया बनाएंगे...(व्यवधान) आपने देश को बेच दिया।...(व्यवधान) हमने यह कभी नहीं सोचा था कि चाय बनाने वाला हमारा देश भी बेच देगा।...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य वाइंड-अप करें।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, केवल 3 प्वाइंट बचे हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य बहुत हो गया और निर्धारित समय भी खत्म हो गया है...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा से सम्बन्धित विषय रखना चाहता हूं।

अध्यक्षः कृपया दो शब्दों में वाइंड-अप कर दें।

श्री जगत सिंह नेगीः नहीं सर, आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा क्योंकि मेरा टाइम सत्तापक्ष के लोग खा गए हैं।

अध्यक्षः किसी ने आपका टाइम नहीं खाया और आप लोग वैल में आ गए इसलिए आपको बोलने का टाइम कम मिला।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, मुझ से पूर्व सदस्यों ने कहा कि जो दस्तावेज़ बनाया गया है वह आधी नींद में बनाया गया है और यह बात बिल्कुल ठीक है। इसके पैरा-97 में स्कूलों की बात हो रही है। इसमें कहते हैं कि स्कूलों की कार्य प्रणाली पर नजर रखने तथा उनके कामकाज में पाई जाने वाली खामियों को

हल करने हेतु 'शिक्षा साथी ऐप' शुरू की गई है जिसके माध्यम से वर्तमान वित्त वर्ष में 12,826 प्राथमिक व 8,948 प्रारम्भिक विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी आंकड़ो के मुताबिक कुल 10,628 प्राथमिक स्कूल हैं और 1,969 माध्यमिक स्कूल व 2,776 हाई स्कूल हैं।...(व्यवधान) आप मुझे देशद्रोही साबित करने में लगे हुए हैं और आपको अपने विभाग का होश नहीं है।...(व्यवधान) आपने शिक्षा का कबाड़ा कर दिया, शिक्षा का भट्टा बिठा दिया। आपने India Today से नकली ट्रॉफी ले ली

और उनका दिमाग खराब है क्योंकि जो मंत्री लैपटॉप नहीं दे सकता, (घण्टी) जो वर्दी नहीं दे सकता उसको इनाम दे दिया।...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप फिर से आक्रोश में आकर उत्तेजित हो रहे हैं। कृपया आप वाइंड-अप करें।...(व्यवधान) आप चेयर को सम्बोधित करें। आपका समय खत्म हो गया है और कृपया वाइंड-अप करें।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, पैरा-90 जनजाति के ऊपर है। इसमें यह कहते हैं कि कुल वार्षिक योजना बजट का 9 प्रतिशत भाग 'अनुसूचित जनजाति उप-योजना' के लिए दिया गया है। लेकिन 639 करोड़ रुपये (9 प्रतिशत) में से 60 प्रतिशत बिजली बोर्ड, एच.पी.सी.एल. वर्ल्ड बैंक के इक्विटी आदि को दे रहें हैं। जनजाति के हिस्से में तो 100 करोड़ भी नहीं आ रहा है। 500 करोड़ तो आप अन्य स्थानों पर ले गए तो हमारे जनजातियों के पास क्या बचा? जनजातियों के लिए संविधान के तहत अनुच्छेद-5 में Tribal Advisory Council बनाने का प्रावधान है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2 साल में इसकी एक भी बैठक नहीं की, इन्होंने खिचड़ी वाली सभी बैठकें कर दी लेकिन जो संविधान के तहत कमेटी बनी है उसकी एक भी बैठक नहीं की गई। उसमें ऐसे-ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो लाभ के पद पर हैं और हमने माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में भी लाया था कि जो व्यक्ति लाभ के पद पर बैठा है वह इस संवैधानिक संस्था का सदस्य नहीं हो सकता और अभी तक आपने उन्हें नहीं हटाया। आप दो प्रकार के नियम पर चल रहे हैं,

माननीय अध्यक्ष, श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

04/03/2020/1525/MS/As/1

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जगत सिंह नेगीः ट्राइबल एरिया का जो कम्पेंडियम है उसमें कहते हैं कि ट्राइबल एरिया में एकरूपता लाने के लिए सभी विधायकों को इस कमेटी का चैयरमेन बनाएंगे। आपने उस कमेटी में लाहौल और भरमौर को स्थान दे दिया तो किन्नौर के साथ क्या

दुश्मनी है? क्या किन्नौर के लोगों ने आपको वोट नहीं दिए हैं? अगर 41 परसेंट वोट मुझे मिले हैं तो कुछ परसेंट वोट आपको भी मिले हैं। इसलिए आप किन्नौर के साथ क्यों भेदभाव कर रहे हैं? आपने इसमें एस0सी0 कम्पोनेंट का ज़िक्र ही नहीं किया है। यहां 17 से ज्यादा एस0सी0 के हमारे माननीय सदस्यगण बैठे हैं और यदि ये चुप हैं तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों हैं। यहां बड़े खुश हो रहे थे कि मंदिर बनेगा। अरे, अगर मंदिर बनेगा तो आप मंदिर के बाहर दरबान भी नहीं होंगे यानी आपको अंदर जाने ही नहीं देंगे। इसलिए आप क्यों खुश हो रहे हैं? मैं आख़िर में यही कहूंगा, हालांकि मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था परन्तु इनको ज्यादा मिर्ची लग गई है इसलिए यहीं रुक जाता हूं। जो अब्राहम लिंकन अमरीका के महान राष्ट्रपति थे, वे ट्रम्प की तरह हाउडी या राउडी नहीं थे। उन्होंने अमरीका को बनाया। उनके विचार मैं यहां पर कहना चाहता हूंः

आप सभी को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं
और कुछ लोगों को हमेशा के लिए,
लेकिन आप कभी सभी लोगों को हमेशा के लिए
मूर्ख नहीं बना सकते हैं।

धन्यवाद।

04/03/2020/1525/MS/As/2

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय सारी चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर इस माननीय सदन में माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा था तथा राकेश जम्वाल जी ने उसका अनुसमर्थन किया था। इस अभिभाषण पर हुई चर्चा में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भाग लिया, जिसका उत्तर देने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, मुझे जो सूचना मिली है उसके मुताबिक कुल-मिलाकर 47 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। जिसमें 28 सत्तापक्ष के, 16 प्रतिपक्ष के, 1 सी0पी0एम0 और दो माननीय सदस्य जो निर्दलीय चुनकर आए हैं, उन्होंने भाग लिया है। यह चर्चा कुल-मिलाकर साढ़े चौदह घण्टे चली और मुझे प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश की विधान सभा में विस्तार से सार्थक चर्चा करने की परम्परा वर्षों से है। मैं सभी माननीय सदस्यों का

आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी बात इस अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान इस माननीय सदन में रखी है। स्वाभाविक रूप से मोटे तौर पर हम सबको इस बात को स्वीकार करना होगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण सरकार की एक साल की कार-गुजारी पर होता है। जो हमने यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण सुना, उसको लगभग सवा दो घण्टे तक उन्होंने यहां पढ़कर सुनाया और जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं उनका विस्तार से अभिभाषण में जिक्र किया। सत्तापक्ष के सभी सदस्यों ने कहा कि हमने अच्छा करने की कोशिश की है। हम यह कभी नहीं कह रहे हैं कि जो काम किए हैं उनमें और सुधार करने की गुंजाइश या जरूरत नहीं है। हमने अच्छा करने की कोशिश की है लेकिन उसके बावजूद हम इस बात से सहमत हैं कि अभी भी और अच्छा करने की गुंजाइश बाकी है यानी इससे भी बेहतर किया जा सकता है और बेहतर क्या किया जा सकता है, उस दृष्टि से हमने सोचा था कि विपक्ष के हमारे मित्रों के कुछ सुझाव आएंगे। हालांकि कुछ बातें कही भी हैं। लेकिन जैसा हम यहां पर देख रहे थे इनका ज्यादा ज़ोर इसी बात पर लग गया कि ये हर बात को नकारने की कोशिश करते हैं। जे0के0 द्वारा जारी------

03.03.2020/1530/JK/DC /1

मुख्य मंत्रीः----जारी-------

आखिरकार कब तक आंखें बंद करके कबूतर की तरह करने की कोशिश करेंगे, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की ओर से जो कहा गया, विपक्ष के नेता जी को सीधे सुनने का उस दिन मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका लेकिन मैंने अपने पास उस दिन की स्पीच रखी है, वह मैंने पढ़ी। कुछ बातें आपने मीडिया में शेयर कीं, वे भी हमने सुनी कि कुछ नहीं हुआ। अगर हम आपकी बात मान लें कि कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ नहीं हुआ तो भी आपकी अच्छी स्थिति नहीं है, फिर यह दुर्दशा क्यों हुई है? लोकतंत्र में हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। आप काम करते हैं, उसके बाद लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, जनता के ऊपर छोड़ देते हैं और फिर जनता निर्णय करती है कि अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर

रहे हैं। हमने काम करने की कोशिश की, हमने प्रदेश की जनता के ऊपर छोड़ दिया। लोक सभा का चुनाव आया, उसमें बहुत सारी बातें हमारे मित्रों ने कही। इन्होंने कहा कि पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं, हमने कहा लगना चाहिए। इन्होंने कहा कि ज़मीन निकल गई है, हमने कहा वह भी हम देख लेंगे। आ़खिरकार अध्यक्ष महोदय, लोक सभा का चुनाव हुआ और उसका परिणाम आया। सीटें तो वर्ष 2014 में भी हमने चारों जीती थीं, जब हम सत्ता में न यहां थे न केन्द्र में थे। वर्ष 2019 के चुनाव में हमारी मंशा थी कि यह एक ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए, जो लम्बे समय तक हिमाचल के इतिहास का हिस्सा बन कर रहे, उसके लिए हमने मेहनत की। हम प्रदेश के लोगों के बीच में गए। लोगों के बीच में जा कर अपनी बात कही, अपनी बात को समझाने की कोशिश की। मुझे प्रदेश की जनता का दिल से आभार व्यक्त करना है कि उन्होंने हमारी बात को सुना, सुना ही नहीं हमारी उस बात को समझा, समझा ही नहीं उस बात को उन्होंने स्वीकार किया और ह्रदय से स्वीकार किया। परिणाम यह हुआ कि मोहर लगी 68 के

03.03.2020/1530/JK/DC /2

68 चुनाव क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आगे रही। अभी कुछ महीने ही बीते हैं, उसके बावजूद भी आज हमें कह रहे हैं कि अब करो, फिर देखो ज़रा। उसके बाद अगला दौर आया, उप चुनाव का दौर आया। अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के चुनाव में तो इन्होंने कहा कि मोदी जी का नाम लेकर इन्होंने अपना जुगाड़ कर लिया लेकिन अब असली पता लगेगा। अध्यक्ष महोदय, फिर उसके बाद हम लोगों के बीच में गए, लोगों ने हमारी बात सुनी, स्वीकार की और लोगों ने हमें सहयोग दिया। धर्मशाला भाजपा की थी, भाजपा की फिर से बनी और आज विशाल नैहरिया जी वहां से हमारे बीच में विधायक हैं। आप कहां रहे, तीसरे स्थान पर रहे और ज़मानत ज़ब्त हुई। फिर भी मैं हैरान हूं कि आप लोगों की इतनी ज़ोर से कहने की हिम्मत तो माननी पड़ेगी। यह चमड़ी बहुत मोटी है। इसमें असर ही नहीं होता। पच्छाद से श्रीमती रीना कश्यप यहां पर बैठी हैं। अरे भाई, कुछ तो सब्र करो, कुछ तो संयम करो, रुक जाओ और अब बोलो कि माफ करो, काफी हो गया लेकिन फिर

भी उसके बावजूद ये नहीं मानते हैं। आप लोग आगे आएं हम लोग यहां पर खड़े हैं। हम कह रहे हैं कि हम शोर नहीं मचाते हैं। अपनी बात कहते हैं। थोड़ी सी बात कहते हैं लेकिन वह भी आपको पसंद नहीं आ रही है। आप लोग तो बोलते ही जाते हैं। हम तो उसके बावजूद भी नहीं बोलते । हम तो थोड़ी सी बात बोलते हैं, कभी-कभी बोलते हैं लेकिन आप लोगों को उस बात में भी परेशानी होती है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना परेशान नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह दौर अभी चला है। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है। स्वाभाविक रूप से हमारी कल्पना है कि हम लोगों को उसके अनुरूप काम भी करना चाहिए। हमने कोशिश भी की है। ठीक है, कुछ बातें होती हैं, कुछ घटनाएं घटित होती हैं, वे विचलित करती हैं, उसमें परेशानी होती है और उनसे हम को भी पीड़ा होती है।

श्री एस.एसय. द्वारा जारी-----

04.03.2020/1535/SS-DC/1

मुख्य मंत्री क्रमागत :

और आप लोगों को भी स्वाभाविक रूप से बुरा लगता है और हमको भी लगता है। लेकिन उसका समाधान होना चाहिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी हर बात पर तारीफ करो। आवश्यकता नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। उसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। लेकिन अपनी बात ऐसी कहो जिसको कहने के बाद लोगों को लगे कि जो बात आप कह रहे हैं वह ठीक है, ज़ायज़ है। अभी तक जो आप कह रहे हैं उसे लोगों ने बुरी तरह से नकारा है। जिसको बोलते हैं कि सिरे से खारिज किया है। आप कहने की कोशिश करते हैं, जोर से कहने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। आप जबरदस्ती सुनाने की कोशिश करते हैं, लोग सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। यह एक अन्तर है। जिस अन्तर को समझने और समझाने की आवश्यकता मुझे लगती है। इसलिए जहां तक आप (श्री मुकेश अग्निहोत्री से) दिल्ली की बात कह रहे हैं, वहां चुनाव में आप लोगों को शून्य मिला है और दूसरी बार हासिल हुआ है। देखिये, हम तो फिर भी वहां पर मुकाबले में आए। हम वहां पर लगभग 40 प्रतिशत वोट के मुकाबले में पहुंचे हैं। लेकिन आप लोग तो चार

छटांक रह गए। पहले जो तोलने का पैमाना होता था उसमें एक छटांक, दो छटांक या छः छटांक इत्यादि होते थे। इनको पता है कि जो पुराने समय में तराजू होता था उस समय छः छटांक का एक सेर होता था। इसलिए आप लोग दिल्ली में एक सेर भी नहीं हुए। आपकी ऐसी हालत हुई है। इसलिए मेहरबानी करके इस विषय को छोड़ दें। उस प्रदेश में जहां तीन बार लगातार आपकी सरकार रही है वहां आप 4 प्रतिशत पर आ गए और हम फिर भी 40 प्रतिशत पर हैं। ...(व्यवधान) उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल छोटा प्रदेश है, हमने यहां पर ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है तो उसका परिणाम सामने आया है। आज अगर हम लोक सभा चुनाव का परिणाम देखें तो पूरे देश भर में highest vote share हिमाचल प्रदेश का है। 69 परसैंट वोट हमारी भाजपा पार्टी को मिला है। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट 72.5 परसैंट के साथ जीती है। इसलिए आपको इन बातों को समझने की आवश्यकता है। हमारे मित्र और विपक्ष के नेता कह रहे थे, आजकल इनका एक बड़ा फिट जुमला है - 'बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया।' मुझे सबूत दो, मैं यहां खड़ा हूं और मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या भाव में हमने बेचा है, किसको हमने बेचा है। कम-से-कम एक चीज़ को करिये, मुकेश जी, आपको लोग सुनना बंद कर देंगे अगर आप बेकार में इस तरह से कहेंगे। ...(व्यवधान) इस तरह से कहते हैं कि बेच दिया, बेच दिया। लेकिन बेचा क्या, वह

04.03.2020/1535/SS-DC/2

बताईये। इस तरह से सारी चीज़ों को सैनसेशनलाइज करने कोशिश होती है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ यहां पर खड़ा होकर दावे से कह सकता हूं कि हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। अनदेखी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हिमाचल के हितों के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा, आपसे कम नहीं बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम बहुत सारी बातों का ज़िक्र करें और आप बेचने की बात कहें तो वह सही नहीं है। अगर हम शुरूआत से देखें तो वाइल्ड फ्लावर हॉल 1995 में जब आप लोग सत्ता में थे तो ज्वाइंट वैंचर में बेच दिया गया। उसमें हमारा शेयर 35 परसैंट था। आज वह शेयर घटते-घटते 14 परसैंट रह गया। वह किसने बेचा? वहां पर जो 2200 स्टैंडिंग ट्रीज़ हैं, 103 बीघा ज़मीन है, आज की तारीख में अगर उसकी कीमत आंकी जाए तो वह 1000 करोड़ रुपये से ऊपर है। क्या हमें उसमें कुछ हासिल हो रहा है? हमारे लिए आप एक भी

उदाहरण बताईये कि दो साल के कार्यकाल में हमने ये बेच दिया। लेकिन हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। आप ये (लिस्ट दिखाते हुए) देखिये। ...(व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूं कि आप कहानियां मत डालिये। ...(व्यवधान) आप (श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से) थोड़ा सुनिये। हमने भी आपके एक-एक सदस्य की बात को सुना है।

जारी श्रीमती के0एस0

04.03.2020/1540/केएस/डीसी/1

मुख्य मंत्री जारी---

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में हमने काम करने की कोशिश की है। हमने जनमंच शुरू किया। ठीक है, आपको पसन्द नहीं है, आप अपनी जगह है लेकिन हम अपनी जगह हैं। हमने उसके माध्यम से लोगों की सेवा करने की कोशिश की है। हमने हिमाचल प्रदेश मे 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए पैंशन शुरू की। यह आपको पसन्द आया या नहीं, मुझे नहीं मालूम और हमने इस बात को पूछा भी नहीं लेकिन हमें पसन्द है कि जिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमने इस दुनिया को देखा और जाना, हमने उनके प्रति अपना आदर-भाव व्यक्त करके उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि ये सारे काम ठीक नहीं हैं, आप आगे बढ़कर अपनी बात कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जनमंच में लोगों की समस्या के समाधान के लिए हमने सोचा कि अगर गांव का आदमी गांव में रहेगा, सरकार उसकी समस्या के समाधान के लिए वहां आएगी, हमारा मंत्री आएगा, डी.सी., एस.पी. सभी अधिकारियों के साथ वहां पहुंचेंगे और मौके पर लोगों की समस्या के समाधान की बात होगी। लोग वहां आते हैं और मुकेश जी, पूरे देश भर में यह एक अनूठी योजना है जहां खुले मंच पर किसी भी आदमी को, जिसकी शिकायत हो, माइक दे दिया जाता है । उसमें खुश होने वाला व्यक्ति तो तारीफ़ करता है लेकिन जो नाराज होता है, वह शिकायत करता है, माइक पर ज़िक्र करता है कि मेरी

समस्या यह है । मंत्री अधिकारियों को आदेश करते हैं और उसकी समस्या का समाधान होता है। इस प्रकार की योजना का भी आप विरोध कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश में 189 जनमंच के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 45,708 के लगभग उनमें शिकायतें आई हैं और कुछ मांगे भी आई हैं लेकिन हमने कहा कि मांगों का समाधान यहां पर नहीं होगा क्योंकि उसके लिए बजट चाहिए। आपको स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, पुल चाहिए या सड़क चाहिए तो उसके लिए बजट का प्रावधान करना पड़ेगा, तब जा कर उनका समाधान

04.03.2020/1540/केएस/डीसी/2

होगा लेकिन हम 41,698 शिकायतों का निपटारा करने में कामयाब हुए हैं। हमने इससे आगे बढ़कर सोचा। इस टैक्नोलॉजी के युग में आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, ऐसी परिस्थिति में हमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है इसलिए हम और आगे बढ़े। हमने कहा कि दुनिया भर में हैल्पलाइन शुरू हो गई है और उसके माध्यम से भी समस्या का समाधान होता है। मान लो किसी के पास समय नहीं है, विवशता है कि वह किसी अधिकारी या कर्मचारी के पास नहीं पहुंच सकता, घर बैठे उसकी शिकायत का समाधान कैसे हो सकता है, इसके लिए हमने हैल्प लाइन की शुरूआत की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में इस प्रकार की शुरूआत करने वाला हिमाचल प्रदेश छठा प्रदेश है जहां हमने 1100 के माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान घर बैठे करने में कामयाबी हासिल की है। मैं खुद गया, खुद जा कर देखा समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, जो लोग नाराज थे, हमने उनकी बात को भी सुना और जिन लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ, उनकी बात को भी सुना। उन्होंने यह नहीं बताया था कि मुख्य मंत्री आएंगे, वे आपकी जो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की है, उसको सुनेंगे लेकिन जब हम वहां पर गए, वहां जा कर जब हमने सबको सुना, मुझे बहुत संतोष है कि 7-7 साल की, 10-10 साल की समस्याएं जिनके बारे में एक बार नहीं, अनेकों बार कागज पर लिखकर शिकायत की गई थी लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ था, 1100 पर फोन करने के बाद उन समस्याओं का समाधान हुआ और अनेक लोगों ने 1100 पर दोबारा फोन करके कहा कि मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, मेरी समस्या का समाधान हो गया है। हमने 16 फरवरी, 2020 को इसकी शुरूआत की थी

और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 33,275 शिकायतों का संतोषजनक निवारण करने में हम कामयाब हुए हैं। इसको भी आप उपलब्धि नहीं मान रहे हैं, जन मंच को भी आप उपलब्धि नहीं मान रहे हैं, बुजुर्गों को पैंशन के कार्यक्रम को भी उपलब्धि न मानें तो मुझे लगता है कि आपकी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

04.03.2020/1545/av-dc/1

मुख्य मंत्री--------जारी

...(व्यवधान) आप अपनी समस्या का समाधान करने के लिए जनमंच में आया करो। यहां पर बहुत सारे सदस्यों ने गैस कनेक्शन के सिलसिले में कहा कि इससे क्या हुआ। हम इस बारे में केवल इतना कहना चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की और हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो इस योजना के अंतर्गत नहीं आ पा रहा था। हमने कहा कि इस कमी को हम पूरा करेंगे और हमने जोश व जुनून के साथ तय किया तथा इसके लिए मैं अधिकारियों व कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमने यह तय किया कि हिमाचल प्रदेश में गैस कनेक्शन हर रसोई घर में पहुंचा कर छोड़ेंगे। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमने 2.76 लाख गैस कनेक्शन दिए हैं। हमारी माताएं-बहनें पहले यह देखने के लिए पड़ोसी के घर जाया करती थीं कि गैस पर खाना कैसे बनता है। आज वे अपने हाथों से अपनी रसोई के अंदर गैस पर खाना बना रही है और अपने परिवार को खिला रही है। यह अंतर है, मगर आप लोग उसको फिर भी उपलब्धि नहीं मानते। हमने आगे बढ़कर संवेदनशीलता का एक और उदाहरण दिया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना शुरू की जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का हैल्थ कवर है। आज इस देश के बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ लेकर अपने स्वास्थ्य का उपचार करवा रहे हैं और मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना के तहत करीब 22 लाख लोग कवर हुए हैं। लेकिन हमारी आबादी तो 70 लाख के लगभग पहुंच गई है। इसलिए हमने कहा कि शेष बचे लोगों की

बीमारी का भी उपचार होना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिस तरह से लोगों को सुविधा मिली है तो इस योजना से वंचित रह गये लोगों को भी अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए कोई ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमने उस वक्त इस बारे में आपके मंत्रालय में चर्चा की और चर्चा करने के बाद योजना बनाई। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हर आदमी के उपचार के लिए इस प्रकार की योजना चलायेंगे कि जो आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं हो पाया उसको हिम केयर के तहत लायेंगे

04.03.2020/1545/av-dc/5

और उसके अंतर्गत हम 5 लाख रुपये तक का हैल्थ कवर लेंगे। आज मुझे इस बात की खुशी है कि इस योजना के अंतर्गत 60000 से ज्यादा लोगों का उपचार कर लिया गया है। इस योजना के तहत हमने लगभग 65 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में हम उन लोगों की पीड़ा कम करने व जान बचाने में कामयाब हुए हैं जिनके पास अपना उपचार करवाने के लिए पैसे नहीं होते थे। पहले कोई बीमार व्यक्ति अस्पताल में दाख़िल होता था और दाख़िल होने के बाद वह अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता था मगर उसके परिवार के लोग डॉक्टर के पास जाते थे कि हमारे मरीज को छुट्टी दे दो। जब डॉक्टर बोलता था कि मरीज छुट्टी देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि यह अभी तक ठीक नहीं हुआ तो कहते थे कि हमें मालूम है कि मरीज ठीक नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास आगे का उपचार जारी रखने के लिए पैसे नहीं है। कई बार तो जमीन बेचने व घर गिरवी रखने तक की परिस्थिति आ जाती थी। कई बार तो लोग डॉक्टर को बिना बताये ही अपने मरीज को उठाकर घर ले जाते थे और चीख-पुकार के बीच में उस मरीज की ज़िंदगी बिना उपचार के ही खत्म हो जाती थी। हमने कहा कि इसके लिए सरकार है। सरकार इसलिए होती है जो कि लोगों की चीख-पुकार सुन सके, उसकी मदद कर सके और इसी उद्देश्य से हमने इस योजना की शुरुआत की है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमने हिम केयर योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके हिमाचल प्रदेश में ऐसे सैंकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों की मदद करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ। आप लोग कहीं तो मान लिया करो। आपको थोड़ा भगवान से भी डरना चाहिए और आप लोग इतना भी असत्य न बोलें कि भगवान भी यह सोचने पर विवश हो जाए कि मैंने इस धरती पर इस तरह के कौन लोग बनाकर भेज दिए।

हमने हिमाचल प्रदेश में इसके अतिरिक्त एक और योजना शुरू की है और यह योजना ऐसे लोगों के लिए है जो लाचार व बेबस है तथा बिस्तर पर पड़े हुए हैं। ऐसे लोग जो ज़िंदा हैं मगर उस ज़िंदगी को वे सिर्फ जी रहे हैं।

टी सी द्वारा जारी

04.03.2020/1550/TCV/YK-1

मुख्य मंत्री...जारी

अगर टॉयलेट भी जाना है तो किसी आदमी का सहारा लेना पड़ता है। किसी आदमी को पैरालिसिज़ हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया है और वह अचेत अवस्था में पड़ा है; किसी का एक्सीडेंट हो गया और टांगे चली गई; किसी की किडनी फेल हो गई है; किसी का कैंसर स्टेज-IV पर पहुंच गया है, ऐसे लोगों के लिए यह योजना है। किसी को अल्जाइमर हो गया है; ऐसी परिस्थिति में उनकी सेवा करने के लिए उनके पास एक आदमी होना चाहिए। हमने इसकी शुरूआत 'सहारा योजना' से की है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस सहारा योजना के अंतर्गत जितने भी मरीज़ इस कैटेगरी में आते हैं जो बेबस हैं, चल नहीं सकते हैं, अपना काम स्वयं नहीं कर सकते हैं, उनके खाते में 2,000 रुपये हर महीने डाले जाते हैं। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि यह सब ठीक नहीं हो रहा है। आपकी इस बात के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। जहां तक काम की बात है, मैं इन चीज़ों का बहुत ज्यादा ज़िक्र नहीं करता कि हमें यह इनाम मिला या वह इनाम मिला। हां थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता ज़रूर होती है, जब कोई अच्छा काम करने के पश्चात कोई अवार्ड मिलता है। यह सम्मान चाहे छोटा या बड़ा हो, यह सम्मान प्रदेश के लिए है। मैं उसका अभिन्नदन करता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि सम्मान मिलने के बाद आगे बढ़ने का उत्साह तो स्वाभाविक रूप से मिलता है लेकिन उसके बाद कुछ भी करने का नहीं है, हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। अगर हम एस0डी0जी0 रैंकिंग की बात करें तो पूरे देशभर में हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर आया है। एस0डी0जी0 के 17 लक्ष्यों में से 5 लक्ष्यों में हमारा प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है, यह भी हमारे लिए संतोष की

बात है। आपको यह कहने में ठीक नहीं लगता है तो मत कहिए लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में जहां अच्छा हुआ है, उसका भी ज़िक्र करते तो आपका बुरा न होता, अच्छा ही होता। आप कहते हैं कि लोन ले लिया, हमें लोन क्यों लेना पड़ा? यह आपकी मेहरबानी है। इतनी मेहरबानी हम पर हो गई है और उन मेहरबानियों की वज़ह से ...(व्यवधान)

04.03.2020/1550/TCV/YK-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुन लीजिए, माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

मुख्य मंत्री : मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये ऐसे आंकड़े कहां से लाते हैं? ये आंकड़े लाते हैं कि इतनी ट्रांस्फरें हो गई, ट्रांस्फरों का आंकड़ा आया तो बराबर का निकला। इन्होंने कहा कि इतनी सारी नौकरियां बाहर के लोगों को दे दी, जब आंकड़ा आया तो आप हमसे आगे निकले। ...(व्यवधान) यहां पर श्री मुकेश जी, श्री राम लाल ठाकुर जी और अन्य कई सदस्यों ने कहा कि ऋण ले लिया और यह भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई कि सरकार 8,000 करोड़ रुपये का ऋण ले रही है, जो कि अत्याधिक है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा तक ही ऋण ले सकती है तथा यह सीमा नेट बोरोइंग की होती है न कि किसी ग्रोस बोरोइंग की। सही आकलन तब होगा जब वर्ष के अंत में प्रदेश के शुद्ध ऋण में कितनी वद्धि हुई; यह देखा जाएगा न कि इस आधार पर कि वर्ष के दौरान कितनी ग्रोस बोरोइंग हुई है। जैसा मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि हमारी सरकार ने अपने प्रथम 2 वर्ष के कार्यकाल में जो शुद्ध ऋण लिए हैं, वह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सीमा से काफी कम हैं। वर्तमान सरकार का यह प्रयास रहा है कि ऋण लेने से यथासंभव बचा जाये और नकदी की अस्थायी कमी को ...(व्यवधान) आज आपको...

एन0एस0 द्वारा ....जारी

04-03-2020/1555/NS/YK/1

माननीय मुख्य मंत्री ..... जारी

आज आपको सही आंकड़े देंगे और आपने आज नोट कर लेना क्योंकि कल के बाद आपने यही आंकड़े बोलने हैं। अध्यक्ष महोदय, अग्रिम Ways & means advance से पूरा किया जाए। यही कारण है कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से अनुमति होने के बावजूद भी खुले बाज़ार से 1,617 करोड़ रुपये के ऋण नहीं उठाए तथा ऋणों को निर्धारित सीमा के अंदर ही रखा। पिछली सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम दो वर्षों 2016-17 व 2017-18 के दौरान 6,751 करोड़ रुपये के शुद्ध ऋण लिए गए। जिसके विरूद्ध वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के दो वर्ष दिनांक 31.01.2020 तक के दौरान मात्र 3,669 करोड़ रुपये के शुद्ध ऋण लिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में न बोलें। माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। ...(व्यवधान) चर्चा का उत्तर दे रहे हैं।

मुख्य मंत्री : यदि वर्तमान बीते वर्ष के शेष दो महीनों अर्थात फरवरी व मार्च के दौरान उठाए गए या संभावित अधिकतम ऋण लगभग 2000 करोड़ रुपये को इसमें जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा मात्र 5,669 करोड़ रुपये बनता है जोकि पिछले दो वर्षों की तुलना में लगभग 1100 करोड़ रुपये कम है। हमारी सरकार बीते प्रबंधने के बारे में सजग है। आप फैक्ट्स को देखिए।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर बाहरी लोगों को नौकरियां देने बारे कहा गया है। इसके बारे में मैंने पहले ही कह दिया है तो मुझे लगता है कि इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर प्रश्न लगा था और मैंने इसका जवाब दे दिया है तथा आंकड़े आपके सामने हैं। हमने इस बात को सुनिश्चित किया, आप नहीं कर पाए। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है और हिमाचल के हितों की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेवारी है। हम इस जिम्मेवारी को निभाएंगे। हमने इसके लिए निर्णय लिया और कहा कि हमारी क्लास-III, क्लास-IV की जितनी भी पोस्टें हैं उसके लिए हिमाचल बोर्ड से मैट्रिक और 10+2 करना लाज़मी होगा। हां, यह भी शर्त है कि हिमाचल का जो स्थायी निवासी है उस पर यह लागू नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी रास्ता रोकने की कोशिश की गई। हम आपकी इस बात से सहमत हैं। आप हमें उधर से ज्ञान बांटतें हैं कि सब-ज्यूडिस मामला है

04-03-2020/1555/NS/YK/2

इसका ज़िक्र क्यों हो गया? इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। पटवारी वाला मामला माननीय उच्च न्यायालय में है। यह भी सब-ज्यूडिस मामला है। आप भी इसको देखिए। हम सी0बी0आई0 को पूरा सहयोग दे रहे हैं। जांच ठीक तरीके से होनी चाहिए। माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी ने कहा कि यह जो महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है इसमें सारे नियमों और व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। हमने तो रैफर किया आपने तो यहां पर भाषण दिए। बाहर के लोगों को रोज़गार देने की हमारी मंशा नहीं है। हमारी प्राथमिकता हिमाचल के लोगों को रोज़गार देने की है। लेकिन क्लास-I, क्लास-II राजपत्रित पद हैं और इनके लिए पूरा देश है। आपने अधिकारियों पर टिप्पणी की, यह उचित नहीं है।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

04.03.2020/1600/RKS/AG-1

मुख्य मंत्री... जारी

ये अपनी योग्यता की वजह से यहां बैठे हैं और हम अपनी योग्यता की वजह से यहां बैठे हैं। इसलिए इस पर नहीं बोलना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर दे रहे हैं, कृपया आप बीच में न बोलें।

मुख्य मंत्रीः आपने यहां पर पुलिस भर्ती का ज़िक्र किया। जब यह प्रक्रिया चल रही थी तो हमें रात के 9:00 बजे सूचना मिली की कुछ गड़बड़ हो रही है। हमने इस पर त्वरित कार्रवाई की और 10:30 बजे उस इंटरव्यू को रद्द कर दिया। जो लोग इसमें दोषी थे उनकी धर-पकड़ उसी रात शुरू कर दी गई। इसमें संलिप्त 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन लोगों ने हमारे कार्यकाल में गलत काम किए हैं उनकी बचने की कोई संभावना नहीं है। हम उन लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने आपके कार्यकाल में गलत काम किये हैं। अध्यक्ष महोदय, जब मेन सरगना पकड़ा गया और जब उससे पूछताछ की गई कि तुमने यह काम कब से शुरू किया है तो उसने कहा कि शायद आज हमारा बुरा

वक्त है कि हम पकड़े गये। उन्होंने यह भी बताया कि इस काम को उन्होंने वर्ष 2013, 2016 व 2017 में भी किया है। उनका यह भी कहना था कि पहले हम इस काम को बड़ी आसानी से करते थे पर आपने हमें पकड़ लिया। वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में थी। वर्ष 2013 में, वर्ष 2016 में और वर्ष 2017 में जिन लोगों के माध्यम से पुलिस कर्मी भर्ती हुए थे वे आठ लोग आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन आपसे वे लोग पकड़े नहीं गए। ...(व्यवधान) जो बातें आपने कही है हम उन बातों में नहीं जाना चाहते। हम नहीं चाहते कि आपका पर्दा उठ जाए परंतु आप स्वयं ही बेपर्दा होने के लिए आमदा है। ...(व्यवधान) आप अपने आंकड़ों का एक नोट बनाकर दीजिए क्योंकि आपका आंकड़ा कहीं मेल नहीं खाता है। हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः नियन्त्रण में है। राज्य के पुलिस बल की अपराधिक घटनाओं का पता लगाने

04.03.2020/1600/RKS/AG-2

तथा अपराधों की रोकथाम करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में अपहरण, महिलाओं से छेड़छाड़, दंगे, चोरी, सड़क दुर्घटना इत्यादि मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2018 में अपहरण आदि के 476 अभियोग दर्ज किये गये हैं, जबकि वर्ष 2019 में 497 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। वर्ष 2018 में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के 515 मामले दर्ज हुए हैं।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

04.03.2020/1605/बी.एस./ए.जी./-1

मुख्य मंत्री जारी...

जबकि वर्ष 2019 में 498 अभियोग पंजीकृत हुए। वर्ष 2018 में 469 दगों संबंधी मामलों की अपेक्षा वर्ष 2019 में 423 मामले दर्ज हुए। यानी इसमें कमी आई है। हम इस बात से संतोष नहीं कर सकते परंतु कमी आई है। मैं हत्या के मामलों की बात करूं तो वर्ष 2019 में हत्या के 70 अभियोग दर्ज हुए। विपक्ष के आंकड़े रखना बड़े मुश्किल हैं क्योंकि वे अपनी मर्जी के

आंकड़े कहते रहते हैं। एक कुछ और बोलता है दूसर कुछ और तीसरे कुछ और ही बोलते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 70 अभियोग पंजीकृत हुए जबकि वर्ष 2018 में 99 मामले पंजीकृत हुए। इसमें 79 प्रतिशत मामले सुलझाए जा चुके हैं और शेष में जांच की प्रक्रिया जारी है। पिछले 10 वर्षों में हत्या के मामलों का विवरण इस प्रकार से है। ...(व्यवधान) कृपया सुन लीजिए। आपने यह मामला उठाया था अब सुन भी लीजिए।

(कांग्रेस विधायक दल के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

मुख्य मंत्री : वर्ष 2010 में 130 वर्ष 2011 में 132 हत्या के मामले और 2012 में 112, वर्ष 2013 में 105 और वर्ष 2014 में 131, वर्ष 2017 में 106, वर्ष 2016 में 101, वर्ष 2017 में 99, वर्ष 2018 में 99 और वर्ष 2019 में 70 मामले पंजीकृत हुए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइए। ...(व्यवधान) चर्चा का उत्तर सुनिए, क्या आप मुख्य मंत्री जी बात नहीं सुनेंगे?

मुख्य मंत्री : जहां तक नैशलन हाईवे की बात आती है, मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कनैक्टिविटी हमारी प्राथमिकता है। हमारी कोशिश है कि जो नैशनल हाईवे के बारे में हमने बात कही है उस पर काम हो और काम आगे बढ़े। ऐसी परिस्थिति में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो

69 नैशनल हाईवे स्वीकृत किए गए थे। अभी हाल ही में हमारी बैठक केन्द्रीय मंत्री आदरणीय नितीन गडकरी जी के साथ हुई है उसमें उन्होंने सैद्धांतिक रूप से मान लिया है कि पहले हम 25 नैशलन हाईवे की शुरूआत करने वाले हैं। उनका कहना था कि आप प्राथमिकता तय करो।

(कांग्रेस विधायक दल के माननीय सदस्यों ने माननीय सदन से बर्हिगमन किया)

मुख्य मंत्री : बात तो सुन करके जाना चाहिए, सिर्फ बात सुना कर जाने की इनकी आदत ठीक नहीं है।

श्री डी.टी.द्वारा जारी...

04-03-2020/1610/DT/AS/1

माननीय मुख्य मंत्री .....जारी

मैं इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति बहुत भयंकर है। नेता किसी माना जाए, किसे सुना जाए यह परिस्थिति इनकी है। किसका आंकड़ा बोला जाए और किसका न बोला जाए, ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से कर रही है। आज इन्होंने बात सुने बिना वॉक आउट किया इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आने वाले समय में हमने जिसका उत्तर देना था और ये लोग उस उत्तर को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी तो हमने शुरूआत की और ये लोग शुरू में ही विचलित हो गए, सुन नहीं सकते हैं। सुन इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि ज़मीनी स्तर पर काम हुए हैं, हवा में काम नहीं हुए है। हमने शोर नहीं मचाया है। हमने लोगों के बीच में जा करके समस्याओं का समाधान करने का काम किया है और लोगों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि अगर यही हालत और परिस्थिति रही तो आने वाले समय में जब भी विधान सभा का चुनाव होगा तो ये मित्र जितनी संख्या में आए हैं उतनी संख्या में भी यहां पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे। कुछ बचेंगे और बहुत सारे यहां पर नहीं होंगे। इसकी वज़ह यह है कि इनका स्वभाव सुनने का नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने 69 नैशनल हाईवेज़ की बात कही और ये स्वीकृति सैद्धांतिक रूप से हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी लेटेस्ट बैठक हुई है उसमें यह तय हुआ है कि लगभग 25 नैशनल हाईवेज़ को सैद्धांतिक स्वीकृति देने के बाद लैंड एक्वीजिशन की प्रोसैस शुरू कर दी जाएगी। 55 की हमने डी0पी0आर0 बना करके तैयार कर दी हैं। ये तो कई सालों तक रहे एक भी डी0पी0आर0 नहीं बना सके। क्योंकि इनको लगता था कि इसका श्रेय केन्द्र सरकार की भाजपा को मिलेगा इसलिए काम न करने की कोशिश की। इसलिए आने वाले समय में प्रदेश में नेशनल हाई-वे में भी काम होगा। यह काम ज़मीन स्तर पर होगा और इस काम को हम तो देखेंगे ही प्रदेश की जनता भी देखेगी लेकिन ये लोग भी देखने के विवश होंगे। एयरपोर्ट के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि हिमाचल

प्रदेश में हमारी कनैक्टिविटी, हमारी प्रायोरिटी है। हमने प्रस्ताव दिया है कि शिमला के एयरपोर्ट में एक्सपेंशन की जितनी भी गुंजाइश है, वह करनी चाहिए। यदि इससे भी बड़ा एयरप्लेन वहां पर उत्तर जाता है तो उससे भी

04-03-2020/1610/DT/AS/2

हमें राहता हो सकती है। उसके काम में प्रोग्रैस हुई है और उसके साथ-साथ हमने कांगड़ा एयरपोर्ट के बारे में भी कहा है कि यह बड़ा एयरपोर्ट है। हिमाचल प्रदेश में यदि कहीं शीघ्र किसी एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो सकता तो कांगड़ा एयरपोर्ट है। यह बात ठीक है कि लैंड एक्विजिशन में उसमें पैसा बहुत लगेगा क्योंकि बहुत-सारे लोगों की ज़मीन और घर उसमें आएगी और लैंड एक्विजिशन में पैसा लगेगा। हमारी हार्दिक इच्छा है कि कांगड़ा की ज़मीन पर बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए और बड़ा एयरपोर्ट बनने के बाद हिमाचल पर्यटन की दृष्टि से जहां पहुंचना चाहिए, उसमें वह एयरपोर्ट योगदान दें। इससे हमें प्रसन्नता होगी और उससे भी हम आगे बढ़ेंगे। तीसरे मण्डी के एयरपोर्ट के लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि उसके लिए भी ज़मीन तलाशी है और उसके लिए ओ0एल0एस0 सर्वे हो गया है। उसके लिए जो राशि हमने केन्द्र को देनी थी, वह हमने दे दी है। उसके बाद हम ग्राउंड की एक्विजिशन की प्रोसैस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात से भी प्रसन्नता है कि 'जल से कृषि को बल' यह योजना भी हमारी आगे बढ़ी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2896 करोड़ रुपये की 327 पेयजल परियोजनाएं मंजूर हुई है और गत 3 महीनों में इस मिशन में 160 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं और 58,000 घरों को नल द्वारा शुद्ध जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जल जीवन मिशन में पूरे देशभर में हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा परफोर्म कर रहा है। इसके लिए मैं विभाग को और विभाग के मंत्री को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं। स्वरोज़गार व रोज़गार हमारी प्राथमिकता है और उस दृष्टि से भी हम लगातार काम कर रहे हैं।

एन0जी0 द्वारा .... जारी

04-03-2020/1615/ए.एस.-एन.जी./1

श्री मुख्य मंत्री जारी...

और आंकड़ों में यदि हम कहें तो इस योजना के अन्तर्गत महिला विकास निगम से रियायती दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक महिला के परिवार की आय सीमा को 50 हज़ार रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष किया गया है। वर्ष 2016-17 में 423 लाभार्थियों को, वर्ष 2017-18 में 393 लाभार्थियों को और वर्ष 2018-19 में 332 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। स्वरोज़गार की दिशा में बहुत कोशिश हुई है और हिमाचल प्रदेश में हम और भी साधन उपलब्ध करवा सकें इसके लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ए.डी.बी. के बारे में श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने कुछ बातों का जिक्र किया था। 3-4 अक्तूबर, 2019 को कोच्चि में हुई TPRM Review meeting के मिनट्स के बारे में पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में मैं इन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि वर्तमान में एशियन डैवलपमैंट बैंक की साहयता से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए चल रही परियोजना का कार्य दो चरणों में क्रियान्वित किया जाना था। प्रथम चरण के सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और यह परियोजना सितम्बर-2018 में पूर्ण हो चुकी है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत 11 कार्य किए जा रहे हैं जिनमें से 3 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, 6 कार्य मई-2020 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे और शेष 2 कार्यों को भी समयावधि में पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। इस परियोजना के पूर्ण करने की तिथि 30 जून, 2020 है।

इस परियोजना की शेष ऋण राशि 11.60 Million U.S.$ 30 जून तक व्यय करनी प्रस्तावित है जिसमें से अभी तक 1.01 Million U.S.$ की राशि व्यय कर दी गई है। यह परियोजना 3 राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब) के लिए स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना में अभी तक सभी राज्यों की उपलब्धि इस प्रकार हैः-

04-03-2020/1615/ए.एस.-एन.जी./2

राज्य का नाम	ऋण राशि	व्यय की गई राशि	उपलब्धि(%)
हिमाचल प्रदेश	38.71	27.26	70.42
उत्तराखण्ड	28.91	11.98	41.44
पंजाब	35.66	15.76	44.21

आंकडे U.S.$ Million में

इन आंकडों के हिसाब से हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। हम ए.डी.बी. को लेकर ज्यादा डीटेल में नहीं जाना चाहते क्योंकि यदि सारी डीटेल यहां पर देंगे तो उसमें बहुत सारा समय लगेगा।

हिमाचल प्रदेश में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी साफ नीति और नियत के साथ काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों का दिल छुने में कामयाब हुए हैं। हम जब भी लोगों के बीच में जाते हैं तब लोग हमें अपना सहयोग और समर्थन देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देते हैं।

एक वर्ष के कार्यकाल में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्ज़ मीट का आयोजन किया तो उस पर विपक्ष विरोध करता है क्योंकि यह हिमाचल कर रहा है। पंजाब के मुख्य मंत्री कहते हैं कि हिमाचल के मोडल को हम पंजाब में लागू करना चाहते हैं। वह अपने अधिकारियों को कहते हैं कि हिमाचल के अधिकारियों से बात करो और पूछो कि उन्होंने इतना सफल इवेंट कैसे आयोजित किया। उनके अधिकारी हमारे अधिकारियों को कहते हैं कि हमें पूरी डीटेल दीजिए कि इतना सफल इवेंट कैसे आयोजित किया। अध्यक्ष महोदय, पंजाब उत्सुक है हिमाचल प्रदेश को फोलो करने के लिए। राजस्थान के मुख्य मंत्री मिलते हैं तो वह कहते हैं कि हम भी अपने प्रदेश में ऐसा आयोजन करेंगे और उन्होंने किया भी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर भी ऐसा कार्यक्रम हुआ है। लेकिन यदि हम ऐसा आयोजन करते हैं तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश बेच दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने तो बहुत कम खर्चे में उस काम को पूरा किया और देश के प्रधान मंत्री उस इन्वेस्टर्ज़ मीट में आते हैं। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

04/03/2020/1620/MS/As/1
मुख्य मंत्री जारी--------

वहां पर वे कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश मेरा अपना घर है और वहां पर जितने भी इन्वैस्टर्ज आए थे उनसे भी उन्होंने अपील की कि आप हिमाचल प्रदेश में अपना काम और व्यवसाय कीजिए। आप हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना योगदान दीजिए क्योंकि यह मेरा अपना घर है। हम आपको अपने घर से निराश नहीं होने देंगे। यह बात प्रधान मंत्री जी कहते हैं। दो साल के कार्यकाल में देश के प्रधान मंत्री तीन बार हिमाचल प्रदेश में आते हैं। यहां शपथ ग्रहण समारोह में प्रधान मंत्री आते हैं और हमें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। जब एक साल का कार्यकाल पूरा होता है तब भी वे हमें शुभ-कामनाएं देने के लिए धर्मशाला आते हैं। ग्लोबल इन्वैस्टर मीट के कार्यक्रम में भी धर्मशाला आते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। दो साल का कार्यकाल पूरा होता है तो हमारे गृह मंत्री जी शिमला के रिज मैदान में आते हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी उनके साथ आते हैं। "गृहिणी सुविधा योजना" देने वाला हिमाचल प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य बनता है, जहां हर घर को गैस का कनैक्शन देने के लिए सैचुरेशन पर प्रदेश को पहुंचाया गया है। उससे डेढ़ महीने पहले जो हमने धर्मशाला में ग्लोबल इन्वैस्टर्ज मीट की थी, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए छोटे से कार्यकाल यानी डेढ़ महीने के कार्यकाल में ही 13,600 करोड़ रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग करने के लिए यहां पर हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री जी आते हैं और फिर भी हमारे मित्र बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। इनकी परेशानी सही है फिर ये हमें यहां कहते हैं कि हिमाचल बेच दिया। हम इन मित्रों को यह जानकारी देना चाहते हैं कि ये भी तो इन्वैस्टर्ज मीट कराने के लिए विदेशी निवेश लाने के लिए पूरे देश का भ्रमण करने के लिए निकले थे। जब भ्रमण पर निकले थे तो कहां-कहां पर घूम आए, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन यह हकीकत है कि उसमें भी करोड़ों रुपये खर्च हुए। इतने पैसे खर्च होने के बाद हम पूछना चाहते हैं कि प्रगति क्या हुई? जो विपक्ष के नेता हैं उनके विधान सभा क्षेत्र के पास साथ लगती पंडोगा में ज़मीन थी। पंडोगा के आगे भी और ज़मीन थी जो बिल्कुल समतल थी लेकिन उस वक्त मंत्रालय इनके पास था। इन्होंने कहा कि समतल ज़मीन पर नहीं बल्कि जो थोड़ा ऊपर-नीचे पहाड़ है इसको काटना है। इसको समतल

04/03/2020/1620/MS/As/2

करके यहां पर इण्डस्ट्रियल प्लॉट बनाएंगे और इसको इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप करेंगे। अध्यक्ष महोदय, उस ज़मीन को खोदने में ही 40 करोड़ रुपये खर्च कर दिए जाते हैं। हमने

ग्लोबल इन्वैस्टर्ज मीट की जिसमें 36 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा 200 से ज्यादा फॉरेन डेलीगेट्स आए। उसमें पूरे देशभर के नामी-गिरामी इन्वैस्टर्ज आए और देश के प्रधान मंत्री भी आए। हम उससे आधे पैसे से भी कम पैसे से ग्लोबल इन्वैस्टर मीट कर रहे हैं और उस पर ये ऐसी बातें कर रहे हैं। इन्होंने मिट्टी खोदने में ही 40 करोड़ रुपये मिट्टी में डाल दिए। सही मायने में ये सारे जांच के विषय हैं और इस प्रकार से इस प्रदेश की हालत की है। विजन कोई नहीं था लेकिन एक लक्ष्य था और उस लक्ष्य को हासिल करने में कुछ लोग कामयाब हुए, मैं उस बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन सब्र और संयम करें। जो हम कर रहे हैं वह पारदर्शी है और हम पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। अध्यक्ष जी, हमारा दो वर्ष का कार्यकाल बीत गया है और ये हर दिन मुद्दा उठाते हैं। उस मुद्दे को ये हाथ में पकड़ते हैं, उछालते हैं और जब वह नहीं चलता है फिर फैंक देते हैं। फिर दूसरा मुद्दा उठाते हैं, वह भी जब नहीं चलता है फिर उसको भी फैंक देते हैं कि इससे भी काम नहीं चला। फिर तीसरा मुद्दा उठाते हैं फिर वह भी नहीं चलता है। वह इसलिए क्योंकि लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, मानना तो दूर की बात है और ऐसी परिस्थिति में मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा दो साल का कार्यकाल बीत गया लेकिन हमारी सरकार के खिलाफ एक भी स्थाई मुद्दा इनके पास नहीं है जिस मुद्दे पर ये बात कर सकें। ये जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे झगड़ा करने आ रहे हैं। बात में गम्भीरता होनी चाहिए और बात अगर शालीनता के साथ कही जाए तो उसमें ज्यादा गम्भीरता होती है। लोग उस बात को सुनते हैं और सुनते ही नहीं हैं बल्कि लोग उस बात को मानते भी हैं। ज्यादा जोर से बोलने की आवश्यकता तब पड़ती है जब तथ्य नहीं होते हैं, हकीकत नहीं होती है, सचाई नहीं होती है और सत्य पर आधारित बातें नहीं होती हैं। मैं इस बात को लेकर हैरान हुआ कि इस माननीय सदन के ट्राइबल के एक सदस्य किस तरह से व्यवहार कर रहे थे और यहां आकर बाजू पीछे कर रहे थे। ये किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ तो उनको सब्र रखना चाहिए। उनके मन में न तो आसन का सम्मान है और न किसी अन्य चीज का सम्मान है। धारा-370 का हमने जिक्र किया है और यह सबसे बड़ी हकीकत है जिसको समाप्त होना था और वह समाप्त होकर रही। हमें इस बात की खुशी है कि जब देश को नरेन्द्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व मिला, तब जाकर यह दौर आया।

जारी जे0के0 द्वारा---

03.03.2020/1625/JK/DC /1

मुख्य मंत्रीः-----जारी------

ये तो बातें हमें कागज़ में सुना रहे हैं। मैं जम्मू-कश्मीर में चार साल रहा हूं। जब मैं सुबह उठता था, जहां हम रहते थे, वहां सामने सचिवालय का भवन होता था। दिल को पीड़ा होती थी जब सचिवालय की छत पर हम दो झंडे देखते थे। तिरंगें झण्डे के समान दूसरा झण्डा होता था क्योंकि जम्मू-कश्मीर में धारा-370 थी। आपका आई.पी.सी. वहां पर लागू नहीं होता था। Ranbir Penal Court (RPC) लगता था। देश की संसद द्वारा पारित 104 कानून तब तक लागू नहीं होते थे जब तक वहां धारा-370 थी। हमारा पांच साल का कार्यकाल होता था और उनकी विधान सभा का कार्यकाल छः साल का होता था। आप थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो आपके ख़िलाफ आर.टी.आई. का कागज़ लग जाता है लेकिन जम्मू-कश्मीर में आर.टी.आई. लागू नहीं होती थी। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्रप्शन से सम्बन्धित जितने भी कानून बने थे, सभी के सभी पार्लियामेंट से पारित हुए लेकिन उसके बावजूद वे वहां पर लागू नहीं होते थे। यह हकीकत है कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ था और जब गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को यह काम दिया गया कि 562 रियासतों को एक करना है, इस भारत में सभी रियासतों को मिलाना है, तो जम्मू-कश्मीर का जिम्मा नेहरू जी ने अपने ऊपर लिया था कि मैं जम्मू-कश्मीर का रहने वाला हूं और जम्मू-कश्मीर का मामला मैं खुद देख लूंगा। 562 रियासतों में से सारी की सारी रियासतें एक-एक करके आपकी जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद की रियासत, जहां पाकिस्तान को निमंत्रण दे दिया था कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं और पाकिस्तान ने आगे बढ़ने की हिम्मत की थी, रातों-रात वहां पर उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के साथ मिलने के लिए, उसको भारत का हिस्सा बनाने के लिए विवश किया लेकिन इनमें से एक रियासत जम्मू-कश्मीर नेहरू के हवाले छोड़ी थी, उसकी हकीकत आपके सामने है और आज तक उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इतिहास में जाएंगे तो बहुत बातें निकलेंगी और जो हमको इतिहास समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि वहां की क्या परिस्थिति थी? मैं चश्मदीद गवाह हूं, 1990 में मैं जम्मू-कश्मीर में होता था, 3,00,000 हिन्दू परिवार जिनके कश्मीर में कई मंजिला भवन थे, उनकी वहां पर करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी थी, करोड़ों रुपये के घर थे, उनको हमने फुटपाथ पर और तंबुओं में सोते हुए देखा है। जो लोग औरों को नौकरियां देते थे, वे भारत के कोने-

कोने में जाकर दर-दर की ठोकरें खा रहे थे। पूरे देश भर से उन लोगों के लिए जो कैम्प ऑर्गेनाइज़ किए गए थे, उनमें हमने भी काम किया था। वहां पर 10-10 हजार लोगों के लिए कैम्प लगाए गए थे और जब गाड़ियां आती थी, जो कश्मीरी पंडित बाकी लोगों को खाना खिलाते थे, उनको उस कतार में देखकर रोना आता था। कई तो अपने को पर्दे में छिपाकर कैम्प में राशन लेने के लिए विवश थे । अपने स्वतंत्र भारत में उनको ये दिन देखने पड़े इसलिए धारा-370 सबसे बड़ी बाधा थी। इसका ज़िक्र हर जगह होना चाहिए, हर बार होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, ये लोग सदन से बाहर चले गए, इनको हकीकत मालूम नहीं है। ये दूसरी दुनिया में जी रहे हैं क्योंकि इन्होंने वो हालत नहीं देखे।

अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता, मैं और भी बातों का ज़िक्र करता लेकिन जितनी बातें हमारे विपक्ष के मित्रों ने यहां पर उठाई थी, उनका जवाब देने के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने काम किया है, तुम यकीन करो या न करो लेकिन प्रदेश की जनता पर हमें भरोसा है, उसने हमारी बात पर यकीन किया है, हम पर विश्वास किया है। लोकतंत्र लोगों के सहारे चलता है, यह स्वीकार करना चाहिए। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लोक सभा के चुनाव और विधान सभा के उप-चुनाव का रिज़ल्ट आप सभी के सामने हैं। आज ये हमें यह धमकी देते हैं कि हम देखेंगे, तो ये क्या देखेंगे? लोगों ने आपको देख लिया, जहां आपको पहुंचाना था, उन्होंने पहुंचा दिया। उसके बावजूद भी हम तैयार है। हमें देखना है, तो आईए। हम सब लोग मिल कर चलेंगे। हमारा लक्ष्य हिमाचल का विकास करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो धन्यवाद प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाया गया था, जिसका माननीय सदस्य राकेश जम्वाल जी ने अनुसमर्थन किया और बलबीर सिंह जी ने उस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, उसमें बोलने वालों की जो संख्या है, उसमें मैं थोड़ी सी करैक्शन कर देता हूं। कुल 42 माननीय सदस्य इस पर बोले जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 25, कांग्रेस पार्टी के 14, सी.पी.एम. के 1 और इंडिपैंडैंट 2 हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी, सार्थक चर्चा रही। कुछेक ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं और जीवन में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहनी चाहिए, हम सीखने की भी कोशिश करते हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

04.03.2020/1630/SS-HK/1

मुख्य मंत्री क्रमागत :

और समझने की भी कोशिश करते हैं। जो बेहतर किया जा सकता है उसे करने के लिए हम आने वाले समय में खुले मन से काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाए:-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य माननीय राज्यपाल महोदय का दिनांक 25 फरवरी, 2020 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकार।

अब इस मान्य सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 5 फरवरी, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है। सभी का धन्यवाद।

शिमला-171 004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 4 मार्च, 2020 **सचिव ।**